

CURRENT AFFAIRS



INDEX

		पेज नं.
1	राजस्थान परिदृश्य	1 – 18
2	राष्ट्रीय परिदृश्य	19 – 22
3	आर्थिक परिदृश्य	23 – 25
4	अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य	26 – 31
5	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	32 – 38
6	खेल	39 – 43
7	पुरस्कार एवं सम्मान	44 – 46
8	चर्चित व्यक्तित्व	47 – 50
9	चर्चित स्थल	51 – 52
10	महत्त्वपूर्ण तथ्य	53 – 55
11	रिपोर्ट्स एवं इंडेक्स	56 – 57
12	प्रमुख दिवस एवं सप्ताह	58 – 61
13	सार : योजना - कुरुक्षेत्र	62 – 72
14	आलेख	73 – 78
15	टर्म इन न्यूज	79 – 83
	मॉडल प्रश्न	84 – 88

मासिक करेंट अफेयर्स

मई : 2024



Near Riddhi-Siddhi Circle, Gopalpura Bypass, Jaipur

1

राजस्थान परिदृश्य

राजस्थान में लोकसभा चुनाव

- चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च को, 2024 के आम चुनावों के साथ-साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई।
- देश में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में हुए, जबकि मतगणना 4 जून को की गई।
- इसके अलावा, चुनाव आयोग द्वारा सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की भी घोषणा की गई।
- वर्तमान 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है।
- देश में 543 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
- राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों हेतु दो चरणों में क्रमशः 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को चुनाव हुए।
- पहले चरण में राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, जबकि दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए।
- राजस्थान में पहले चरण में कुल मतदान 57.65% रहा, जबकि दूसरे चरण में कुल मतदान 65.03% रहा।

राजस्थान में मतदान प्रतिशत	
कुल	61.53%
पुरुष	62.27%
महिला	60.72%
अन्य	53.03%

राजस्थान में मतदान प्रतिशत		
	सर्वाधिक	न्यूनतम
जिला	बाड़मेर (75.93%)	करौली-धौलपुर (49.59%)
पुरुष	बाड़मेर (76.54%)	करौली-धौलपुर (51.25%)
महिला	बाँसवाड़ा (75.75%)	करौली-धौलपुर (47.66%)
अन्य	जयपुर ग्रामीण (87.50%)	बाड़मेर (22.22%)
18-19 वर्ष का वर्ग	बाँसवाड़ा (77.93%)	करौली-धौलपुर (47.44%)
दिव्यांग	बाँसवाड़ा (84.93%)	भरतपुर (44.37%)

- राजस्थान में दिव्यांग मतदाताओं का कुल मतदान प्रतिशत 68.63% रहा।
- राजस्थान में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 57.8% रहा तथा राज्य में घर से मतदान करने (Vote from Home) वालों का मतदान प्रतिशत 98.30% रहा।
- राजस्थान में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला गाँव बूँदी जिले का भगवानपुरा गाँव रहा, जहाँ 92.46% वोटिंग हुई।
- भगवानपुरा गाँव ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भी 97.04% वोटिंग के साथ पहले स्थान पर रहा था।
- नोट: राजस्थान में वर्ष 2019 में हुए 17वीं लोकसभा के चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 66.34% रहा था।

राजस्थान में लोकसभा के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य :-

- राजस्थान में वर्तमान में लोकसभा की 25 तथा राज्यसभा की 10 सीटें हैं। इस प्रकार राजस्थान से कुल 35 सांसद निर्वाचित होते हैं।
- राजस्थान में लोक सभा हेतु 4 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए तथा 3 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए आरक्षित
1. भरतपुर	1. बाँसवाड़ा
2. बीकानेर	2. दौसा
3. श्रीगंगानगर	3. उदयपुर
4. करौली-धौलपुर	

- राजस्थान से अब तक दो व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष बने हैं-
 1. बलराम जाखड़ (सीकर)
 2. ओम बिड़ला (कोटा)
- बलराम जाखड़ का लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल सर्वाधिक रहा है।

राजस्थान विधानसभा में 15 समितियों का गठन

- राजस्थान विधानसभा की 15 समितियों का गठन 17 मई 2024 को किया गया।
- इन समितियों की संरचना में परिवर्तन किया गया है इसके तहत कई समितियों की सदस्य संख्या में कटौती की गई।

- वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में कुल 21 में से 19 समितियों का गठन किया जा चुका है।
- विधानसभा अध्यक्ष ने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 183 (1) के तहत इन समितियों का गठन किया है।
- विधानसभा की दो समितियों का सभापति महिला विधायकों को बनाया गया है।

समिति	सभापति के नाम
नियम समिति	वासुदेव देवनानी
सदाचार समिति	हरीश चौधरी
स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं संबंधी समिति	हरि सिंह रावत
विशेषाधिकार समिति	पुष्पेंद्र सिंह
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनिता भदेल
याचिका समिति	हमीरसिंह भायल
सरकारी आशवासनों संबंधी समिति	जितेन्द्र कुमार गोठवाल
प्रश्न एवं संदर्भ समिति	संदीप शर्मा
पर्यावरण संबंधी समिति	डॉ. दयाराम परमार
पुस्तकालय समिति	सुरेन्द्र सिंह राठौड़
महिलाओं एवं बाल कल्याण संबंधी समिति	शोभा चौहान
पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति	केशाराम चौधरी
अनुसूचित जाति कल्याण समिति	डॉ. विश्वनाथ मेघवाल
अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति	फूलसिंह मीणा
अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति	पब्बाराम विशनोई

- राजस्थान विधानसभा में 4 अन्य समितियों का गठन 17 अप्रैल 2024 को किया गया था, जो निम्नलिखित हैं:
 - जनलेखा समिति : टीकाराम जूली (विपक्ष के नेता)
 - प्राक्कलन समिति 'क' : अर्जुन लाल नागर
 - प्राक्कलन समिति 'ख' : श्रीचन्द कृपलानी
 - राजकीय उपक्रम समिति : कालीचरण सर्राफ

राजस्थान विधानसभा

- विधानसभा: 16वीं
- सदस्य संख्या: 200
- विधानसभा अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी
- सदन का नेता: श्री भजनलाल शर्मा
- विपक्ष का नेता: श्री टीकाराम जूली

राजनीतिक दल	सीटें
भारतीय जनता पार्टी	115
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	69
भारतीय आदिवासी पार्टी	4
बहुजन समाज पार्टी	2
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	1
राष्ट्रीय लोक दल	1
निर्दलीय	8
कुल	200

- राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जाति (SC) और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं अर्थात् राजस्थान की कुल विधानसभा सीटों में से 59 सीटें आरक्षित रखी गई हैं।
- राजस्थान के 16वें विधानसभा चुनाव (2023) में कुल 20 महिला विधायक निर्वाचित हुईं। (इसमें 9 भाजपा, 9 कांग्रेस और 2 निर्दलीय हैं।) अर्थात् कुल विधानसभा सीटों में से महिला विधायकों की भागीदारी 10% है।

राजस्थान हाई कोर्ट ने हीटवेव से मौत होने पर आश्रितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया

- राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में राज्य सहित पूरे देशभर में चल रही हीटवेव पर चिंता जताते हुए केंद्र व राज्य सरकार से इसके प्रतिकूल प्रभावों से बचने के उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
- जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने हीटवेव पर स्वतः संज्ञान लेकर निर्देश दिए।
- हाई कोर्ट ने केंद्र व राजस्थान सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन परियोजना के तहत बनाए गए हीट एक्शन प्लान को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया।
- हाई कोर्ट ने हीटवेव और कोल्डवेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और राजस्थान सरकार को हीटवेव से हुई मौत के मामलों में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
- वर्तमान में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हीटवेव से मौत पर मुआवजे का प्रावधान नहीं है।
- हाई कोर्ट ने 18 दिसंबर 2015 को राज्यसभा में पेश लू और शीतलहर के कारण मृत्यु रोकने वाले विधेयक को लागू करने का निर्देश दिया।
- राजस्थान के मुख्य सचिव, गृह व स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए कि वे हर विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) या प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समिति बनाएँ और ये हीट एक्शन प्लान व गर्मी से जुड़ी बीमारियों से बचाने के लिए कदम उठाएँ।

- राजस्थान में प्रचंड गर्मी के कारण 67 लोगों की मौत (31 मई तक) हुई है।
- **नोट:** केंद्र व राज्य सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदाओं में किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर उसके परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। वहीं दिव्यांग होने पर 74 हजार से 2.5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।

केंद्र एवं राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम

- राजस्थान सरकार द्वारा 'राजस्थान में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005' को 1 अगस्त 2007 को लागू किया गया था।
- इसमें केंद्र सरकार द्वारा घोषित 10 व राज्य सरकार द्वारा घोषित केवल 2 आपदाओं को ही शामिल किया गया है।
- हीटवेव यानी लू को अभी तक प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है।
- हालांकि केंद्र सरकार द्वारा घोषित आपदाओं में शामिल नहीं होने पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी आपदा घोषित कर सहायता दे सकती हैं।
- **नोट:** केंद्र सरकार ने कोविड-19 को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था।
- देश में आपदाओं के नियंत्रण और मुआवजे के प्रावधान के लिए देश में 'आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005' लाया गया था, जिसके तहत आपदा राहत कोष में केंद्र 75% व राज्य 25% मदद करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली में नए खनन पट्टे जारी करने पर रोक लगाई

- सर्वोच्च न्यायालय ने चार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली (Aravalli) में नए खनन पट्टे देने और नवीनीकरण करने से रोक दिया है।
- ये आदेश दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के लिए लागू किए गए हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उसके आदेश वैध परमिट और लाइसेंस के तहत कानूनी खनन गतिविधियों पर लागू नहीं होता।
- सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

मामला

- सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन को लेकर भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार को इसे रोकने को कहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की 2018 में दी अवैध खनन रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिए।

- FSI ने रिपोर्ट में बताया था कि हरियाणा से राजस्थान होते हुए गुजरात तक अरावली पर्वत श्रृंखला में 3 हजार स्थलों पर खनन हुआ है। 31 पहाड़ियां खत्म हो गई हैं।

अरावली पर्वत श्रृंखला

- भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है।
- अरावली रेंज पृथ्वी पर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है।
- राजस्थान में गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊँचा बिंदु है, जिसकी ऊँचाई 1,722 मीटर है।
- विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के नाम पर इस शिखर का नाम 'गुरु शिखर' रखा गया है।

अरावली का महत्त्व

- अरावली मरुस्थलीकरण के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा के रूप में काम करती है।
- अरावली अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाली शुष्क हवाओं को गंगा के मैदानी इलाकों में आने से रोकती है।
- जलवायु को नियंत्रित रखने में भूमिका निभाती है।
- साबरमती, लूनी और बनास सहित कई नदियों के लिए जलक्षेत्र के रूप में कार्य करती है।
- यह नदियों का उद्गम स्थल भी है।
- यह एक महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है।
- कुंभलगढ़ किला, दिलवाड़ा मंदिर और रणकपुर जैन मंदिर जैसे प्रसिद्ध स्थल समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण हैं।

राजस्थान में बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी सरपंच की होगी: उच्च न्यायालय

- राजस्थान में बाल विवाह को रोकने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक आदेश पारित कर राज्य सरकार को राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है।
- उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से गांव-कस्बे के वार्ड स्तर तक के जनप्रतिनिधियों को जागरूक कर बाल विवाह रोकने में उनका साथ लेने का निर्देश दिया है।
- उच्च न्यायालय ने कहा कि बाल विवाह होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार माना जाएगा।
- न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस एवं बचपन बचाओ आंदोलन की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया।
- न्यायालय ने कहा कि पंचायती राज नियम के तहत बाल विवाह रोकना सरपंच का कर्तव्य है।

राजस्थान विधानसभा दिसंबर 2024 तक पेपरलेस होगी

- राजस्थान विधानसभा को दिसंबर 2024 तक नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन के तहत पूर्ण रूप से कम्प्यूटराईजेशन किया जाएगा।
- इस पूर्ण कम्प्यूटराईजेशन के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, राजस्थान सरकार तथा राजस्थान विधानसभा सचिवालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया गया है।
- इसके तहत विधायकों की टेबल पर कंप्यूटर स्क्रीन लगेंगे तथा प्रश्नकाल व शून्यकाल सहित सारी कार्रवाई ऑनलाइन होगी।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA)

- यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है।
- इसका उद्देश्य सभी राज्य विधानसभाओं को पूर्ण रूप से डिजिटल रूप में बदलकर पेपरलेस बनाना है।
- NeVA में एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप शामिल है।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में NeVA के कार्यान्वयन के लिये केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय, 'नोडल मंत्रालय' है।

डॉ. कमला बेनीवाल

- डॉ. कमला बेनीवाल का 15 मई 2024 को निधन हो गया।
- यह 1952 में राजस्थान की दूसरी महिला विधायक (आमेर से) बनीं।
- यह राजस्थान की पहली महिला मंत्री (27 वर्ष की आयु में) और पहली महिला उपमुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं।
- डॉ. बेनीवाल राजस्थान आमेर और बैराठ (वर्तमान विराट नगर) से कुल 7 बार विधायक रहीं।
- यह 3 राज्यों – गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यपाल भी रह चुकी हैं।
- इनका जन्म 12 जनवरी 1927 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के गौरीर गाँव में हुआ था।

राजस्थान में प्रथम महिला

- पहली महिला मुख्यमंत्री: वसुंधरा राजे
- पहली महिला राज्यपाल: प्रतिभा देवीसिंह पाटिल
- पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष: सुमित्रा सिंह
- पहली महिला विधायक: यशोदा देवी
- पहली महिला लोकसभा सदस्य: महारानी गायत्री देवी
- पहली महिला राज्यसभा सदस्य: शारदा भार्गव

राजस्थान में जवाबदेही कानून की स्थिति

- राजस्थान में लंबे समय से जवाबदेही कानून हेतु आंदोलन चलाया जा रहा है।
- जवाबदेही कानून लाने के लिए राज्य सरकार ने 2019-20 के बजट में भी घोषणा की।
- राजस्थान में वर्ष 2019 में राज्य सरकार द्वारा जवाबदेही विधेयक के प्रारूप हेतु **पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त, रामलुभाया की अध्यक्षता** में एक समिति का गठन किया गया।
- इस समिति द्वारा वर्ष 2020 में अपनी रिपोर्ट एवं कानून का प्रारूप पेश किया गया था।
- नोट:** राजस्थान लोक सेवा प्रदायगी गारंटी अधिनियम (Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Service Act), 2011 तथा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम (Rajasthan Right to Hearing Act), 2012 पहले ही लागू हो चुके हैं।
- इसके तहत राजस्थान में नागरिक सेवाओं से संबंधित काम नहीं करने पर अफसरों और कर्मचारियों को जवाबदेह ठहराए जाने का प्रावधान किया है।
- राज्य में इस हेतु ' राजस्थान लोक सेवा प्रदायगी गारंटी और जवाबदेही विधेयक-2022' के नाम से प्रारूप तैयार किया गया है।
- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम (Rajasthan Guaranteed Delivery of Public Service Act), 2011 में जनता का काम नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं था।
- इस कानून हेतु प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय और उनके सहयोगी कार्यकर्ता निखिल डे द्वारा नागरिकों को जागरूक करने हेतु आंदोलन किया जा रहा है।
- अरुणा राय के प्रयासों से ही देश में सबसे पहले सूचना का अधिकार कानून राजस्थान में बना था।
- इस जवाबदेही कानून को सूचना के अधिकार कानून का अगला महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।

प्रारूप में प्रावधान

- सरकारी विभागों में प्रत्येक काम को अधिकतम 30 दिनों में ही करना होगा।
- सरकारी विभागों को हर काम के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा पूछने पर यह बताना होगा उसका काम कौन सा अधिकारी-कर्मचारी करेगा।
- संबंधित काम को करने या ना करने के लिए एक सरकारी कार्मिक की जिम्मेदारी व जवाबदेही तय रहेगी।
- नियमानुसार व समयबद्ध तरीके से हो सकने वाले काम को तय समय सीमा में ना करने पर संबंधित जवाबदेह कार्मिक पर आर्थिक, प्रशासनिक और वैधानिक कार्रवाई होगी।

- लगातार 3 बार जवाबदेही का उल्लंघन करने वाले कार्मिक की सरकारी नौकरी पूर्णतः खत्म करने की कार्रवाई होगी।

चुनौतियाँ

- सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों का मत है कि यह कानून उनके लिए बेहद सख्त होगा और सरकारी नौकरी करना बहुत कठिन हो जाएगा।
- इस कानून की प्रभावशीलता पर संदेह है। सूचना के अधिकार कानून के तहत भी सरकारी विभाग आम तौर पर सूचना मांगने वाले को यह बता कर निजात पा लेते हैं कि सूचना 30 दिनों के भीतर देनी है।
- राज्य सरकार में इच्छाशक्ति का अभाव है। इसके अलावा सरकार को कर्मचारियों और नौकरशाही की नाराजगी का भी खतरा है।

समाधान

- **नौकरशाहों और कर्मचारी संगठनों का पक्ष भी जानना:** राज्य सरकार को विभिन्न सरकारी कार्मिकों के संगठन और अधिकारियों से वार्ता कर उनका पक्ष जानना चाहिए। उनकी शंकाओं का निवारण भी किया जाना चाहिए
- **विधिक राय:** प्रशासनिक सुधार विभाग को विधि विभाग और स्वतंत्र विधि विशेषज्ञों की राय के लिए तुरंत इस कानून के मसौदे को जारी करना चाहिए, ताकि वे अपनी राय दे सकें।
- **नागरिकों के सुझाव भी शामिल हो:** राज्य सरकार को इस कानून के संदर्भ में नागरिकों की राय भी जाननी चाहिए।
- **कानून हेतु विशेष टास्क टीम का गठन हो:** इस कानून के लिए विभाग के संसाधन सीमित है। ऐसे में सरकार वित्त, विधि, संसदीय मामलात, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अफसरों-कार्मिकों की एक विशेष टास्क टीम भी गठित कर सकती है।

राजस्थान में अन्य कानूनों की स्थिति

- राजस्थान में जनसुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 से लागू है जिससे आम जनता को उसके निवास स्थान के नजदीक सुनवाई का अवसर प्रदान करने का प्रावधान है।
- इसके तहत जन शिकायत या परिवाद पर 15 दिवस में सुनवाई की अनिवार्यता है, साथ ही शिकायत/परिवाद पर लिये गये निर्णय की सूचना 7 दिवस में देने की अनिवार्यता भी सुनिश्चित की गई है।
- इसमें अधिकारियों/कर्मचारियों के दोषी पाए जाने पर 500 से 5,000 रुपये तक दंड का प्रावधान भी रखा गया है लेकिन यह वास्तव में धरातलीय स्तर पर उतना प्रभावी नहीं है।

राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य में कछुओं के संरक्षण के लिए हैचरी का निर्माण होगा

- सवाईमाधोपुर. वन विभाग की ओर से पालीघाट और उसके आसपास चम्बल नदी में अब घड़ियालों की तर्ज पर कछुओं के संरक्षण को लेकर कार्य किया जाएगा।
- राजस्थान वन विभाग ने नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी में चार जगहों पर अंतस्थलीय हैचरियाँ बनाई हैं।
- राजस्थान में पहली बार कछुओं के संरक्षण के लिए हैचरी का निर्माण किया जाएगा।
- एक हैचरी मंडरायल रेंज के गुमश घाट और तीन हैचरियाँ राजघाट, शंकरपुर और अंडवापुरैनी घाट पर बनाई गई हैं।
- वन विभाग द्वारा अगले चरण में पालीघाट पर भी कछुए की हैचरी तैयार की जाएगी।
- राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में कछुओं की 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से 4 प्रजातियाँ नरम कवच वाले कछुओं और 5 कठोर कवच वाले कछुओं की हैं।
- इनमें से स्थानीय चंबल नदी में 6 प्रकार की प्रजाति ही पाई जाती है।
- **बटागुर और बटागुर डोंगोका प्रजाति क्रमशः** अति संकटग्रस्त और संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं।

राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य

- राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य सवाई माधोपुर के पालीघाट गाँव में स्थित है, जो चम्बल नदी के तट से सटा हुआ है।
- राजस्थान में चम्बल नदी की दुर्लभ मगरमच्छ प्रजाति के संरक्षण हेतु सरकार ने 7 दिसम्बर, 1979 को राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य का राजपत्रीकरण किया।
- इन दुर्लभ मगरमच्छ प्रजातियों को घड़ियाल के नाम से जाना जाता है।
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का क्षेत्र लगभग 425 वर्ग किमी है।
- यह नदी अभयारण्य राजस्थान के कोटा बैराज से शुरू होता है।
- चम्बल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी भाग में बहती है और इसका मार्ग सवाई माधोपुर से होकर गुजरता है।
- अगले भाग में, चंबल घड़ियाल मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के धौलपुर को कवर करता है।
- राजस्थान में कुल अभयारण्य क्षेत्र लगभग 285 वर्ग किमी है।
- यह एक नदी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था।
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र **तीन राज्यों में विस्तृत** है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

'अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम'

- यह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग की मोबाइल एप आधारित प्रणाली है।
- इसका उद्देश्य कार्मिकों हेतु समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए इसे 'राज SSO AMS' प्रणाली के माध्यम से शुरू किया गया है।
- यह एप सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा विकसित किया गया है।
- इसके तहत विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों की उपस्थिति को डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जा सकेगा।
- इसमें जियो फेंसिंग तकनीकी के माध्यम से कार्यालय और कार्य स्थल परिसर के दायरे में मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का प्रावधान किया गया है।
- इसके संचालन हेतु जिला स्तरीय कार्यालयों की SSO आईडी को अक्षांश एवं देशांतर के साथ मैप किया गया है।
- जिओ फेंस तकनीक में ऑफिस की जीपीएस लोकेशन पर ही 'मार्क इन' किया जा सकता है।

राजस्थान में 4 और डेल्टिक क्लब बनेंगे

- इस संदर्भ में डेल्टिक काउन्सिल ऑफ राजस्थान और 4 विद्यालयों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
- इस हेतु डेल्टिक काउन्सिल ऑफ राजस्थान की तरफ से काउन्सिल के महासचिव श्री जितेन्द्र कुमार सोनी (IAS) ने द पैलेस स्कूल जयपुर, गवर्नमेन्ट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल किशनगढ़, दिल्ली पब्लिक स्कूल और विद्याश्रम स्कूल ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
- इसका उद्देश्य 6 डेल्टिक कलाओं (शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, समकालीन नृत्य, फोटोग्राफी) के प्रति युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है।
- इससे प्रदेश में डेल्टिक आंदोलन को गति मिलेगी छात्रों को कला-संस्कृति के प्रदर्शन के लिए एक मंच मिल सकेगा।
- डेल्टिक काउन्सिल ऑफ राजस्थान, भारतीय डेल्टिक काउन्सिल और इंटरनेशनल डेल्टिक काउन्सिल का ही एक भाग है।
- डेल्टिक काउन्सिल द्वारा इन विद्यालयों के साथ वार्षिक कैलेंडर तैयार कर डेल्टिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा।

'शुद्ध आहार - मिलावट पर वार' अभियान

- यह अभियान राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुरू किया गया।

- इसका उद्देश्य आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा मिलावटी खाद्य सामग्री के प्रति जागरूक करना है।
- इस अभियान के तहत जिले में मिलावटखोरों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के तहत नियमित रूप से कार्रवाई किए जाने के साथ ही विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी।
- इसमें मिलावटी तेल, घी, दूध मसाले मिलावटी खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों एवं अन्य मिलावटी खाद्य पदार्थों जैसे आटा, बेसन इत्यादि की बिक्री पर रोकथाम के लिए पुलिस विभाग के साथ विशेष अभियान संचालित कर कार्रवाई की गई।
- इस अभियान के तहत मिलावट प्रमाणित होने पर सूचना देने वाले को 51,000 रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई है।

द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 13वाँ संस्करण

- उद्देश्य: राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना।
- आयोजन: जयपुर में 5 से 7 मई 2024 को।
- आयोजक: पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और फिक्की
- 'वेड इन इंडिया एक्सपो' का आयोजन 5 मई 2024 को महारानी महल रामबाग पैलेस, जयपुर में किया गया।
- इस एक्सपो का उद्देश्य राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ वैडिंग डेस्टिनेशन बनाना है।
- इसमें 6 व 7 मई 2024 को जयपुर के सीतापुरा में एग्जीबीशन का आयोजन किया गया।
- इसमें विदेशी टूर ऑपरेटर्स के साथ राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बी टू बी मीटिंग आयोजित की गई।
- राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का पहली बार आयोजन वर्ष 2008 में किया गया।

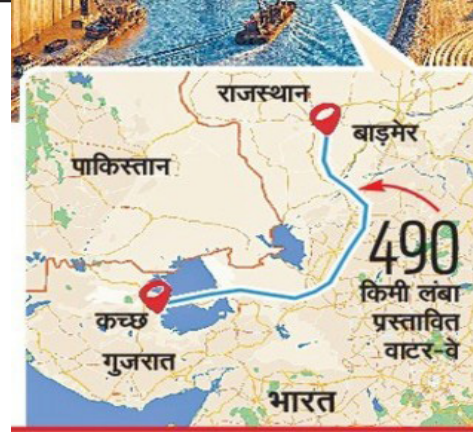
राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थलों को धरोहर स्थल घोषित किया जाएगा

- अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्रांतिकारियों के योगदान को रेखांकित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा प्रमुख स्थलों के धरोहर स्थल घोषित किया जाएगा।
- राजस्थान सरकार इस हेतु आर्कलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ब्रिटिश दस्तावेजों की सहायता लेगी।
- इसके तहत अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाली शख्सियतों की मूर्तियाँ लगाई जाएगी और उनसे जुड़े स्थलों को ऐतिहासिक धरोहर स्थल किया जाएगा।
- इनमें पाली, मारवाड़ जंक्शन के निकट **आऊवा गाँव** में अंग्रेजों के खिलाफ हुए सबसे बड़े विद्रोह को रेखांकित किया जाएगा।

एरिनपुरा विद्रोह में आऊवा की भूमिका

- 1857 में एरिनपुरा में सैन्य विद्रोह हुआ। आऊवा ठाकुर कुशालसिंह ने बागी सैनिकों को शरण दी।
- एरिनपुरा विद्रोह में आऊवा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के 6000 सैनिक मिल गए थे जिस कारण विद्रोहियों की संख्या अधिक हो गई तथा इस विद्रोह का दबाने हेतु जोधपुर के सेनापति कुशल राज तथा अंग्रेज अधिकारी हीथकोट के नेतृत्व में सेना भेजी गई।
- **8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा (पाली) का युद्ध** हुआ जिसमें ओनार सिंह मारा गया तथा कुशल सिंह विजयी हुआ।
- इसके पश्चात लॉरेंस मात्र एक बार युद्ध करने अजमेर की सीमाओं के बाहर आया तथा **18 सितंबर 1857 को चेलावास (पाली) का युद्ध** लड़ा गया इसमें भी कुशल सिंह विजय हुआ।
- इस युद्ध को **“गोरे तथा कालों का युद्ध”** कहा जाता है।
- इस युद्ध में भाग लेने के लिए **जोधपुर के पोलिटिकल एजेंट मोक मेसन** भी आया था परंतु दिशा भ्रम हो जाने के कारण उनका ऊँट विद्रोहियों के शिविर में ही चला गया जहाँ उसकी हत्या करके शव को आऊवा दुर्ग के बाहर टांग दिया गया।
- आऊवा में मोक मेसन की समाधि स्थित है जिसे ऊँट की समाधि भी कहा जाता है तथा ऊँटों की पालक जाति रेबारी इस समाधि पर मन्त मांगती है।
- होम्स ने 20 जनवरी 1858 को आऊवा पर अधि कार कर लिया।
- अजमेर लौटते समय आऊवा के चंपावत ठाकुरों की कुलदेवी सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले गया जो वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में है।
- **सुगाली माता** को राजस्थान में **1857 क्रांति की देवी** कहा गया है।

बाड़मेर से कच्छ तक वाटर-वे बनेगा



- राजस्थान के बाड़मेर से गुजरात में कच्छ तक वाटर-वे बनेगा।
- इस हेतु राजस्थान सरकार ने नदी परिवहन की राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
- इस समिति का अध्यक्ष जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार को बनाया गया है।
- इस वाटर-वे की लंबाई लगभग **490 किमी.** और चौड़ाई लगभग 100 मीटर रहेगी।
- इसकी गहराई लगभग 4 मीटर तक होगी तथा 3,000 टन क्षमता के कार्गो शिप (Vessels) चल सकेंगे।
- इससे अंतरराज्यीय व्यापार में आवागमन सड़क मार्ग की अपेक्षा सस्ता होगा तथा पर्यटन के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

बहज गाँव (डीग): 2,500 वर्ष पुराना यज्ञ कुंड, अश्विनी कुमारों की प्रतिमा और अस्थियों से निर्मित औजार के अवशेष मिले

- राजस्थान के डीग के बहज गाँव में टीले की खुदाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 2,500 वर्ष पुराना यज्ञ कुंड, धातु के औजार, सिक्कों के साथ मौर्य कालीन मातृदेवी का सिर मिला है।
- इसके अलावा शृंग कालीन अश्विनी कुमारों की मूर्ति फलक और अस्थियों से निर्मित उपकरण एवं महाभारत कालीन माने जाने वाले मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं।
- खुदाई के दौरान प्राचीन काल की अस्थियों से निर्मित उपकरण तथा मौर्य काल की प्राचीन पकी मिट्टी की बनी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं।
- अश्विनी कुमारों की एक युगल मूर्ति प्राप्त हुई है जो शृंग काल की है। अश्विनी कुमारों का नाम महाभारत में दस्र और नासत्य था।
- भारत में पहली बार बहज गाँव में 200 ई.पू. के अश्विनी कुमारों के प्रमाण मिले हैं।
- पुरातत्व विभाग ने बहज गाँव का प्राचीन नाम बज नगर होने की भी संभावना व्यक्त की है।
- ब्रज क्षेत्र में 50 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद बड़े स्तर पर खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया है।

राजस्थान का सबसे लंबा रोप-वे

- राजस्थान का सबसे लंबा रोप-वे **जयपुर में** स्थापित किया जाएगा।
- यह आमेर महल से जयगढ़ और नाहरगढ़ को जोड़ेगा।
- इन तीनों पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले इस रोप-वे की लंबाई 6.5 किमी. प्रस्तावित है।
- ये शहर के एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देगा, साथ ही पर्यटक चंद घंटों में तीन बड़े स्मारक देख पाएंगे।
- इस रोप-वे के 4 स्टेशन बनेंगे। पहला स्टेशन आमेर मावठे के पिछले हिस्से में बनेगा।
- आमेर मावठे से सीधे पर्यटकों को आमेर महल के पीछे माधोसिंह की ठान (दूसरा स्टेशन) तक ले जाया जा सकेगा।
- तीसरा स्टेशन जयगढ़ के एंट्री गेट के पास बनाया जाएगा, जबकि चौथा स्टेशन नाहरगढ़ पर बनेगा।
- इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार से भी मंजूरी मिल चुकी है।



इन्टीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0

- राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण और चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह ऑनलाइन करने के लिए इन्टीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लागू किया जाएगा।
- यह आमजन को सुगमतापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक महत्वाकांक्षी एवं दूरदर्शी प्रोजेक्ट है।
- यह एक अत्याधुनिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिससे प्रदेश के चिकित्सा तंत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा।
- इस सिस्टम के तहत इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, डिजी हेल्थ लॉकर, मरीजों को कतारों से मुक्ति, यूनीफाइड डिजिटल सर्वे, केपीआई आधारित डैशबोर्ड, स्वास्थ्य संबंधी लाइसेंस एवं एनओसी आदि के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, टेली आईसीयू, जीओ टैगिंग आधारित चिकित्सालय का मैप जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

- इससे ज्यादातर स्वास्थ्य सेवाएँ ऑनलाइन होंगी और मरीजों को उपचार लेने में आसानी होगी।
- इससे दवाओं के उपभोग एवं उपलब्धता की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी।

जयपुर के चाकसू में सीए प्रोफेशनल व स्टूडेंट्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा

- सीए प्रोफेशनल्स और सीए स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) देश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाई जाएगी।
- देश में 500 करोड़ की लागत से 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इनमें से 2 जयपुर के चाकसू और हैदराबाद में एक-एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन चुके हैं और 9 बनाए जाने हैं।
- इसके दूसरे चरण में चाकसू में इंक्यूबेशन सेंटर बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

- इसमें रेजिडेंशियल फ़ैसिलिटी सहित रिसर्च एसोसिएट प्रोफेसर, फाइनेंस स्टाफ सहित करीब 15 लोगों का स्टाफ होगा।
- स्टूडेंट्स के आइडियाज को सपोर्ट करने और बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए इंक्यूबेशन में कई तरह की लैब होंगी।
- जैसे: रिसर्च, टीचिंग और लर्निंग, डिजिटल लाइब्रेरी, कम्प्यूनिटी, इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी और वर्चुअल लैब जैसी कई सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी।

RSGL की ग्रीन एनर्जी- क्लीन एनर्जी सुविधा

- राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (RSGL) द्वारा कोटा में 25,000 से अधिक नागरिकों तक ग्रीन एनर्जी- क्लीन एनर्जी सुविधा से जोड़ा गया है।
- इसके अलावा जयपुर के कूकस व नीमराना में CNG व कोटा में CNG व PNG सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ ही सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।
- RSGL द्वारा कोटा में 5,064 परिवारों को डोमेस्टिक पाइपड नेचुरल गैस (DPNG) सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- RSGL द्वारा 10 सीएनजी स्टेशनों का संचालन करते हुए वाहनों को ग्रीन एनर्जी उपलब्ध कराई जा रही है।

ओडीके एप से मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग होगी

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण नवाचार किया है।
- इसके तहत अब मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग ओडीके एप से की जाएगी।
- इससे राज्य में मौसमी बीमारियों के बचाव एवं रोकथाम के लिए त्वरित रूप से कारगर कदम उठाए जा सकेंगे।
- इस एप का मुख्य उद्देश्य मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया के केसों में कमी लाना है।

'हरि वन वृक्षारोपण अभियान'

- राजस्थान में यह अभियान राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा।
- यह महत्वपूर्ण अभियान 1 से 31 जुलाई तक संचालित किया जाएगा।
- इसके तहत प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली में वृद्धि हेतु 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
- इसका उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों में बेहतर वातावरण, हरियाली, छाया एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है।
- इसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं इससे निचले स्तर के चिकित्सा संस्थानों में 5 तथा इससे उच्चतर चिकित्सा संस्थानों में 10 पौधे लगाए जाएंगे।

- पौधरोपण के बाद 5 वर्ष तक रख- रखाव, पानी एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की ही होगी।
- इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए 11 चिकित्सा संस्थानों के हरि वन मित्र को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला

- आयोजन: 19 से 28 मई, 2024 तक जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।
- संस्था: सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के संयुक्त तत्वावधान में।
- सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जो कई वर्षों से सहकार मसाला मेले का आयोजन करते हुए जयपुरवासियों को शुद्ध मसाले उपलब्ध कराने की पहल करता आ रहा है।

राजस्थान में आत्महत्या रोकने हेतु कोटा पुलिस का मेटा से समझौता

- कोटा में विद्यार्थियों की आत्महत्या रोकने हेतु कोटा पुलिस ने मेटा कंपनी ('मैटास्किमा टैगिंग और एस्केमा से') समझौता किया है।
- कोटा पुलिस का यह मॉडल राजस्थान पुलिस महानिदेशक (DGP) उत्कल रंजन साहू ने पूरे राज्य में लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।
- इस मॉडल को कोटा पुलिस पूरे राजस्थान में संचालित कर रही है।
- इसके तहत अब कोई भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तनाव, सुसाइड की मंशा व्यक्त करने वाले और स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो जैसी कुछ भी पोस्ट डालता है तो मेटा इसे तुरंत अपने एल्गोरिदम (सिस्टम) में फ्लैग (चिह्नित) कर देगा और इसकी जानकारी तुरंत कोटा पुलिस से शेयर करेगी।
- इस जानकारी में पोस्ट की गई सामग्री और व्यक्ति का टेक्निकल विवरण होगा।
- संबंधित जिले की पुलिस टीम ऑन ग्राउंड जाकर संबंधित व्यक्ति को सुसाइड से रोकेगी। उसके परिजनों को भी अलर्ट किया जाएगा।

हृदयरोगी बच्चों की निरूशुल्क सर्जरी हेतु एमओयू नवीनीकरण

- यह एमओयू नवीनीकरण राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं गुजरात के श्री सत्यसाई हृदय हॉस्पिटल, अहमदाबाद व राजकोट, गुजरात (प्रशान्ति मेडिकल सर्विसेज एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन) के बीच किया गया।
- इस एमओयू के माध्यम से प्रदेश राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के तहत हृदयरोग से पीड़ित 3 माह से 18 वर्ष तक के बच्चों व किशोर-किशोरियों को निःशुल्क हार्ट सर्जरी की सुविधा मिल सकेगी।

- RBSK कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्मिकों की मोबाइल टीमों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों, मदरसों, राजकीय स्कूलों में प्रत्येक बच्चे की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाती है।
- इसके अलावा जन्मजात दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उन्हें उच्च चिकित्सालयों में सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।

कट्स और राजस्थान के वाणिज्य विभाग के बीच एमओयू

- राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कट्स इंटरनेशनल और वाणिज्य विभाग के बीच एक समझौता किया गया।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और राज्य में निवेश लाने के लिए इस एमओयू पर उद्योग और वाणिज्य विभाग, कट्स इंटरनेशनल और राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद (REPC) के बीच हस्ताक्षर किए गए।
- इस सहयोग का उद्देश्य राजस्थान में औद्योगिक विकास और लक्षित निवेश को बढ़ावा देना है।

राजस्थान में कैंसर के इलाज हेतु सरकार के प्रयास

- जयपुर में अपेक्स कैंसर इंस्टीट्यूट, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, बीकानेर एवं झालावाड़ में टर्सरी कैंसर सेंटर संचालित हैं।
- इसके अलावा राजस्थान में जयपुर एवं बीकानेर में पीईटी स्केन की सुविधा भी उपलब्ध है।
- राजस्थान में जिला अस्पतालों से लेकर उपस्वास्थ्य केन्द्र तक 3 प्रकार के कॉमन कैंसर जैसे ऑरल, ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जा रही है।
- राजस्थान में जिला स्तर पर कैंसर यूनिट संचालित की जा रही है।
- लीवर कैंसर की रोकथाम के लिए हैपेटाइटिस-बी का टीका लगाया जा रहा है।
- सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी के टीके को यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- राजस्थान में 8 कैंसर वैन संचालित है जिनमें अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर जोन हैडक्वार्टर पर एक-एक कैंसर वैन तथा जयपुर में दो वैन सहित कुल 8 कैंसर वैन संचालित हैं।
- जिला चिकित्सालयों से एक चिकित्साधिकारी व दो स्टाफ नर्स को एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट मुम्बई से विशेष प्रशिक्षण दिलाकर कैंसर केयर यूनिट में पदस्थापित किया गया है।
- राजस्थान में ICMR-NCDIR बेंगलोर के तकनीकी सहयोग से कैंसर मरीजों के प्रमाणित डाटा के लिए कैंसर के संबंध में पॉलिसी तैयार की जा रही है।

- **नोट:** वैश्विक स्तर पर 17.9%, भारत में 9.9% तथा राजस्थान में 9.3% मौतें कैंसर के कारण होती है।

राजस्थान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अनुभाग की स्थापना होगी

- राजस्थान में ब्लड बैंकों के सुचारू संचालन के लिए निदेशक जनस्वास्थ्य के अधीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अनुभाग की स्थापना की जाएगी।
- यह अनुभाग राजस्थान में औषधि नियंत्रण विभाग के साथ समन्वय कर ब्लड बैंक से संबंधित समस्त कार्यों में पारदर्शिता और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगा।
- इस संदर्भ में ब्लड बैंक से संबंधित सभी चिकित्सकों को एवं पैरामेडिकल स्टाफ को नियमित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
- जोनल टीमों का गठन कर सभी ब्लड बैंकों का नियमित अंतराल पर निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
- चिकित्सा विभाग द्वारा ब्लड बैंकों में बेहतर विजिलेन्स के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जाएगा।
- इसमें बार कोड आधारित इन्वेंट्री मैनेजमेंट एवं सप्लाई सिस्टम होगा।
- इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ब्लड बैंकों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी।

राजस्थान सरकार द्वारा ई-फाइलिंग सिस्टम की रैंकिंग जारी

- हाल ही में राजस्थान सरकार ने ई-फाइलिंग सिस्टम में प्रदेश के 47 जिलों के कलेक्टरों की रैंकिंग जारी की गई है।
- इस रैंकिंग में शीर्ष-10 जिलों में पहली बार बनने वाले 7 जिले सलूंवर, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी, सांचौर, गंगापुर सिटी और खैरथल-तिजारा शामिल हैं।
- इनमें से 3 जिले सलूंवर, शाहपुरा और सांचौर लगातार टॉप-1, 2, 3 स्थान पर है।
 1. जसमीत सिंह संधू, सलूंवर
 2. राजेंद्र सिंह शेखावत, शाहपुरा
 3. शक्ति सिंह राठौड़, सांचौर
- सलूंवर के जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू पहले स्थान पर है यह 11 मिनट में एक फाइल निपटा रहे हैं।
- इस रैंकिंग में चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर आलोक रंजन अंतिम स्थान पर है। आलोक रंजन 22 घंटे 22 मिनट का समय लेकर एक फाइल निपटा रहे हैं।

ई-फाइलिंग सिस्टम

- ई-फाइलिंग सिस्टम के तहत कोई भी अधिकारी खासकर जिला कलेक्टर किसी फाइल को कब तक बिना फ़ैसला किए खुद के पास रोकता है, इस बात की जानकारी मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर पहुंचती है।

- इसके तहत राज्य में किसी फाइल के अधिकारी के पास आने के समय और उसके निस्तारण करने के समय नोट होता है।
- इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाना और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

राजस्थान में बाघों की संख्या

- राजस्थान में वर्तमान में बाघों की संख्या बढ़कर 134 हो गई हैं।
- राजस्थान में वर्तमान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ (73) है।

राजस्थान में वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व है-

1. सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व
 2. अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व
 3. कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व
 4. बूँदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व
 5. करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व
- इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में कुंभलगढ़ को भी टाइगर रिजर्व घोषित करने की भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

राजस्थान के 1 करोड़ किसानों की जमीनें आधार से लिंक होगी

- केन्द्र सरकार के डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत राजस्थान के लगभग 1 करोड़ किसानों की जमीनों को आधार नंबर से लिंक किया जाएगा।
- इसके लिए 5 साल बाद केन्द्र सरकार ने राजस्थान के लिए 582.61 लाख रुपये का बजट मंजूर करते हुए 45.72 लाख रुपये जारी कर दिए हैं।
- इसमें राजस्व मंडल द्वारा आधार को लैंड रिकॉर्ड से इंटीग्रेट किया जाएगा।
- इसमें राज्य का सूचना एवं संचार विभाग आधार से लिंक करने के लिए अनुमति देगा। इसके बाद ऑनलाइन जमाबंदी से जुड़े सॉफ्टवेयर में आधार लिंक किए जाने का प्रावधान किया जाएगा।

निर्यात क्षमता बढ़ाने हेतु शिपरॉकेट सम्मेलन

- आयोजन: जोधपुर (राजस्थान)।
- संस्था: विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शिपरॉकेट द्वारा।
- उद्देश्य: MSME की निर्यात क्षमता बढ़ाना।

ऑपरेशन एंटी वायरस

- यह ऑपरेशन ऑनलाइन साइबर ठगी पर लगाम लगाने हेतु भरतपुर व मेवात क्षेत्र में चलाया गया।

- यह ऑपरेशन केन्द्र सरकार के इंडियन साइबर क्राइम कोर्डिनेशन सेन्टर (I4C) के सहयोग से चलाया गया।
- मेवात क्षेत्र के साइबर अपराधियों की रोकथाम व इनके खिलाफ एक्शन के लिए संयुक्त अनुसंधान दल का भी गठन किया गया।
- राजस्थान में मेवात क्षेत्र को साइबर ठगी का गढ़ कहा जाता है।

ऑपरेशन क्लीन स्वीप

- यह ऑपरेशन जयपुर पुलिस द्वारा शुरू किया गया।
- इसके तहत जयपुर में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ जयपुर में अभियान चलाया गया।

मिशन सन-रक्षण 24

- राजस्थान के गोपालन विभाग द्वारा भीषण गर्मी में पशु-पक्षियों को बचाने के लिए मिशन सन-रक्षण 24 शुरू किया गया है।
- गौवंश एवं पक्षियों को लू और तापघात से बचाने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है।

शिक्षा क्षेत्र में भामाशाह सम्मान समारोह-2024 की गाइडलाइन जारी

- राजस्थान के शिक्षा विभाग की ओर से भामाशाह सम्मान समारोह- 2024 की गाइडलाइन जारी की गई है।
- राज्य के शिक्षा विभाग ने एक बार फिर भामाशाह सम्मान में कटौती की है।
- इसके तहत में जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान में भी कटौती की गई है। इसके तहत अब 5 लाख रुपये या इससे अधिक के सहयोग पर 'शिक्षा श्री' सम्मान मिलेगा।
- इससे पहले 1 लाख रुपये से अधिक के सहयोग पर भी जिला स्तर पर यह सम्मान प्रदान किया जाता था।
- नई गाइडलाइन के अनुसार-
 - 1 करोड़ रुपये से अधिक का सहयोग: 'शिक्षा विभूषण' सम्मान
 - 30 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का सहयोग: 'शिक्षा भूषण' सम्मान
 - 5 लाख रुपये से 30 लाख रुपये से कम तक सहयोग: 'शिक्षा श्री' सम्मान
- नोट: 2022 तक 15 लाख से 1 करोड़ रुपए का सहयोग देने वाले को शिक्षा भूषण दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2023 में इस सम्मान के लिए सहयोग राशि 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर दी गई।

चंद्रपाल सिंह और हरिकेश मीना को राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मान

- राजस्थान के 2 सुरक्षा जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है।

- इनमें भरतपुर के चंद्रपाल सिंह (मरणोपरांत पदक) और झुंझुनू के हरिकेश मीना शामिल हैं।
- चंद्रपाल सिंह बीएसएफ की 156 बटालियन में बतौर मुख्य आरक्षक कार्यरत थे। जो कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर की भूरीवाला चौकी पर हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे।
- उन्हें देश सेवा में योगदान के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।
- इसके अलावा झुंझुनू जिले के जवान हरिकेश मीना को भी वीरता के लिए पुलिस पदक से नवाजा गया।

आशिरा USA में 'द जी. कीथ फंस्टन पुरस्कार इन इकोनॉमिक्स' से सम्मानित

- राजस्थान की आशिरा को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में प्रतिष्ठित 'द जी. कीथ फंस्टन पुरस्कार इन इकोनॉमिक्स' से सम्मानित किया गया है।
- आशिरा यूएसए के ट्रिनिटी कॉलेज में क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ साइंस के अंतिम वर्ष की छात्रा है।
- यह पुरस्कार अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि के लिए दिया गया।

अरिजीत बनर्जी

- राजस्थान के 1991 बैच के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी अरिजीत बनर्जी को राज्य का नया हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स (HoFF) नियुक्त किया गया है।
- बनर्जी का कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक रहेगा।
- अरिजीत बनर्जी को भारतीय वन सेवा की प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) - हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स की वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है।
- यह आदेश मौजूदा हॉफ मुनीष गर्ग के 31 मई को सेवानिवृत्त होने के बाद लागू होंगे।

वन बलों का प्रमुख (HoFF)

- भारत में वन बलों का प्रमुख (HoFF) भारतीय वन सेवा (IFS) का सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी होता है।
- भारतीय वन सेवा भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है।
- वन बलों का प्रत्येक प्रमुख एक भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी होता है और उसका पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) होता है।
- HoFF भारतीय राज्यों में वन विभाग का प्रमुख है और इसका चयन राज्यपाल द्वारा, राज्य के सबसे वरिष्ठ प्रधान मुख्य वन संरक्षकों में से एक होता है।
- इनका चयन मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर किया जाता है।
- HoFF रैंक और प्रभाव में राज्य पुलिस प्रमुख (DGP), मुख्य सचिव और सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के समान होती है।

हेल्थ केयर के लिए निदान मेडिकल चेक्सपर्ट विकसित

- स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए जयपुर के दर्श, कन्हव, नक्षत्र और ऋषभ ने निदान मेडिकल चेक्सपर्ट विकसित किया है।
- चेक्सपर्ट एप से मरीजों और मेडिकल प्रोफेशनल्स को त्वरित मदद मिल सकेगी।
- इससे मरीज और डॉक्टरों के बीच संवाद के लिए केंद्रीकृत मंच मिलेगा।

टोफर (TOFR) योजना

- TOFR पूरा नाम: Tree Outside Forest in Rajasthan (ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान)
- यह राजस्थान के वन विभाग की प्रमुख योजना है।
- इसे केंद्र सरकार की योजना 'ट्री आउट साइड फॉरेस्ट' योजना तर्ज पर शुरू किया गया है।
- इस योजना के तहत 5 करोड़ पौधे वन क्षेत्र से बाहर लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
- यह योजना राजस्थान में वन क्षेत्र के बाहर हरियाली बढ़ाने हेतु है।
- इसके तहत चालू वित्त वर्ष में वन विभाग, विभिन्न संस्थाओं व आमजन के सहयोग से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
- इसके तहत 4 करोड़ पौधों का वितरण आमजन, एनजीओ, अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को वितरित किये जाएंगे।
- इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष में 70 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया जाएगा।

पीएम श्री विद्यालयों को उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा

- राजस्थान में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कर पीएम श्री विद्यालयों को उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- इसमें छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम के साथ-साथ सह-शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

पीएम श्री विद्यालय योजना

- इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण समान व समावेशी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित कर विद्यालयों का सम्पूर्ण रूपान्तरण करना है।
- केन्द्र प्रवर्तित पीएमश्री विद्यालय योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 402 विद्यालयों का चयन किया गया था।
- पीएम श्री विद्यालय योजना के द्वितीय चरण में 7 मार्च 2024 को राजस्थान के 237 पीएम श्री विद्यालयों का चयन किया गया था।
- इस योजना में अब तक राजस्थान के कुल 639 विद्यालयों का चयन किया जा चुका है।

राजस्थान की दूसरी मल्टी डिस्पिनेनरी रिसर्च यूनिट

- राजस्थान की दूसरी मल्टी डिस्पिनेनरी रिसर्च यूनिट पाली में बनेगी।
- इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (नई दिल्ली) द्वारा 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- इससे कॉलेज में अलग से रिसर्च लैब और प्रोजेक्ट के लिए अलग से संसाधन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- इसका पूरा सेटअप तैयार होने के बाद सिलिकोसिस, डिप्रेसन, डायबिटीज, मैनस्ट्रुअल हाइजीन और थायरॉइड डिसऑर्डर सहित 9 प्रमुख बीमारियों पर रिसर्च की जाएगी।
- इस रिसर्च पर होने वाला खर्च भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (नई दिल्ली) द्वारा वहन किया जाएगा।
- अभी तक डिप्रेसन का स्तर पता करने के लिए बायोमार्कर द्वारा कोई भी जाँच उपलब्ध नहीं है।
- रिसर्च के बाद शुगर की तरह मरीज के ब्लड का सैंपल लेकर उसके डिप्रेसन का पता लगाया जा सकेगा।
- नोट: राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसाइटी (RajMES) के 17 मेडिकल कॉलेजों में पहली रिसर्च यूनिट **डूंगरपुर में शुरू** की गई थी।

जयपुर में जेम्स एंड ज्वैलरी जेम बोर्स बनेगा

- राजस्थान के जयपुर स्थित सीतापुरा में मुंबई और सूरत की तर्ज पर 12 मंजिला जेम्स एंड ज्वैलरी जेम बोर्स बनेगा।
- यह 44 हजार स्क्वायर मीटर एरिया में 1500 करोड़ की लागत से बनेगा।
- जयपुर के जेम्स एंड ज्वैलरी बोर्स में 1500 ऑफिस 300 कियोस्क 01 बड़ा ऑडिटोरियम 02 कॉन्फ्रेंस रूम होंगे।
- यह जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और ज्वैलर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में बनाया जाएगा।
- जयपुर को अब तक **कलर स्टोन की मंडी या एमरल्ड हब** के रूप में जाना जाता है।
- जेम बोर्स बनने के बाद कलर स्टोन ज्वैलरी को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- जयपुर से वर्ष 2023-24 में 11269.11 करोड़ की जेम्स एंड ज्वैलरी निर्यात हुई है।

रावतभाटा में भारी पानी का संयंत्र स्थापित होगा

- राजस्थान के रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) भारी पानी संयंत्र का एक और संयंत्र स्थापित होगा।
- यह संयंत्र गैर न्यूक्लियर क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमी कंडक्टर, दवा में भारी पानी की बढ़ती मांग को पूरा करेगा।
- रावतभाटा भारी पानी संयंत्र के विस्तार के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

- हाल ही में रावतभाटा स्थित भारी पानी संयंत्र ने सबसे कम बिजली खर्च पर भारी पानी का उत्पादन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
- भारी पानी बोर्ड देश में ग्रीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने में अपना सहयोग देगा।
- रावतभाटा में ही 2030 के हाइड्रोजन गैस के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की नई तकनीक से ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन प्लांट का पायलट प्रोजेक्ट लगाया जाएगा।

भारी पानी

- भारी पानी (D2O) या ड्यूटेरियमऑक्साइड, ड्यूटेरियम के दो परमाणुओं और ऑक्सीजन के एक परमाणु से बना होता है।
- ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक स्थिर समस्थानिक है जिसके नाभिक में एक अतिरिक्त न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण हाइड्रोजन का द्रव्यमान दोगुना होता है।
- ड्यूटेरियम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन युक्त यौगिकों जैसे पानी, हाइड्रोकार्बन आदि में मौजूद होता है।
- इसे दाबित भारी पानी रिएक्टर (PHWR) में मंदक (मॉडरेटर) और शीतलक (कूलेंट) के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

राजस्थान में ICJS 2.0 के लिए गठित समिति

- **ICJS पूरा नाम: Inter-Operable Criminal Justice System.**
- हाल ही में मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के क्रियान्वयन के संबंध में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक की गई।
- इसमें ICJS 2.0 के लिए तैयार कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- इस अनुमोदित प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जायेगा।
- यह 'वन डेटा, वन एंट्री' के सिद्धांत पर आधारित है।
- इसका मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के पांच स्तंभों पुलिस, ई-अभियोजन, ई-जेल, ई-न्यायालय, ई-फॉरेंसिक को एकीकृत कर डेटा का निर्बाध आदान-प्रदान करना है।
- यह परियोजना स्मार्ट पुलिसिंग को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।

ICJS

- ICJS देश में आपराधिक न्याय के वितरण के लिये उपयोग की जाने वाली मुख्य आईटी प्रणाली के एकीकरण को सक्षम बनाने के लिये एक राष्ट्रीय मंच है।

- यह प्रणाली के पाँच स्तंभों जैसे- पुलिस (अपराध तथा आपराधिक ट्रैकिंग एवं नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से), फोरेंसिक लैब के लिये ई-फोरेंसिक, न्यायालयों के लिये ई-कोर्ट, लोक अभियोजकों के लिये ई-अभियोजन तथा जेलों के लिये ई-जेल को एकीकृत करने का प्रयास करती है।
- ICJS प्रणाली को हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ एक समर्पित और सुरक्षित क्लाउड-आधारित बुनियादी ढाँचे के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

राजस्थान में सभी जिलों में जिओ टैगिंग के साथ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे

- राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा सघन पौधारोपण किया जाएगा।
- सभी जिलों में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने जिले के जिला वन अधिकारी से समन्वय कर अन्य विभागों के सहयोग से 25 मई तक आवश्यक रूप से कार्ययोजना तैयार करेंगे।
- पौधे लगाने से पूर्व हर एक पौधे की जिओ टैगिंग, पौध रोपण स्थल की फेंसिंग, पौधों की पर्याप्त उपलब्धता 1 जून से 30 जून तक सुनिश्चित किया जाएगा।
- सभी जिलों में एक जुलाई से 15 अगस्त तक पौधारोपण अभियान क्रियान्वित किया जाएगा।

राजस्थान में 110 स्थानों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा

- राजस्थान में वन विभाग द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में 110 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित किए जाएंगे।
- इसमें सबसे ज्यादा जयपुर और उदयपुर के 10-10 पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है।
- इसके लिए विभाग द्वारा बजट का आवंटन किया जाएगा।

ताकली बाँध से रामगंजमंडी (कोटा) क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई सुविधा मिलेगी

- जलापूर्ति के लिए रामगंजमंडी उपखंड क्षेत्र दूसरे जिले पर निर्भर है। करीब 70 किमी दूर रावतभाटा में स्थित राणा प्रताप सागर बांध से रामगंजमंडी क्षेत्र के लिए पानी लाया जा रहा है।
- राजस्थान का जलदाय विभाग द्वारा रामगंजमंडी क्षेत्र में ताकली बाँध से जलापूर्ति की जाएगी।

ताकली बाँध मध्यम सिंचाई परियोजना

- वसुंधरा राजे के पहले मुख्यमंत्रित्व काल में वर्ष 2006 में ताकली बांध मध्यम सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई थी।

- इस बाँध के निर्माण को 2012 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन कभी बजट में देरी व मुआवजा तो कभी ग्रामीणों के विरोध के चलते काम सुचारू नहीं चल पाया।
- ताकली बाँध का निर्माण 2023 में पूरा हुआ।
- ताकली बाँध भरने से रामगंजमंडी में पेयजल आपूर्ति और किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा।

मतदाता जागरूकता में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा

- निर्वाचन आयोग द्वारा देशभर में सोशल मीडिया (एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब) पर मतदाता जागरूकता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है।
- इस रैंकिंग में राजस्थान और झारखंड ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है।
- सीईओ राजस्थान के एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट्स पर अप्रैल माह में करीब 11 लाख इम्प्रेसन मिले हैं।

मतदाता जागरूकता के संदर्भ में रैंकिंग

1. झारखंड, राजस्थान (संयुक्त रूप से)
 2. कर्नाटक
 3. उत्तराखंड
 4. उत्तर प्रदेश एवं पंजाब (संयुक्त रूप से)
 5. मध्य प्रदेश
- राजस्थान के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन है।

एन्फोर्समेंट सैंपल लेने में राजस्थान पहले स्थान पर रहा

- राजस्थान ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए एन्फोर्समेंट सैंपल लेने में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान में 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को 5,880 सैंपल का लक्ष्य दिया था, जबकि राजस्थान में 16,691 सैंपल लिए गए।

जैसलमेर में गोडावण पक्षी की गणना

- राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर में वार्षिक वाटरहोल सर्वेक्षण के दौरान गोडावण पक्षी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) की गणना की गई।
- जैसलमेर में वर्तमान में गोडावण पक्षियों की संख्या 64 है, जबकि पिछली गणना वर्ष 2022 में 42 पक्षी थे।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान में गोडावण के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो मुख्य रूप से सूखे घास के मैदानों में रहती है।

- रेगिस्तानी क्षेत्र में वन्यजीवों की गिनती के लिए वाटरहोल तकनीक का उपयोग करते हैं।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की गणना केवल रामदेवरा और जैसलमेर में की गई।
- इसके तहत 21 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रामदेवरा क्षेत्र में थे, जबकि 43 को जैसलमेर के सिपला, सुदासरी, गाजई माता, जमरा, चौहानी और बरना क्षेत्रों में देखा गया।
- इसके अलावा 1,000 से अधिक चिंकारा, 30 रेगिस्तानी बिल्लियाँ, 150 लोमड़ियाँ और 100 से अधिक गिद्धों की भी गणना की गई।
- गोडावण का वैज्ञानिक नाम 'अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स' है।
- भारत में सर्वाधिक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या वाला राज्य राजस्थान है।
- इसके ड्राफ्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी में 10 से ज्यादा रिसर्च ब्लॉक बनेंगे।
- इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजिकल साइंसेज में फॉरेंसिक बायोलॉजी सिरोलॉजी, डीएन फिंगर प्रिंटिंग पर शोध होगा।
- इंस्टीट्यूट ऑफ साइबर फॉरेंसिक एंड साइबर सिम्योरिटी में साइबर फॉरेंसिक साइबर क्राइम इंवेस्टिगेशन, साइबर सिम्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ड्रोन फॉरेंसिक पर शोध किए जाएंगे।
- इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल फॉरेंसिक में लाई डिटेक्शन, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग पर रिसर्च होगा।
- इसमें डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीएचडी सहित 50 कोर्स उपलब्ध होंगे।
- इसमें ED, CBI, IB, NIA और DRI के अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जयपुर भारत का 11वाँ सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना

- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारा जारी रिपोर्ट में विभिन्न एयरपोर्ट्स के फ्लाइट संचालन के आंकड़े जारी किए गए हैं।
- विमान संचालन से व्यस्तता के संदर्भ में जयपुर एयरपोर्ट देशभर में 11वें स्थान पर रहा है।
- जयपुर एयरपोर्ट से गोवा, गुवाहाटी, त्रिवेन्द्रम, श्रीनगर जैसे एयरपोर्ट पीछे रहे हैं।

भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट

1. दिल्ली
2. मुंबई
3. बंगलूरु
4. हैदराबाद
5. कोलकाता

प्रेम कंवर

- भारत से एकमात्र मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट बनी है।
- प्रेम कंवर मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क में कार्यरत है।
- प्रेम कंवर देश की पहली महिला वनकर्मी है जो डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में क्रोकोडाइल स्पेशलिस्ट ग्रुप की 27वीं कॉन्फ्रेंस में शामिल हुईं तथा अंतरराष्ट्रीय वन क्षेत्र में एक महीने की स्पेशल ट्रेनिंग ली है।
- इन्हें ऑस्ट्रेलिया में क्रोकोडाइल का रेस्क्यू और उनके प्रबंधन को लेकर विशेष ट्रेनिंग दी गई।

राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी

- इसकी स्थापना जयपुर में की जाएगी।
- इसका उद्देश्य फॉरेंसिक साइंस में अलग-अलग विंग के एक्सपर्ट तैयार करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
- यहाँ नार्को, ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्ट, वर्ल्ड क्लास इक्यूपमेंट होंगे।
- इसके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित है।

CSIR-CEERI और राजस्थान विश्वविद्यालय (RU) के मध्य कौशल विकास और प्रशिक्षण हेतु MoU

- इसके लिए CEERI पिलानी के निदेशक डॉ. पी.सी. पंचारिया व राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की कुलपति प्रो. अल्पना कटेजा के बीच समझौता हुआ।
- इसके तहत राजस्थान विश्वविद्यालय भौतिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं दक्षता को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्किल डवलपमेंट कोर्स भी शुरू करेगा।
- दोनों संस्थाएँ इसके लिए क्रेडिट, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और फ़ैकल्टी प्रशिक्षण कोर्स हेतु सहयोग करेगी।
- राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र अब CSIR-CEERI पिलानी में कौशल विकास का विशेष प्रशिक्षण भी ले सकेंगे।
- सेमीकंडक्टर का उपयोग आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है जो एग्रोटेक, बायोटेक, बायोफिजिक्स और जियोलॉजी के क्षेत्र में उपयोगी है।

फोर्ब्स की सूची में राजस्थान का स्टार्टअप ईएफ पॉलीमर शामिल

- प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स की 'वर्ष 2024 की 30 अंडर 30 एशिया' में सस्टेनेबल फार्मिंग में उदयपुर के स्टार्टअप ईएफ पॉलीमर भी शामिल है।
- इस कंपनी की स्थापना अंकित जैन और नारायण लाल गुर्जर ने 2018 में की थी।
- यह स्टार्टअप एडवांस बायो पॉलीमर तकनीक से अमृत नाम का हाईड्रोजेल बनाता है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना में राजस्थान के प्रमुख बाँधों को शामिल किया गया

- इसके तहत राजस्थान की प्रमुख नदियों और बाँधों को स्काडा सिस्टम से जोड़ा जाएगा।

- इसके तहत मानसून में नदी और बाँधों की स्थिति, जल स्तर और आवक की स्वचालित यंत्रों से गणना कर हाइटेक उपकरणों से डाटा तैयार किया जाएगा। पानी के डाटा को 12 विभागों से आपस में साझा किया जाएगा।
- इसके डाटा के आधार पर बाँधों से जल की आपूर्ति करने पर सुविधा रहेगी तथा इसमें बाढ़ की स्थिति का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा।
- इसके आधार पर संबंधित एजेंसियाँ पहले ही सक्रिय हो जाएंगी और बाढ़ से होने वाली हानि को रोक सकेंगी।
- केंद्र सरकार ने राजस्थान की प्रमुख नदियों पर बने बाँधों को स्काडा (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन) से जोड़ने की डेडलाइन तय कर दी है।
- चंबल नदी के तीनों बाँध कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बाँध और जवाहर सागर बाँध भी इस परियोजना में शामिल है।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (NHP)

- इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में की गई थी।
- इसमें अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों को 100% अनुदान दिया गया था।
- यह परियोजना केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (विश्व बैंक) की ओर से वित्त पोषित है।
- इसके तहत 8 वर्ष की अवधि में 3,680 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ व्यय का प्रावधान है।
- इस परियोजना की अवधि मार्च 2024 थी, जिसे बढ़ाकर सितंबर 2025 कर दिया है।
- इस परियोजना का उद्देश्य जल संसाधन सूचना की सीमा, विश्वसनीयता और पहुंच में सुधार करना तथा भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत बनाना है।

स्काडा (SCADA) सिस्टम

- **पूरा नाम:** Supervisory Control And Data Acquisition.
- यह एक रिमोट कंट्रोल आधारित स्वचालित केंद्रीयकृत व्यवस्था है।
- इसका पूरा सिस्टम ऑनलाइन केंद्रीकृत होता है। जाएगा। इससे जल आपूर्ति में फाल्ट के बारे में जानकारी मिलेगी।
- यह अलर्ट जारी करेगा तथा फाल्ट लोकेशन की सही स्थिति की जानकारी से समय की बचत वोल्टेज नियंत्रण होगा।
- इसके द्वारा सिस्टम ही से लाइन में आने वाली समस्याओं के बारे में अभियंताओं को ऑनलाइन दिशानिर्देश भी दिए जा सकेंगे।

रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा लड़ाकू विमानों हेतु रडार एब्जोर्बिंग पेंट तैयार किया गया

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से सम्बद्ध रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर की ओर से तैयार रडार एब्जोर्बिंग पेंट भारतीय वायुसेना के सभी लड़ाकू विमानों पर लगाया जाएगा।
- इससे वायुसेना के लड़ाकू विमान दुश्मन देशों के रडार की पहुंच से दूर रहेंगे।
- यह तकनीक DRDO द्वारा 3 कम्पनियों को ट्रांसफर किया जा रहा है।
- इसके तहत कम्पनियाँ वायुसेना बेस पर जाकर लड़ाकू विमानों को पेंट करेंगी।
- DRDO जोधपुर ने 2019 में रडार एब्जोर्बिंग पेंट तैयार किया था, जिसके बाद से इसकी 5 साल तक टेस्टिंग की जा रही थी।
- इस पेंट का उपयोग सामरिक महत्व की वस्तुओं पर भी किया जाएगा।
- इसमें परीक्षण के दौरान एयरबेस पर पेंट के बाद हवा में उड़ रहा लड़ाकू विमान का रडार उसको पकड़ नहीं पाया।
- इससे दुश्मन देशों के लड़ाकू विमानों के लेजर बमों से एयरबेस सुरक्षित रहेंगे।
- पेंट का दक्षिणी भारत में नेवी के बेस पर मिग-29 लड़ाकू विमान पर परीक्षण किया, जो सफल रहा।
- फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमान और अमरीका के एफ-14 लड़ाकू विमानों पर भी रडार एब्जोर्बिंग पेंट होता है।
- इसके अलावा रूस और चीन भी यह टेक्नोलॉजी विकसित कर चुके हैं।

रडार एब्जोर्बिंग पेंट की विशेषताएँ

- 90 प्रतिशत तक तरंगों का अवशोषण करने में सक्षम।
- कम व अधिक तापमान पर स्थायी।
- हाईड्रोलिक ऑयल, पानी, एयर टरबाइन फ्यूल के प्रति प्रतिरोधक क्षमता।
- थर्मल शॉक साइक्लिंग को झेलने में सक्षम।
- प्रेशर गन का उपयोग करके आसानी से पेंट कर सकते हैं।

केंद्र-राज्य के संयुक्त उपक्रम द्वारा बीकानेर में लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट में विद्युत उत्पादन होगा

- राजस्थान में बीकानेर के गुढ़ा वेस्ट में 125 मेगावाट क्षमता के प्लांट में लिग्नाइट से विद्युत उत्पादन होगा।
- इसके लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और भारत सरकार की कंपनी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन संयुक्त उपक्रम समझौता किया जाएगा तथा ज्वाइंट वेंचर कंपनी का गठन होगा।

- इससे राजस्थान में सस्ता विद्युत उत्पादन संभव हो सकेगा।
- राजस्थान में प्रचुर मात्रा में लिग्नाइट उपलब्ध है और सस्ता ईंधन होने के कारण इससे बिजली उत्पादन लागत 3.80 रुपए प्रति यूनिट आंकी गई है।
- इससे करीब 2,000 रुपये प्रति टन परिवहन लागत बचेगी। जबकि, अभी थर्मल पावर प्लांट के लिए छत्तीसगढ़, ओडिशा से कोयला मंगाया जाता है।
- इसी कारण थर्मल पावर प्लांट के अनुपात में लिग्नाइट आधारित प्लांट से बिजली उत्पादन 90 पैसे से एक रुपए प्रति यूनिट सस्ता होगा।
- इसके अलावा बाड़मेर के जलीपा कपूरडी माइन्स में लिग्नाइट का भंडार है।
- वर्तमान में राजस्थान में लिग्नाइट से विद्युत उत्पादन हो रहा है, लेकिन यह एक निजी कंपनी राजवेस्ट द्वारा किया जा रहा है।
- राजवेस्ट की 135-135 मेगावाट क्षमता की 8 यूनिट है।

RTU सर्वाधिक NBA एक्रिडेशन के साथ राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय बना

- नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रिडेशन (NBA) द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के बीटेक इंजीनियरिंग प्रोग्राम की मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटेशन इंजीनियरिंग ब्रांचों को एक्रिडेशन प्रदान किया गया।
- इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर, इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीयल सहित 5 ब्रांचों को एनबीए पहले ही मान्यता दे चुका है।
- इसके तहत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय राजस्थान का सर्वाधिक 8 एनबीए एक्रिडेशन वाला पहला तकनीकी विश्वविद्यालय बन गया है।
- RTU में 11 में से 8 कोर्स में एनबीए (नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रिडेशन) शामिल हो चुका है।

केंद्र सरकार क्रिटिकल मिनरल्स में अनुसंधान हेतु निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देगी

- राजस्थान में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने को लेकर प्रोत्साहन देगी।
- इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स, पोटाश, लिथियम, टंगस्टन, केडमियम, कोबाल्ट, कॉपर, ग्रेफाइट, टिटैनियम, बेरेलियम, सिल्वर, जिंक, गोल्ड, लेड जैसे 29 तरह के क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिक व अन्य मिनरल्स शामिल हैं।
- इन खनिजों के वैज्ञानिक व वैश्विक स्तरीय एक्सप्लोरेशन के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (EL) की ई-नीलामी का निर्णय किया है।
- इससे एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (EL) के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ेगी और देश में खनिजों की खोज और खनन कार्य को गति मिलेगी।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में बोन एवं टिश्यू बैंक खुलेगा

- सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में अब ट्रांसप्लांट के लिए आने वाले और दुर्घटनाग्रस्त गंभीर मरीजों के लिए ट्रामा सेंटर में ह्यूमन ल्युकोसाइट एंटीजन (HLA) लैब, बोन एवं टिश्यू बैंक स्थापित किए जाएंगे।
- इसके लिए लगभग 4 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
- चूंकि ऑर्गन डोनेशन के बाद अंग प्रत्यारोपण के लिए ह्यूमन ल्युकोसाइट एंटीजन (HLA) टेस्ट की जरूरत होती है।
- इसमें ऑर्गन डोनर और रिसीवर के टिश्यू मैच करवाए जाते हैं। इसमें यह पता लगता है कि डोनर का अंग रिसीवर यानी लेने वाले के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं।
- इससे ट्रांसप्लांट में लगने वाले समय में कमी होगी।
- HLA लैब के साथ ही अस्पताल में बोन एवं टिश्यू बैंक भी बनाया जा रहा है।
- इसमें दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हड्डी के दुर्घटना स्थल पर ही रह जाने या हड्डी के ज्यादा क्षतिग्रस्त होने पर हड्डी के गैप को मिटाने के लिए नई हड्डी लगाई जा सकेगी।
- हड्डी की गाँठ, कैंसर के कारण हड्डी खराब होने की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए भी यह बैंक संजीवनी साबित होगा। इसमें डेडिकेटेड स्टाफ होगा।
- बैंक में हड्डी व टिश्यू को माइनस 77 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर रखा जाएगा।
- बैंक के लिए हड्डी ब्रेनडेड मरीजों के परिजनों की स्वीकृति से जुटाई जाएगी।

राजस्थान की पहली हाईटेक सिटी

- राजस्थान की पहली हाईटेक सिटी जयपुर में विकसित की जाएगी। (अंतरिम बजट 2024-25 में घोषणा)
- भारत में कई राज्यों में अपने बड़े शहरों के पास सेटेलाइट सिटी विकसित कर ली हैं। जैसे कि मुंबई के पास पुणे, हैदराबाद के पास साइबराबाद, अहमदाबाद के पास गिफ्ट सिटी आदि।
- जयपुर के निकट बन रही इस हाईटेक सिटी टेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एआई, एमएल समेत अन्य न्यू एज एब्जेक्ट्स के साथ संस्थानों व कंपनियों को विश्व स्तरीय सुविधाएँ दी जाएगी।
- इससे राजधानी जयपुर का आर्थिक विकास होगा साथ ही आईटी क्षेत्र के युवाओं के लिए कई नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

रामगढ़ बाँध में प्रथम फेज में लाया जाएगा पानी

- रामगढ़ बाँध में पूर्वी राजस्थान नहर योजना के प्रथम चरण में पानी लाया जाएगा।
- इससे जयपुर जिले सहित आसपास के इलाके में सिंचाई एवं पेयजल के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा।

सिद्दी शर्मा और अंजलि जाट

- राजस्थान की युवा अंडर- 19 वीमेन खिलाड़ी सिद्दी शर्मा व अंजलि जाट का चयन नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) की ओर से आयोजित अंडर 19 वीमेन चैंपियनशिप के लिए किया गया है।
- नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) की ओर से 23 मई से 2 जून तक राजकोट में आयोजित की जाएगी।
- सिद्दी शर्मा टीम D और अंजलि जाट टीम C में खेलेंगी।
- सिद्दी शर्मा राइट ऑलराउंडर है तथा अंजलि जाट राइट आर्म मध्यम तेज गति की गेंदबाज है।

जूही प्रजापति

- जूही नेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता है।
- जूही ने बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में 10 और 11 वर्ष के आयु वर्ग में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए दोहरा स्वर्ण पदक हासिल किया है।
- इस चैंपियनशिप में 22 राज्य से 1500 से भी अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।

एशियाई जु जिम्सु प्रतियोगिता

- स्थान: अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात)
- आयोजन: ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया तथा एशियन जु जिम्सु यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में।
- नंदकिशोर जाखड़ (जयपुर) ने 94 किग्रा. भर वर्ग में कांस्य पदक जीता।

गोजुरियो कराटे चैंपियनशिप

- स्थान: श्रीगंगानगर (राजस्थान)
- आयोजन: इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी व कॉमनवेल्थ फेडरेशन द्वारा।
- अंडर 13 वर्ग में ओजस्व गजराज ने स्वर्ण पदक जीता।
- ओजस्व ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डेन विजेता हैं।

नेशनल कराटे प्रतियोगिता

- स्थान: हिमाचल प्रदेश।
- प्रनिका भार्गव और महेंद्र चौहान ने स्वर्ण पदक जीता।
- वियान जैन, शौर्य मीना और अक्षत सिन्हा ने रजत पदक जीता
- आर्यन ने कांस्य पदक जीता।

ग्रेपलिंग में राजस्थान के 4 खिलाड़ी भारतीय टीम में चयनित

- एशियन ग्रेपलिंग चैंपियनशिप फिलिपींस के तगाते में आयोजित होगी।

- इसमें भारतीय टीम में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है।
 - दीक्षिता जोशी (90 किग्रा वर्ग)
 - दीपक नेहरा (77 किग्रा वर्ग)
 - पुष्पेंद्र सिंह (71 किग्रा वर्ग)
 - हंसराज मीना (66 किग्रा वर्ग)
- राजस्थान के सुरेन्द्र सिंह एशियन रेफरी के लिए चयनित हुए हैं।

जगदीश तंवर के नेतृत्व में भारत जीता

- विश्व टेनिस प्रतियोगिता (50 आयु वर्ग में) का आयोजन मैक्सिको किया गया।
- इसमें राजस्थान के जगदीश तंवर की कप्तानी में भारतीय टीम ने पूर्व विश्व चैंपियन फ्रांस को 2-1 से हराया।
- भारतीय टीम में जगदीश तंवर, (कप्तान) (राजस्थान), नितिन कीर्तने, अजित सैल व हतितंदर पंवर है।

जयनारायण चौधरी

- जयनारायण चौधरी को भारतीय महिला वालीबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं।

अक्षयराज सिंह राठौड़

- भारत ने ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में आयोजित सेंट्रल एशियन ओपन हैंडबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता।
- इसमें पुरुष वर्ग में कांस्य पदक मैच में भारत ने क्रिगिस्तान को 34-31 से हराया।
- टीम में राजस्थान के अक्षयराज सिंह राठौड़ की शानदार गोलकीपिंग की बदौलत भारत ने कांस्य पदक जीता।
- भारतीय टीम में राजस्थान के जयपुर के अक्षयराज सिंह राठौड़, हनुमानगढ़ के राय सिंह व बूंदी के शाहरुख गौरी थे।

अवलोकित सिंह

- अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए जयपुर के अवलोकित सिंह का चयन हुआ है।
- अंडर-19 की मौजूदा नेशनल रैंकिंग में सातवें नम्बर के खिलाड़ी अवलोकित सिंह इससे पहले तीन बार एशियन चैंपियनशिप में अलग-अलग आयु वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

संस्कार सारस्वत

- राजस्थान के संस्कार सारस्वत वर्तमान में बैडमिंटन खिलाड़ी है।
- इंडोनेशिया के योजकरता में आयोजित होने वाली एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के संस्कार सारस्वत भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे।

2

राष्ट्रीय परिदृश्य

राजव्यवस्था एवं शासन

कलकत्ता हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 से पश्चिमी बंगाल में OBC सर्टिफिकेट रद्द किए

- कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 मई 2024 को पश्चिमी बंगाल में वर्ष 2010 से 2024 तक 77 समुदायों को बाँटे गए OBC सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है।
- इन 77 समुदायों को तत्कालीन पश्चिम बंगाल सरकार ने सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए थे।
- हाइकोर्ट ने 'पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा) (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 2012' के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका के संदर्भ में यह निर्णय दिया।
- जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा, मुसलमानों के कुछ वर्गों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ओबीसी आरक्षण दिया गया।
- कोर्ट ने 2012 के अधिनियम की धारा 16 को रद्द कर दिया क्योंकि यह राज्य सरकार को, केवल आदेश द्वारा पिछड़ा वर्ग वाली अनुसूची को 'जोड़ने, संशोधित करने या बदलने' की अनुमति देती है।
- इसके अलावा हाइकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ओबीसी प्रमाण पत्र वाले नागरिक जो पहले से ही सेवा में हैं, या आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या राज्य की किसी भी चयन प्रक्रिया में सफल हुए हैं, वे इससे प्रभावित नहीं होंगे।
- कोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह आमतौर पर राज्य विधानमंडल पर बाध्यकारी है।
- कोर्ट ने राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को आयोग के परामर्श से ओबीसी की राज्य सूची में नए वर्गों को शामिल करने या शेष वर्गों को बाहर करने की सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट विधायिका के समक्ष रखने का निर्देश दिया।
- खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 2010 से पहले ओबीसी की 66 श्रेणियों को वर्गीकृत करने वाले राज्य सरकार के कार्यकारी आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया गया था, क्योंकि इन्हें याचिकाओं में चुनौती नहीं दी गई थी।

- नोट: 1999 के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी फैसले (ओबीसी कोटा के कार्यान्वयन पर) ने ओबीसी सूची में जातियों को शामिल करने के लिए पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा को अनिवार्य कर दिया था।
- नोट: पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग को 17% आरक्षण का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग को दो वर्गों में बाँटा गया है
 - OBC A
 - OBC B
- OBC A से तात्पर्य अति पिछड़ा से है, जबकि OBC B में पिछड़ा वर्ग का प्रावधान रखा गया था।

हिंदू विवाह तभी वैध होगा जब इसे उचित रीति से समारोहों के साथ किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हिंदू विवाह एक 'संस्कार' है और इसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 (1) के तहत तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती, जब तक कि इसे 'उचित रीति और समारोहों के साथ नहीं किया जाता'।
- कोर्ट ने कहा कि जहाँ हिंदू विवाह लागू संस्कारों या सप्तपदी जैसे समारोहों के अनुसार नहीं किया जाता है, वहाँ विवाह को हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा।
- दूसरे शब्दों में, अधिनियम के तहत एक वैध विवाह के लिए, अपेक्षित समारोहों का आयोजन किया जाना चाहिए और कोई मुद्दा/विवाद उत्पन्न होने पर उक्त समारोह के प्रदर्शन का प्रमाण होना चाहिए।
- कोर्ट ने कहा कि विवाह कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है। इसके तहत एक पुरुष और एक महिला के बीच पवित्र संबंध स्थापित होता है।
- इसके अलावा कोर्ट ने दंपति के विवाह प्रमाण पत्र को 'हिंदू विवाह' के प्रमाण के रूप में अमान्य घोषित कर दिया।
- यह संबंध भविष्य में एक विकसित परिवार के लिए पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं जो भारतीय समाज की एक बुनियादी इकाई है।
- हिंदू विवाह वंश वृद्धि के लिए परिवार की इकाई को मजबूत करता है और विभिन्न समुदायों के भीतर भाईचारे की भावना को मजबूत करता है।

- कोर्ट के अनुसार विवाह दो व्यक्तियों को आजीवन, गरिमापूर्ण, समान, सहमतिपूर्ण और स्वस्थ मिलन प्रदान करता है।
- धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत विवाह संस्कारों और समारोहों में सप्तपदी शामिल है, यानी, दूल्हे और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के सामने फेरे लेने के पश्चात् विवाह पूर्ण माना जाता है।
- अर्थात् उचित प्रक्रियाओं का पालन किये बिना निजी संपत्ति का अधिग्रहण असंवैधानिक है।
- संपत्तियों के अधिग्रहण के दौरान सरकार को अनुच्छेद 300A के तहत 7 उप-अधिकारों का पालन करना होता है।

मामला

- यह मामला डॉली रानी और मनीष नामक दंपति का है। ये दोनों प्रशिक्षित पायलट हैं।
- दोनों ने 2021 के मार्च महीने में सगाई की तथा उसके बाद जुलाई में एक मंदिर में जाकर तथाकथित रूप से विवाह करके एक प्रमाणपत्र ले लिया और फिर उसके आधार पर विवाह का पंजीकरण करा लिया।
- दोनों के परिवार ने उनका विवाह हिन्दू रीति रिवाजों से करने के लिए 25 अक्टूबर 2024 की तिथि तय की। लेकिन आपसी मतभेद बढ़ने के कारण यह मामला तलाक लेने हेतु कोर्ट तक पहुंचा।
- **नोट:** इनके विवाह में सप्तपदी का संस्कार (7 फेरे) और विवाह का आधिकारिक समारोह या रीति रिवाज के तहत नहीं किया गया था।
- इस मामले में अन्य बातों के आलावा अदालत के सामने प्रश्न यह था कि क्या सप्तपदी के बिना कोई हिन्दू विवाह को वैधानिक मान्यता दी जा सकती है?
- इस मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू विवाह के अनुष्ठानों और उसके कानूनी और सामाजिक सामाजिक प्रभावों की व्यापक विवेचना की।

अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किए बिना 'सार्वजनिक उद्देश्य' के लिए निजी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, असंवैधानिक है: सुप्रीम कोर्ट

- सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को निर्णय दिया कि अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किए बिना "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए निजी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण, असंवैधानिक होगा।
- न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि संपत्ति का अधिकार (Right to Property) एक संवैधानिक अधिकार के रूप में संरक्षित है और इसकी व्याख्या एक मानव अधिकार के रूप में भी की गई है।
- सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण हेतु भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए एक आदेश दिया।
- इस आदेश के अनुसार, सरकारों के पास लोगों की संपत्तियों का अधिग्रहण करने का अधिकार तो है, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा।

संपत्ति का अधिकार

- भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 31 के तहत 'संपत्ति का अधिकार' मौलिक अधिकार था।
- केंद्र सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन (1978) के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया।
- अनुच्छेद 300 A के तहत 'कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा'।
- इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A में 'कानून के अधिकार' का एक अभिन्न अंग है।

अनुच्छेद 300A के तहत 7 उप-अधिकार

1. **नोटिस का अधिकार:** राज्य का कर्तव्य है कि वो व्यक्ति को सूचित करे कि राज्य उसकी संपत्ति अधिग्रहण करना चाहती है।
 2. **सुनवाई का अधिकार:** जिस व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण होना है, राज्य को उसकी आपत्तियों को सुनना होगा।
 3. **तर्कसंगत निर्णय का अधिकार:** राज्य को इस बात की सूचना देनी होगी कि उन्होंने किसी व्यक्ति की संपत्ति के अधिग्रहण का निर्णय ले लिया है।
 4. **केवल सार्वजनिक जरूरतों के लिए अधिग्रहण:** राज्य को ये बताना होगा कि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।
 5. **पुनर्वास या उचित मुआवजा:** राज्य को ये सुनिश्चित करना होगा कि अधिग्रहण के लिए व्यक्ति को उचित मुआवजा मिले या उसके पुनर्वास की उचित व्यवस्था हो।
 6. **कुशल और समयसीमा के अंदर होने वाली प्रक्रिया:** राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि अधिग्रहण कुशलतापूर्वक हो और अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के भीतर हो।
 7. **निष्कर्ष का अधिकार:** राज्य को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये पूरी प्रक्रिया अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचे।
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये 7 अधिकार अनुच्छेद 300 (A) के मूलभूत तत्व हैं।
 - इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं करने पर इस कानून का उल्लंघन होगा।
 - इन अधिकारों को अधिग्रहण से जुड़े कई अन्य अधिनियमों में भी शामिल किया गया है। जैसे- 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम।

अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम अधिसूचित किया गया

- अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम को रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- यह अधिनियम 10 मई, 2024 से लागू हुआ।
- इसे अंतर-सेवा संगठनों (आईएसओ) के प्रभावी आदेश, नियंत्रण और कुशल कामकाज को बढ़ावा देने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था।
- इसे 15 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।
- यह अधिनियम आईएसओ के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को प्रत्येक सेवा की विशिष्ट व्यक्तिगत सेवा की शर्तों को बिना छेड़े, अनुशासन और प्रशासन को प्रभावी बनाए रखने के लिए, अपने अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है।
- यह अधिनियम अंतर-सेवा संगठनों के प्रमुखों को सशक्त बनाएगा और मामलों के शीघ्र निपटान का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- यह सशस्त्र बल कर्मियों के बीच अधिक एकीकरण और एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह अधिनियम भारतीय सेना को एकीकृत थिएटर कमांड में नियोजित पुनर्गठन से पहले लागू किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 39b के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई

- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।
- इस पीठ में CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस बी वी नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जे बी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय में मुंबई के प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन (POA) द्वारा दायर मुख्य याचिका सहित कुल 16 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
- POA ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डिवेलपमेंट एक्ट (MHADA) के अध्याय VIII-A के विरुद्ध याचिका दायर की थी।
- महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डिवेलपमेंट एक्ट 1986 में जोड़े गए इस अध्याय के तहत यह प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार को जीर्ण-शीर्ण इमारतों और उसकी जमीन को अधिग्रहित करने का अधिकार है बशर्ते उसके 70% मालिक ऐसा अनुरोध करें।

- अनुच्छेद 39 (b) के तहत दायित्व को लागू करते हुए MHADA अधिनियम को वर्ष 1986 में संशोधित किया गया था। इसमें धारा 1A को जोड़ा गया था, जिसके तहत भूमि और भवनों को प्राप्त करने की योजनाओं को क्रियान्वित करना शामिल था, ताकि उन्हें जरूरतमंद लोगों को हस्तांतरित किया जा सके।
- याचिका के तहत यह तर्क दिया गया कि इस अध्याय के प्रावधान संपत्ति के अधिकार के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।
- इस याचिका के तहत निम्नलिखित मुद्दों में सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करेगा-
 - क्या निजी संपत्ति अनुच्छेद-39b के तहत 'समुदाय के संसाधन' के तहत आती है?
 - क्या राज्य किसी व्यक्ति या समुदाय की निजी संपत्ति को लोकहित के लिए अपने नियंत्रण में ले सकता है?
 - क्या राज्य उस संपत्ति को अधिग्रहण और पुनर्वितरित कर सकता है?

अनुच्छेद 39b

- यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) के अंतर्गत आता है।
- इसके तहत **राज्य प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे अधिकतम लोगों का हित हो।**
- अर्थात् राज्य को ये अधिकार है कि वो लोकहित के लिए सामुदायिक या निजी संसाधनों को उचित रूप से बाँट सकती है और नीतियाँ भी बना सकती है।

- **नोट:** राज्य के पास अधिकार होने के बावजूद अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है, तो उसके पास सरकार को चुनौती देने का न्यायिक विकल्प भी उपलब्ध है।
- राज्य के निजी संपत्ति पर अधिकार को निम्नलिखित आधार पर चुनौती दी जा सकती है:
 - अधिग्रहण 'लोक हित' के लिए नहीं है।
 - राज्य ने बदनीयती से संपत्ति कब्जे में ली है।
 - यदि इस अधिग्रहण पर बाजार भाव से मुआवजा नहीं मिला हो।

देश में पहली बार मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रीय राजनीतिक दल को भी घोटाले का आरोपी बनाया गया

- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में **दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) को पहली बार आरोपी बनाया है।**
- देश में यह पहला मौका है जब किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को आरोपी बनाया गया है।

राजनीतिक दल पर मुकदमे का आधार

- ED ने इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 70 के तहत कार्रवाई की है जो कंपनियों के अपराध से संबंधित है।
- धारा 70 एक राजनीतिक दल पर मामला दर्ज करने का अधिकार देती है।
- धारा 70 के तहत जब किसी कंपनी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय व्यवसाय संचालित करने वाली इकाई का हिस्सा होने के नाते प्रभारी या जिम्मेदार था, उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- इस कानून के अनुसार, एक कंपनी, कंपनी अधिनियम के तहत एक व्यावसायिक इकाई है।
- इसके तहत एक कंपनी को 'व्यक्ति' के रूप में भी माना जाता है।
- एक कंपनी एक राजनीतिक दल के विपरीत, मुनाफा चाहती है। लेकिन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 'व्यक्तियों के संघ' की परिभाषा के तहत राजनीतिक दल को 'कंपनी' के रूप में शामिल करने के लिए धारा 70 के दायरे का विस्तार किया गया था।
- राजनीतिक दल को धारा 29A के तहत नागरिकों के एक संघ के रूप में परिभाषित किया गया है।
- चूंकि आम आदमी पार्टी भी व्यक्तियों का एक संघ है, इसलिए वह भी कंपनी की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।
- एक कंपनी एक अलग कानूनी इकाई है और उसके सदस्यों या इसे संचालित करने वालों पर स्वतंत्र रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

- यह एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग (अवैध धन को वैध करना) के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जाँच करता है।
- यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली में है।
- ED के वर्तमान निदेशक राहुल नवीन हैं।
- इसके मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता प्रदान की गई

- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की अधिसूचना जारी होने के बाद 15 मई 2024 को पहली बार 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे गए।
- यह नागरिकता पोर्टल के माध्यम से उनके आवेदन ऑनलाइन संसाधित होने के बाद दी गई।
- इसमें पोर्टल के माध्यम से आवेदन, जिलास्तरीय समिति (DLC) द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (EC) द्वारा आवेदनों की जांच और नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)

- नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship (Amendment) Act) 11 मार्च 2024 को देश में लागू हो गया।
- इस अधिनियम के तहत नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया था।
- इस अधिनियम में 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।
- यह भारत के तीन पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का कानून है।
- CAA 2019 से पहले किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए यह समय अवधि 5 साल कर दी गई है।

3

आर्थिक परिदृश्य

चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना

- चीन वित्त वर्ष 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है।
- भारत के साथ व्यापार के मामले में चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया।
- यह आँकड़े आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) द्वारा जारी किए गए।
- भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 118.3 अरब डॉलर रहा है।
- 2021-22 और 2022-23 में अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
- वित्त वर्ष 2023-24 में चीन को भारत का निर्यात 8.7% बढ़कर 16.67 अरब डॉलर हो गया।
- भारत का निर्यात लौह अयस्क, सूती धागा / कपड़े/ मेकअप, हथकरघा, मसाले, फल और सब्जियां, प्लास्टिक और लिनोलियम जैसे क्षेत्रों में बढ़ा है।
- इसके अलावा चीन से भारत का आयात 3.24% बढ़कर 101.7 अरब डॉलर हो गया है।
- भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात 2023-24 में 1.32% घटकर 77.5 अरब डॉलर रह गया। 2022-23 में यह 78.54 अरब डॉलर था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत का आयात लगभग 20% घटकर 40.8 अरब डॉलर रह गया।

रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करने की मंजूरी दी

- रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2.11 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है।
- रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर को 6.50% तक बढ़ाने का फैसला किया।
- **आकस्मिक बफर जोखिम:** इसका तात्पर्य उस धनराशि से है जो आरबीआई को अपनी वर्तमान देनदारियों (जैसे दिन-प्रतिदिन की लागत, कर्मचारी वेतन, आदि) को पूरा करने और मौद्रिक और विदेशी मुद्रा कार्यों जैसे अपने वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बनाए रखना होता है।
- रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से 2018 में आरबीआई के आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए

बिमल जालान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

- बिमल जालान समिति ने सिफारिश की थी कि आरबीआई को एक आकस्मिक बफर जोखिम बनाए रखना होगा जो उसकी बैलेंस शीट का 6.5% से 5.5% होगा।
- इस समिति ने आकस्मिक बफर जोखिम बनाने के बाद बाकी अधिशेष केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में हस्तांतरित कर देने की सिफारिश की थीं
- रिजर्व बैंक ने 26 अगस्त 2019 को जालान समिति की सिफारिश को अपनाया।
- कोविड-19 के कारण, आरबीआई ने 2018-19 से 2021-22 तक अपनी बैलेंस शीट का 5.5% का आकस्मिक बफर जोखिम बनाए रखा।
- मजबूत आर्थिक विकास के कारण, आकस्मिक बफर जोखिम को 2022-23 में 6% और 2023-24 में 6.5% तक बढ़ा दिया गया।

सेबी द्वारा अफवाहों पर रोक लगाने हेतु नए नियम और मार्केट कैप कैलकुलेशन हेतु नया तरीका लागू किया गया

- शेयर बाजार को अफवाहों से बचाने के लिए सेबी ने नई गाइडलाइंस जारी की है।
- इस गाइडलाइन के मुताबिक, अगर किसी अनवेरिफाइड न्यूज या अफवाह की वजह से स्टॉक में बड़ा बदलाव आता है तो 24 घंटे के अंदर कंपनी को उस खबर को कंफर्म करना होगा और अपनी स्थिति साफ करनी होगी।
- इसके तहत 250 टॉप लिस्टेड कंपनियों को 24 घंटे के अंदर स्टॉक को प्रभावित करने वाली खबरों पर स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
- यह गाइडलाइन 1 जून 2024 से टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों पर लागू हुई, जबकि दिसंबर 2024 तक अगली 150 कंपनियों पर लागू होगी।
- सेबी ने कंपनियों, स्टॉक एक्सचेंज और देश के दिग्गज बिजनेस चैंबर्स एसोसिएम, फिक्की और सीआइआइ के लिए यह सर्कुलर जारी किया है।
- इस गाइडलाइन में मार्केट से जुड़े अफवाहों के वेरिफिकेशन को लेकर इंडियन स्टैंडर्ड तैयार किया गया है।
- अब सेबी के 'लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्कलोजर नॉर्म्स' के तहत बाजार से जुड़े किसी भी खबर को वेरिफाई करना अनिवार्य होगा।

- इसके अलावा बाजार में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू के आकलन का तरीका बदल गया है।
- सेबी के नए निर्देशों के अनुसार कंपनियों का मार्केट कैप दैनिक ट्रेडिंग की बजाय पिछले 6 महीने के औसत भाव से तय होगा।
- ये बदलाव 31 दिसंबर 2024 से लागू होंगे।
- इसके तहत लिस्टेड कंपनियों की रैंकिंग 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक रहे औसत मार्केट कैप के आधार पर तय होगी, जिसमें 31 दिसंबर कट-ऑफ तारीख होगी।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI)

- यह एक वैधानिक निकाय है।
- इसका गठन 12 अप्रैल, 1988 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में किया गया।
- इसे वर्ष 1992 में एक वैधानिक दर्जा दिया गया और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधान 30 जनवरी, 1992 को लागू हुए।
- इसका मुख्य कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना है।
- इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में हैं।
- वर्तमान में इसकी अध्यक्ष सुश्री माधवी पुरी बुच (SEBI की पहली महिला अध्यक्ष) है।

अप्रैल में अब तक का सबसे अधिक 2.10 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह

- अप्रैल में अब तक का सबसे अधिक 2.10 लाख करोड़ रुपये का वस्तु और सेवा कर (GST) संग्रह हुआ।
- वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में सकल जीएसटी संग्रह में 12.4% की वृद्धि हुई है।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) का ट्रेडिंग-कम-क्लियरिंग (TCM) सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना

- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 13 मई 2024 को गुजरात के गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) का ट्रेडिंग-कम-क्लियरिंग (TCM) सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना है।
- इससे SBI IBU गिफ्ट सिटी को IIBX प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने और अपने ग्राहकों की ओर से उनका सेटलमेंट करने में सक्षम बनाएगा।
- ट्रेडिंग-कम-क्लियरिंग के रूप में इस क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े बैंक के प्रवेश से IIBX में ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ावा मिलेगा।

इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लिमिटेड (IIBX)

- इसे 29 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था।
- IIBX को NSE, INDIA INX (बीएसई की सहायक कंपनी), NSDL, CDSL और MCX जैसे भारत के लीडिंग मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थानों द्वारा स्पॉन्सर किया गया है।
- इसे GIFT सिटी गांधीनगर (गुजरात) में स्थापित किया गया है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है।
- IIBX को भारत में सर्राफा यानी बुलियन (सोना-चांदी) आयात करने हेतु गेटवे प्रदान करने और सर्राफा व्यापार, सर्राफा वित्तीय उत्पादों में निवेश और IFSC में वॉल्टिंग सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए एक विश्व स्तरीय सर्राफा एक्सचेंज इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए की गई है।
- इसके तहत एक भारतीय जौहरी IIBX का ग्राहक या सीमित प्रयोजन ट्रेडिंग सदस्य बनकर IIBX के माध्यम से सीधे भारत में बुलियन आयात कर सकता है।

सेसम (Sesame): सेतु ने भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) लॉन्च किया

- सेसम भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) है, जिसे विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसे पाइन लैब्स के स्वामित्व वाली सेतु (Setu) द्वारा लॉन्च किया गया है।
- यह वित्तीय सेवाओं के लिए चैटजीपीटी जैसी सेवा है।
- फिनटेक फर्म सेतु ने घरेलू एआई रिसर्च फर्म सर्वम एआई के सहयोग से विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (BFSI) क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया है।
- सेसम भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे द्वारा सक्षम डेटा की सहायता से बेहतर क्रेडिट अंडरराइटिंग, धोखाधड़ी का पता लगाने, ऋण निगरानी, अपसेल/क्रॉस-सेल और व्यक्तिगत वित्त सलाहकार जैसी सुविधाओं को सशक्त बनाया जा सके।
- इसे 7 मई 2024 को गैर-लाभकारी पीपल+एआई (People+ai) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम 'अदभुत इंडिया' में लॉन्च किया गया।
- सेतु और सर्वम एआई ने मिलकर सेसम को कस्टम डेटा पर प्रशिक्षित करके डोमेन और क्षेत्र-विशिष्ट बनाया है जो भारत के BFSI क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
- **नोट:** सर्वम की स्थापना जुलाई 2023 में विवेक राघवन और प्रत्यूष कुमार ने की थी।

सेतु

- सेतु एक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता है
- यह बिल भुगतान, बचत, क्रेडिट और भुगतान पर सेवाएं प्रदान करता है।
- इसे 2018 में साहिल किनी और निखिल कुमार द्वारा स्थापित किया गया।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कंपनी को अकाउंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने का लाइसेंस दिया है।

वित्त वर्ष 2023-2024 में भारत का निर्यात रिकॉर्ड 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा

- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य 776.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- 2023-2024 में सेवा निर्यात 325.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- 2023-2024 में व्यापारिक निर्यात 451.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 437.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- वित्त वर्ष 2023-2024 में चीन, रूस, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर सहित कई देशों में भारत के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- यूके, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका शीर्ष 10 सूची में शामिल अन्य देश हैं।
- भारत का कुल आयात 2022-2023 में 898.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023-2024 में 853.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

- भारत का व्यापार घाटा 2022-23 में 121.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023-24 में 75.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

शुद्ध घरेलू बचत 2022-23 में 14.16 लाख करोड़ रुपये रही

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी 2024 के अनुसार, शुद्ध घरेलू बचत 2020-21 में 23.29 लाख करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर से कम होकर 2022-23 तक तीन साल में 14.16 लाख करोड़ रुपये रह गई है (9 लाख करोड़ रुपये घटी)।
- वर्ष 2020-21 से घरेलू बचत में लगातार गिरावट हो रही है।
- 2021-22 में शुद्ध घरेलू बचत घटकर 17.12 लाख करोड़ रुपये रह गई और 2022-23 में यह 5 साल के निचले स्तर 14.16 लाख करोड़ रुपये पर आ गई।
- 2017-18 में शुद्ध घरेलू बचत का पिछला निचला स्तर 13.05 लाख करोड़ रुपये था।
- इसके अलावा म्यूचुअल फंड में निवेश 2020-21 में 64,084 करोड़ रुपये से 3 साल में लगभग तिगुना बढ़कर 2022-23 में 1.79 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- शेयरों और डिबेंचर में घरेलू निवेश 2020-21 से तीन साल में 1.07 लाख करोड़ रुपये से लगभग दोगुना होकर 2022-23 में 2.06 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- परिवारों को बैंक अग्रिम (ऋण) भी तीन साल में दोगुना होकर 2022-23 में 11.88 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि 2021-22 में यह 7.69 लाख करोड़ रुपये था।

4

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

चाबहार बंदरगाह पर भारत और ईरान के बीच 10 वर्षों के अनुबंध पर हस्ताक्षर

- भारत और ईरान ने 10 वर्षों तक ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल का संचालन हेतु 13 मई 2024 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- अभी तक भारत चाबहार के शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह को एक अल्पकालिक अनुबंध पर संचालित करता था जिसे समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता था।
- चाबहार पहला अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह टर्मिनल है जिसे भारत द्वारा संचालित किया जाएगा।
- यह समझौता ईरान की राजधानी तेहरान में इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन (PMO) द्वारा किया गया।
- **नोट:** ईरान के चाबहार बंदरगाह के दो टर्मिनल हैं, शाहिद बेहिश्ती और शाहिद कलंतरी। भारत को सिर्फ शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल के संचालन का अधिकार मिला है।
- यह 2016 में हस्ताक्षरित समझौते का स्थान लेगा, जिसने इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को एक वर्ष के लिए शाहिद बेहिश्ती पोर्ट को संचालित करने का अधिकार दिया था।
- इसमें प्रत्येक एक वर्ष के बाद अनुबंध का नवीनीकरण किया जाता था।
- इस समझौते के हिस्से के रूप में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल को विकसित करने में लगभग 120 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा।
- इस टर्मिनल तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रेल और सड़क बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए भारत सरकार ने ईरान को 250 मिलियन डॉलर का कर्ज भी दिया है।

चाबहार बंदरगाह

- चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर स्थित ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है जो ईरान को हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है।
- चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित है।
- यह बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से लगभग 120 किमी. दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहां चीन द्वारा वित्त पोषित ग्वादर बंदरगाह स्थित है।

- चाबहार का निकटतम भारतीय बंदरगाह गुजरात में कांडला बंदरगाह है। कांडला से इसकी दूरी 550 समुद्री मील है।
- चाबहार बंदरगाह 7,200 किमी लंबे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का भी हिस्सा है।
- यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के रास्ते भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ेगा।

स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वाँ सदस्य बना

- स्पेन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का 99वाँ सदस्य बन गया है।
- स्पेन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य बनने के लिए आवश्यक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन उपकरण की पुष्टि कर दी है और उसे ISA हेड ऑफ डिपॉजिटरी के पास जमा कर दिया है।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मेजबान देश है और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह इस समय डिपॉजिटरी के प्रमुख हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

- भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP21) के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी।
- इसका मुख्यालय गुरुग्राम (हरियाणा) में है।
- इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए देशों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है।
- प्रारंभ में वे देश जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच स्थित थे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य बनने के पात्र थे।
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन द्वारा 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पहले संस्थापक सम्मेलन में ISA के फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन किया गया जिसके तहत अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं।

- यह प्रावधान 15 जुलाई 2020 से लागू हुआ।
- इसका लक्ष्य जीवाश्म ईंधन के मुकाबले सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के देशों को एक साथ लाना है।
- अब तक 119 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि 99 देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन दस्तावेज का अनुमोदन कर दिया है।

नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी

- नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से हुई।
- संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से लगभग दो तिहाई सदस्य फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, जिसमें भारत, रूस और चीन जैसे देश भी शामिल हैं।
- अल्जीरिया दुनिया का पहला देश था जिसने दो-राष्ट्र समाधान, फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी थी।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अधिकांश पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया ने अभी तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को सदस्य बनाने प्रस्ताव पारित

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया।
- इस प्रस्ताव को भारत सहित 143 देशों का समर्थन मिला, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल समेत 9 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया।
- हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा से प्रस्ताव पारित होने से फिलिस्तीन को कुछ विशेष अधिकार मिल सकते हैं। सितंबर 2024 से फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन उसे UN के किसी भी प्रस्ताव में वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा से प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास जाएगा।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की सहमति से ही फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन सकता है।
- अप्रैल 2024 में फिलिस्तीन को सदस्य बनाने का प्रस्ताव UNSC में पेश किया गया था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के वीटो के कारण प्रस्ताव पास नहीं हुआ था।

NPCI नामीबिया में UPI की तर्ज पर पेमेंट सिस्टम विकसित करेगा

- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 2 मई 2024 को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) के माध्यम से नामीबिया के लिए UPI की तरह इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलप करने में मदद करने की घोषणा की।
- इसके लिए बैंक ऑफ नामीबिया (BON) के साथ एक एग्रीमेंट में साइन किया गया है।
- इस एग्रीमेंट का उद्देश्य अफ्रीकी देश में डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस को बढ़ाना, रियल टाइम पर पर्सन-टू-पर्सन (P2P) और मर्चेन्ट पेमेंट ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करना है।
- यह इंटरनेशनल मार्केट में UPI स्टैक को डिप्लॉय करने के लिए किसी केंद्रीय बैंक के साथ NPCI का पहला सहयोग है।
- NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL), UPI को डेवलप करने वाली कंपनी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है।
- यह दूसरे देशों में UPI के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का काम करती है।

आर्मेनिया और अजरबैजान में साझा सीमा के विवादित हिस्सों के समझौते पर सहमति बनी

- आर्मेनिया और अजरबैजान अपनी साझा सीमा के विवादित हिस्सों पर 16 मई 2024 को एक समझौते पर सहमत हुए हैं।
- इस समझौते में 1990 के दशक में आर्मेनिया द्वारा जब्त किए गए चार सीमावर्ती गांवों की अजरबैजान को वापसी शामिल है।
- इसके तहत 4 सीमावर्ती गाँव - बाघनिस आयरुम, अशाघी अस्कपारा, खैरिमली और घिजिलाजिली पुनः अजरबैजान के नियंत्रण में आ जाएंगे।
- यह 2023 में अजरबैजान द्वारा नागोर्नो-काराबाख के अपने अलग हुए क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के बाद आया है, जिस पर दशकों से अर्मेनियाई अलगाववादियों का नियंत्रण था।
- नागोर्नो-काराबाख संघर्ष नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक जातीय और क्षेत्रीय संघर्ष था।

'वॉक द टॉक' योग कार्यक्रम

- इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में किया गया।
- इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम गेबियस और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भाग लिया।

WHO के बारे में

- स्थापना:- 7 अप्रैल 1948
- महानिदेशक:- टेड्रोस एडनोम गेब्रेयसस
- मुख्यालय:- जिनेवा, स्विट्जरलैंड

BIMSTEC का पहला चार्टर लागू हुआ

- हाल ही में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) का चार्टर 20 मई 2024 को लागू हुआ।
- **नोट:** अप्रैल 2024 में, नेपाल की संसद ने बिम्सटेक चार्टर को अपनाने के साथ ही समूह के सदस्यों की सहमति प्राप्त हो गई।

BIMSTEC चार्टर का महत्व

- चार्टर के लागू होने के साथ अब यह संगठन नए सदस्यों और पर्यवेक्षकों को शामिल कर सकेगा।

- चार्टर इस क्षेत्र में सहयोग के लिए कानूनी और संस्थागत फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
- यह चार्टर समूह को कानूनी मान्यता भी प्रदान करता है।
- यह देशों या उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थानों के साथ समझौतों के समापन को सक्षम बनाता है।
- इससे बिम्सटेक के संचालन हेतु एक सुस्पष्ट रूपरेखा स्थापित हुई है।
- इसमें सहयोग के क्षेत्रों का पुनर्गठन करते हुए इनकी संख्या घटाकर 7 कर दी गई है और प्रत्येक सदस्य-राज्य एक क्षेत्र के लिए, नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करेगा-
 1. व्यापार, निवेश और विकास - बांग्लादेश
 2. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन - भूटान
 3. ऊर्जा के साथ-साथ सुरक्षा - भारत
 4. कृषि और खाद्य सुरक्षा - म्यांमार
 5. पीपल-टू-पीपल कनेक्ट - नेपाल
 6. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार - श्रीलंका
 7. कनेक्टिविटी - थाईलैंड

BIMSTEC

- यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है।
- इसके सदस्य बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं।
- इसके 7 सदस्य निम्नलिखित हैं-

1. बांग्लादेश	2. भूटान	3. भारत	4. नेपाल
5. श्रीलंका	6. म्यांमार	7. थाईलैंड	
- यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व-एशिया के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है।
- इसका उद्देश्य दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में तटीय और निकटवर्ती देशों के बीच साझा विकास और सहयोग में तेजी लाना है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई।
- इसका गठन BIST-EC (Bangladesh, India, Srilanka, Thailand - Economic Cooperation) नाम से किया गया। इसमें 4 सदस्य देश बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे।
- वर्ष 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर 'BIMST-EC' कर दिया गया।
- वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के इसमें शामिल होने के बाद संगठन का नाम बदलकर '**बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (BIMSTEC)**' कर दिया गया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए दुनिया के पहले प्रमुख कानून को यूरोपीय संघ की अंतिम मंजूरी मिली

- यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने 21 मई 2024 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने के लिए दुनिया के पहले प्रमुख कानून पर अंतिम सहमति दे दी है।
- यह नियामक कानून कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के लिए व्यापक नियम निर्धारित करता है।
- इसका लक्ष्य यूरोप में नई प्रौद्योगिकियों से निपटने में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर जोर देना है।

- यह कानून एआई के उन अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध लगाता है, जो मानवीय मूल्यों और मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न करते हो।
- एआई अधिनियम को यूरोपियन यूनियन परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो नियामक कानून का एक प्रमुख हिस्सा है।
- एआई अधिनियम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण लागू करता है।



यूरोपीय संघ

- वर्तमान सदस्य संख्या: 27 देश
- स्थापना: मास्ट्रिच संधि द्वारा 1 नवंबर, 1993 में।
- मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम
- वर्तमान प्रमुख : उर्सुला वॉन डेर लेयेन
- वर्तमान सदस्य: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। यूनाइटेड किंगडम, जो यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य था, ने वर्ष 2020 में संगठन छोड़ दिया।

- यह संधि सदस्य देशों के नागरिकों हेतु अधिकार, अप्रवास, शरण, और न्यायिक मामलों के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाकर एकल मुद्रा (यूरो), एकीकृत विदेश और सुरक्षा नीति, और सामान्य नागरिकता के माध्यम से यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु की गई।

न्यू कैलेडोनिया विवाद

- हाल ही में फ्रांस के अधिकार वाले न्यू कैलेडोनिया (New Caledonia) में हाल के विरोध प्रदर्शनों के बीच दंगे भड़क गए और कई लोगों की मौत हो गई।
- फ्रांस ने 15 मई 2024 को वहाँ आपातकाल की स्थिति की घोषणा की।

विवाद का कारण

- यह विरोध प्रदर्शन फ्रांसीसी संसद द्वारा पारित विधेयक के बाद हुआ, जिसके तहत 10 साल से अधिक समय से न्यू कैलेडोनिया में रहने वाले फ्रांसीसी निवासियों को मतदान का अधिकार दिया गया है।
- इस कारण वहाँ के मूल निवासी कनक लोगों के निर्वाचन अधिकारों में कमी की आशंका के कारण यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है।

न्यू कैलेडोनिया

- यह फ्रांस के अधिकार वाला विदेशी क्षेत्र है, जो दक्षिणी प्रशांत में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में लगभग 1,500 किमी. दूर स्थित है।
- इनमें 41% मेलानेसियन कनक (मूल निवासी) और लगभग 24% यूरोपीय मूल के लोग हैं तथा यूरोपीय लोगों में अधिकांश फ्रेंच हैं।
- इस जलडमरूमध्य को यह नाम ब्रिटिश खोजी यात्री कैप्टेन जेम्स कुक ने 1774 में दिया था।
- 1854 में इसे फ्रांस ने अपने नियंत्रण में ले लिया।
- 19वीं सदी में फ्रांस का उपनिवेश बनने के बाद न्यू कैलेडोनिया 1946 में फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी बन गया।
- हिंद प्रशांत क्षेत्र में न्यू कैलेडोनिया उन पांच द्वीपीय इलाकों में से एक है जिनका नियंत्रण फ्रांस के हाथ में है।
- 1998 में 'नूमेया अकाॉर्ड' के तहत इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के सुधार का एक खाका तैयार किया गया और इसके साथ ही 1998 के पहले से यहां रहते आए कनक मूल निवासियों और प्रवासियों को वोटिंग का अधिकार मिला।
- नूमेया अकाॉर्ड की शर्तों के तहत प्रांतीय चुनावों में मतदान का अधिकार सिर्फ उन लोगों और उनके वंशजों को दिया गया जो न्यू कैलेडोनिया में 1998 के पहले से रहते आए हैं।
- इसका उद्देश्य मूल निवासी कनक लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना था जो आबादी के लिहाज से अल्पसंख्यक हो गए थे।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के DAHD और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

- केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने वैक्सीन कोल्ड चैन प्रबंधन, संचार योजना के डिजिटलीकरण और क्षमता निर्माण पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस समझौते के तहत UNDP समुदायों और जानवरों

- की सुरक्षा और जूनोटिक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए भारत की पहली पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली का समर्थन और मजबूत करेगा।
- यह समझौता ज्ञापन यूएनडीपी इंडिया द्वारा कोल्ड चैन के डिजिटलीकरण और दूरस्थ तापमान निगरानी के माध्यम से डिजिटल भविष्य बनाने में मदद करेगा।
- भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ लोग, 53.57 करोड़ खेतीहर पशुओं और 85.18 करोड़ कुक्कुट आबादी है।
- वैक्सीन स्टॉक और प्रवाह पर वास्तविक समय की जानकारी यूएनडीपी द्वारा विकसित एनिमल वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (एविन) द्वारा प्रदान की जाएगी।
- एविन वैक्सीन भंडारण तापमान पर वास्तविक समय की जानकारी भी प्रदान करेगा।
- DAHD और UNDP दोनों का लक्ष्य मिलकर देश में पशु स्वास्थ्य और कल्याण प्रबंधन के लिये एक मजबूत, सक्षम और समावेशी ढांचा तैयार करना है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)

- इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1965 में संयुक्त राष्ट्र विस्तारित तकनीकी सहायता कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष के साथ विलय करके की गई।
- मुख्यालय: न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका)
- यह संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है, जो सदस्य देशों को उनकी विकास चुनौतियों का समाधान खोजने में मदद करता है।
- वर्तमान में यूएनडीपी का कार्य इन तीन मुख्य क्षेत्रों पर है:
 - ◆ सतत विकास
 - ◆ लोकतांत्रिक शासन और शांति निर्माण
 - ◆ जलवायु और आपदा लचीलापन

46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक (ATCM)

- 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक (Antarctic Treaty Consultative Meeting: ATCM) और पर्यावरण संरक्षण समिति (Committee for Environmental Protection: CEP) की 26वीं बैठक 20 मई को कोच्चि (केरल) में हुई।
- इसका आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अंटार्कटिक संधि सचिवालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR), गोवा द्वारा किया गया।
- ATCM और CEP उच्च स्तरीय वैश्विक वार्षिक बैठकें हैं जो अंटार्कटिक संधि (Antarctic Treaty) के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाती हैं।

अंटार्कटिक संधि

- यह संधि 1959 में हस्ताक्षरित और 1961 में लागू हुई।
- अंटार्कटिक संधि ने अंटार्कटिका को शांतिपूर्ण उद्देश्यों, वैज्ञानिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया है।

10वाँ वर्ल्ड वाटर फोरम

- इसका आयोजन 18-25 मई, 2024 तक इंडोनेशिया के बाली में किया गया।
- इसकी थीम 'साझा समृद्धि के लिए जल' (Water for shared Prosperity) थी।
- वर्ल्ड वाटर फोरम जल के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों को शामिल करने वाली सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सभा है।
- इसकी सह-मेजबानी विश्व जल परिषद और एक मेजबान होस्ट शहर करता है।
- यह फोरम 1997 से प्रत्येक 3 वर्षों में आयोजित किया जाता है।
- वैश्विक जल संकट के समाधान के लिए पहला वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन 1997 में मोरक्को के मराकेश में हुआ।

- इस बैठक के बाद माराकेच घोषणा पत्र (Marrakech Declaration) जारी की गई थी।
- इस फोरम के दौरान विश्व बैंक द्वारा 'साझा समृद्धि के लिए जल' (Water For Shared Prosperity) शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई।

लेखापरीक्षा में सहयोग हेतु भारत और नेपाल में समझौता

- भारत और नेपाल ने लेखापरीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राया ने काठमांडू में इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- इसका उद्देश्य दोनों देशों के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के बीच लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करना है।

5

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इंजन के साथ अग्निबाण SOrTeD लॉन्च हुआ

- अग्निकुल कॉसमॉस प्राइवेट लिमिटेड ने 30 मई, 2024 को भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC)-SHAR के भीतर स्थित अग्निकुल लॉन्च पैड 1 (ALP-1) से अग्निबाण SOrTeD (सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
- अग्निबाण SOrTeD अग्निकुल द्वारा स्थापित 'धनुष' नामक निजी लॉन्चपैड से भारत का पहला लॉन्च है।
- यह अग्निबाण SOrTeD की पहली उड़ान थी, इसे दुनिया के पहले सिंगल-पीस 3D प्रिंटेड सेमी-क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित किया गया।
- अग्निबाण SOrTeD भारत का दूसरा निजी तौर पर विकसित रॉकेट है, जो दुनिया की अग्रणी 3D प्रिंटेड इंजन तकनीक से लैस है।
- अग्निबाण SOrTeD एक सिंगल-स्टेज लॉन्च वाहन के रूप में संचालित होता है, जिसमें अग्निकुल का 'अग्निलेट' इंजन है।
- यह भारत का पहला अर्ध-क्रायोजेनिक इंजन-संचालित रॉकेट लॉन्च भी है।
- इस मिशन का मुख्य उद्देश्य, जो अग्निकुल की पहली उड़ान भी है, एक परीक्षण उड़ान के रूप में काम करना, घरेलू और घरेलू प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना, महत्वपूर्ण उड़ान डेटा इकट्ठा करना और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है।
- यह रॉकेट भारत के निजी अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वदेशी डिजाइन और इंजीनियरिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।

अग्निकुल कॉसमॉस प्राइवेट लिमिटेड

- इसका निर्माता भारतीय एयरोस्पेस है।
- यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास में राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास केंद्र (NCRD) के भीतर स्थित है।
- स्थापना:- 2017
- मुख्यालय:- चेन्नई, तमिलनाडु

DRDO ने रुद्रम-II मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने Su-30 MK-I प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार

करने वाली रुद्रम-II मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया।

- इस उड़ान परीक्षण ने सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया।

रुद्रम-II मिसाइल

- रुद्रम-II स्वदेशी रूप से विकसित, ठोस प्रणोदक, वायु-प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है।
- मिसाइल प्रणाली में विभिन्न DRDO प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित कई अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकें शामिल हैं।
- रुद्रम-II एक ठोस प्रणोदक हवा से प्रक्षेपित मिसाइल है।
- इसे हवा से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- रुद्रम मिसाइल पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी-रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल है।
- इसे SEAD/DEAD (Suppression and Destruction of Enemy Air Defenses) (शत्रु वायु रक्षा का दमन) मिशनों में दुश्मन के ग्राउंड रडार और संचार स्टेशनों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- रुद्रम-II मार्क-1 संस्करण के बाद नवीनतम संस्करण है।
- मार्क-1 संस्करण का परीक्षण 2020 में सुखोई-30 MK-I द्वारा किया गया था।
- रुद्रम-II को कई ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। यह 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी से रडार से सिग्नल प्राप्त कर सकता है।

DRDO

- यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अंतर्गत एक एजेंसी है।
- यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।
- DRDO सैन्य अनुसंधान एवं विकास के लिए जिम्मेदार है।
- स्थापना:- 1958
- वर्तमान अध्यक्ष:- समीर वी. कामत
- मुख्यालय:- नई दिल्ली

पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम 'SMART' का सफल परीक्षण

- भारतीय नौसेना ने 1 मई 2024 को ओडिशा में बालासोर तट (एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप) से सुपरसोनिक मिसाइल टॉरपीडो (SMART) प्रणाली सफल परीक्षण किया है।
- यह परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने भारतीय नौसेना के लिए किया था।

- SMART का पूरा नाम Supersonic Missile Assisted Release of Torpedo है।
- यह अगली पीढ़ी का पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम है, जो लाइटवेट टॉरपीडो डिलीवरी सिस्टम पर आधारित है।
- इसे DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- यह मिसाइल लंबी दूरी के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है तथा इसे वॉरशिप के साथ ही तटीय इलाकों से भी लॉन्च किया जा सकता है।
- कैनिसटर आधारित इस मिसाइल सिस्टम में कई आधुनिक सब-सिस्टम हैं, जिनमें दो चरणीय सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टुएटर सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम आदि शामिल हैं।

ISRO का सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण

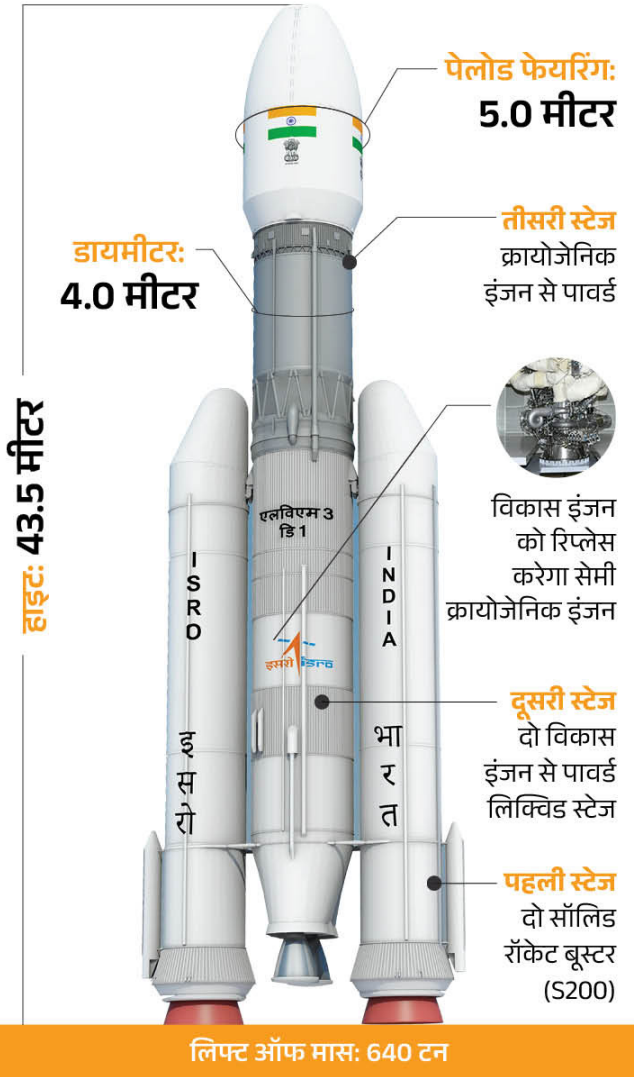
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 6 मई 2024 को सेमी क्रायोजेनिक इंजन के डेवलपमेंट में एक और टेस्ट पास कर लिया है।
- सेमी क्रायोजेनिक इंजन को स्टार्ट करने के लिए प्रीबर्नर को इगनाइट करने का परीक्षण सफल रहा।
- ये इंजन ISRO के LVM3 रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेगा।
- भारत ने अपना चंद्रयान-3 मिशन LVM3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया था।
- चंद्रयान-4 मिशन में भी इसी रॉकेट का इस्तेमाल होगा।
- ISRO का सेमी क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड ऑक्सीजन (LOX) और केरोसीन के कॉम्बिनेशन पर काम करता है और 2,000kN का थ्रस्ट जनरेट करता है।
- इसमें ट्राइथाइल एल्युमनाइड और ट्राइथाइल बोरोन के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है।
- सेमी क्रायोजेनिक इंजन LVM3 रॉकेट की सेकेंड स्टेज में लगे विकास इंजन को रिप्लेस करेगा।

ISRO ने नए तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा एडिटिव मैनुफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से निर्मित नए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
- तमिलनाडु के महेंद्रगिरि में 9 मई 2024 को इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
- इससे प्रति इंजन कच्चे माल के उपयोग में महत्वपूर्ण बचत होगी, धातु पाउडर 565 किलोग्राम से घटकर 13.7 किलोग्राम हो जाएगा और उत्पादन समय 60% कम हो जाएगा।
- इस नए, रीडिजाइन किए गए इंजन का उपयोग PSLV प्रथम चरण प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली और PSLV प्रक्षेपण यान के चौथे चरण दोनों में किया जाएगा।
- इसरो इस PS4 इंजन को नियमित पीएसएलवी कार्यक्रम में शामिल करने की योजना बना रहा है।
- एडिटिव मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का तात्पर्य PS4 इंजन की 3D प्रिंटिंग से है।
- यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उन्नत 3D विनिर्माण प्रौद्योगिकी के एक नए युग की शुरुआत करेगा।



LVM3 रॉकेट को पावरफुल बनाएगा सेमी क्रायोजेनिक इंजन



BHISHM पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण

- हाल ही में आगरा में **BHISHM** पोर्टेबल अस्पताल का भारतीय वायु सेना द्वारा 14 मई 2024 को विमान से एयरड्रॉप के लिए परीक्षण किया।
- यह परीक्षण आपात स्थिति से निपटने के लिए पोर्टेबल अस्पताल को कहीं भी तैनात करने हेतु किया गया।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स 'प्रोजेक्ट भीष्म' नामक व्यापक पहल का हिस्सा हैं।
- BHISHM पूरा नाम: Bharat Health Initiative for Sahyog, Hita and Maitri** (सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल)
- इसे 200 घायलों के इलाज के लिए तैयार किया गया है, जिसमें त्वरित प्रतिक्रिया और व्यापक देखभाल पर जोर दिया गया है।
- इन क्यूब्स को आपात स्थिति के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी समन्वय, वास्तविक समय की निगरानी और कुशल प्रबंधन की सुविधा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स को भी एकीकृत करता है।
- इस पूरी इकाई में 72 आसानी से परिवहन योग्य घटक होते हैं जिन्हें आसानी से हाथ, साइकिल या यहां तक कि ड्रोन द्वारा ले जाया जा सकता है।
- इसमें आवश्यक बुनियादी सहायता से लेकर उन्नत चिकित्सा और शल्य चिकित्सा देखभाल की सुविधा है।
- यह 12 मिनट के भीतर तैनात होने की क्षमता रखता है।
- ये क्यूब्स मजबूत, जलरोधक और हल्के हैं, जिन्हें विभिन्न विन्यासों के लिए डिजाइन किया गया है, जो इन्हें विविध आपातकालीन स्थितियों के अनुकूल बनाता है।

देश का पहला लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन (Loitering Aerial Munitions: LAM) विकसित किया गया

- कैडेट डिफेंस सिस्टम्स ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (DRDO) के सहयोग से सशस्त्र बलों के लिए देश का पहला लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन (Loitering Aerial Munitions: LAM) विकसित किया है।
- LAM की रेंज रॉकेट-सहायता कनस्तर लॉन्च और रनवे स्वतंत्र हाइब्रिड वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (VTOL) प्रणाली के साथ 150 किमी से 300 किमी तक है।
- कामिकेज ड्रोन (Kamikaze drones) - जिसे लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन या आत्मघाती ड्रोन के रूप में भी जाना जाता है।

- यह सटीक मिसाइलों और मानव रहित हवाई प्रणालियों (UAS) के समान हैं।
- पारम्परिक मिसाइलों के विपरीत, कामिकेज ड्रोन किसी लक्ष्य पर हमला करने से पहले अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने में सक्षम है जिसे लोइटरिंग के रूप में जाना जाता है।
- इन प्रणालियों में एक अंतर्निर्मित वारहेड या पेलोड की सुविधा भी हो सकती है, जिसका उद्देश्य युद्ध के दौरान विस्फोट करना है।
- हालाँकि LAM में सटीक मिसाइलों की तुलना में छोटे हथियार होते हैं, वे अपने छोटे आकार और उड़ान कौशल के कारण रडार से बच निकलने में सक्षम होते हैं।

भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान

- फ्लाइंग वेज डिफेंस ने **FWD -200B नामक मानवरहित विमान** लॉन्च किया है।
- फ्लाइंग वेज डिफेंस एक रक्षा और एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म है।
- यह भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान है।
- स्वदेशी FWD-200B की कीमत मात्र 25 करोड़ रुपये है। यू.एस. प्रीडेटर की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपये है।
- FWD-200B की पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी स्थिरता क्षमता 12-20 घंटे है।
- यह 200 किलोमीटर की ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन (GCS) रेंज रखता है।

चीन द्वारा 'चांग ई-6 (Chang'e-6)' मिशन लॉन्च

- चीन ने 3 मई 2024 को अपने चंद्र रिसर्च मिशन के लिए अपना अंतरिक्ष यान 'चांग ई-6' (Chang'e 6) को लॉन्च किया है।
- यह प्रक्षेपण रॉकेट 'लांग मार्च-5 Y8' के माध्यम से किया गया है।
- इस मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव-एटकेन बेसिन नमूना एकत्र करने और फिर पृथ्वी पर वापस लाने का काम सौंपा गया है।
- चांग ई-6, चंद्रमा पर पहुंचने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग के 48 घंटों के भीतर चंद्रमा की सतह से चट्टानों और मिट्टी को निकालने के लिए रोबोटिक हाथ बढ़ाया जाएगा, जबकि जमीन में छेद करने के लिए ड्रिल का इस्तेमाल किया जाएगा।
- चांग ई-6 मिशन का प्राथमिक लक्ष्य लैंडिंग और नमूना (सैंपल) एकत्र करना है।
- यदि यह मिशन अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होता है, तो चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो चाँद के उस हिस्से से नमूना लाने में कामयाब होगा जिसे पृथ्वी से कभी देखा ही नहीं जा सकता है।

- भारत, अगस्त 2023 में अपने चंद्रयान-3 मिशन के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना था।
- चांग ई 6 मिशन में पाकिस्तान द्वारा विकसित आईक्यूब-कमर ('ICube Qamar') उपग्रह भी है।
- इस लघु उपग्रह में दो ऑप्टिकल कैमरे हैं जो चंद्रमा की सतह की तस्वीरें ले सकते हैं।
- आईक्यूब-कमर ('ICube Qamar') पाकिस्तान का पहला चंद्र मिशन है।
- पाकिस्तान के क्यूबसैट सैटेलाइट आईक्यूब-कमर को चीन की शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी SUPARCO के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (IST) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- **नोट:** चीन का चांग ई-4 ने 2018 में चंद्रमा पर पहली मानवरहित लैंडिंग थी।
- **नोट:** चांग ई-5 ने 2020 में चंद्रमा से नमूने प्राप्त किए।

नासा ने चाँद पर पहली रेलवे प्रणाली विकसित करने की योजना पेश की

- नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने चाँद पर रोबोट ट्रेन बनाने की अपनी योजना की पेश की है।
- इस प्रणाली को FLOAT नाम दिया गया है।
- **FLOAT पूरा नाम:** Flexible Levitation on a Track.
- नासा चाँद पर विश्वसनीय, स्वायत्त और कुशल परिवहन प्रदान करने वाली पहली लूनर रेलवे प्रणाली बनाएगी।
- नासा FLOAT परियोजना के तहत बिना बिजली वाले चुंबकीय रोबोट का उपयोग करेगा।
- ये रोबोट चंद्र सतह की धूल से घर्षण को रोकने के लिए तीन-परत वाले लचीले फिल्म ट्रैक को ऊपर उठाएंगे।
- ग्रेफाइट परत रोबोट को निष्क्रिय रूप से डायमैग्नेटिक लेविटेशन का उपयोग करके पटरियों पर तैरने देगी।
- फ्लेक्स-सर्किट परत रोबोट को नियंत्रित रूप से पटरियों के साथ आगे बढ़ाने के लिए विद्युत चुम्बकीय जोर उत्पन्न करती है।
- इन रोबोटों का उपयोग नासा के चंद्र बेस तक लगभग 100 टन निर्माण सामग्री ले जाने और लाने के लिए किया जाएगा।

नासा द्वारा PREFIRE मिशन लॉन्च किया

- नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने 22 मई को ध्रुवों से ऊष्मा के उत्सर्जन की स्टडी के लिए PREFIRE मिशन लॉन्च किया।
- PREFIRE पूरा नाम: Polar Radiant Energy in the Far-Infrared Experiment

- इसे न्यूजीलैंड के माहिया से रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया गया।
- इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों का अध्ययन करना है।
- यह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से अंतरिक्ष में उत्सर्जित होने वाली गर्मी की मात्रा की जाँच करेगा और इसके जलवायु को प्रभावित करने के कारकों का विश्लेषण करेगा।
- पृथ्वी की सतह से निकलने वाली सुदूर अवरक्त ऊर्जा को मापने के लिए एक थर्मल इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर भी इस मिशन का हिस्सा है।
- इसके तहत शू बॉक्स के आकार के दो क्यूब सैटेलाइट्स यानी क्यूबसैट लॉन्च किए जाएंगे।
- इसका दूसरा उपग्रह कुछ समय बाद लॉन्च किया जाएगा।
- इसमें एक सैटेलाइट का नाम 'रेडी, एम, प्रीफायर (Ready, Aim, PREFIRE)' और दूसरा क्यूबसैट, 'प्रीफायर और आईसीई (PREFIRE and ICE)' है।
- यह पृथ्वी के दो सबसे ठंडे क्षेत्र; यानी आर्कटिक और अंटार्कटिका में अध्ययन करेगा कि इन क्षेत्रों से कितनी ऊष्मा अंतरिक्ष में उत्सर्जित होती है और ये पृथ्वी की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं।
- इसे नासा और विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय (USA) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- शोधकर्ता इस मिशन से **पृथ्वी के ऊर्जा बजट (Earth's energy budget)** को समझना चाहते हैं।
- यह सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊष्मा की मात्रा और पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली ऊष्मा की मात्रा के बीच संतुलन है।
- दोनों के बीच का अंतर पृथ्वी के तापमान और जलवायु को निर्धारित करता है।
- **नोट:** आर्कटिक और अंटार्कटिका से निकलने वाली ऊष्मा की एक बड़ी मात्रा फार-इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में उत्सर्जित होती है।
- PREFIRE मिशन इस मामले में हमारे ज्ञान को बढ़ाएगा। इसके दो क्यूबसैट पृथ्वी के ध्रुवों से फार-इंफ्रारेड रेडिएशन का अध्ययन कर सकते हैं

यूरोपियन स्पेस एजेंसी और 12 देशों ने जीरो डेब्रिज चार्टर पर हस्ताक्षर किए

- 12 देशों और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 23 मई, 2024 को जीरो डेब्रिज चार्टर (Zero Debris Charter) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- जीरो डेब्रिज चार्टर 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा तटस्थ यानी डेब्रीज न्यूट्रल (मलबे में कोई वृद्धि नहीं) बनाने का एक प्रयास है।
- यह पहली बार है जब विश्व के कुछ देशों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसमें शामिल हुए हैं।

- ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम सभी चार्टर का पालन करने पर सहमत है।
- यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अनुमान है कि वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में एक सेमी से बड़े आकार के दस लाख से अधिक अंतरिक्ष मलबे के टुकड़े मौजूद हैं।
- इनमें से प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स अंतरिक्ष में लॉन्च किये गए उपग्रहों आदि को क्षति पहुंचा सकते हैं।

55 कैनक्री ई (55 Cancri e) के आसपास वायुमंडलीय गैसों का पता लगाया गया

- नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से शोधकर्ताओं ने पृथ्वी से 41 प्रकाश वर्ष दूर एक गर्म चट्टानी ग्रह एक्सोप्लैनेट 55 कैनक्री ई (55 Cancri e) के आसपास वायुमंडलीय गैसों का पता लगाया है।
- यह हमारे सौर मंडल के बाहर किसी चट्टानी ग्रह के वातावरण के जीवन के अस्तित्व का अब तक का सबसे अच्छा संभावित सबूत है।
- 55 कैनक्री ई को जैनसेन के नाम से भी जाना जाता है, यह कर्क राशि में सूर्य जैसे तारे 55 कैनक्री की परिक्रमा करने वाले 5 ज्ञात ग्रहों में से एक है।
- यह पृथ्वी से लगभग दोगुना व्यास और थोड़ा अधिक घनत्व वाला है। इस ग्रह को सुपर-अर्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **नोट:** पृथ्वी से बड़ा और नेपच्यून से छोटे चट्टानी ग्रहों को सुपर अर्थ (Super-Earth) कहा जाता है।
- 55 कैनक्री ई या जानसेन नामक ग्रह पृथ्वी से लगभग 8.8 गुना अधिक विशाल है।
- यह ग्रह संभवतः टाइडली लॉक्ड (Tidally Locked) है, जिसका अर्थ है कि इसका एक साइड हमेशा इसके सूर्य की ओर रहता है, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा का एक साइड हमेशा पृथ्वी की ओर होता है।
- **नोट:** एक्सोप्लैनेट (Exoplanet) हमारे सौर मंडल से बाहर ऐसा कोई भी ग्रह है जो किसी अन्य सूर्य का परिक्रमा करता है।

चट्टानी (Terrestrial) या पार्थिव ग्रह

- हमारे सौर मंडल में, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र पार्थिव (Terrestrial) या चट्टानी ग्रह हैं।
- इन्हें पार्थिव (terrestrial) या चट्टानी कहा जाता है क्योंकि इनकी सतह पृथ्वी की टेरा फर्मा की तरह सघन होती है।
- पार्थिव ग्रह सौरमंडल के चार सबसे भीतरी (इनरमोस्ट) ग्रह हैं। किसी भी पार्थिव ग्रह में वलय या रिंग नहीं हैं।
- पार्थिव ग्रहों में केवल पृथ्वी के पास ही पर्याप्त ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र है।

चीन द्वारा पाकिस्तान हेतु पहली हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी लॉन्च

- हाल ही में चीन ने पाकिस्तान के लिये तैयार की जा रही 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली पनडुब्बी को चीन के वुहान शिपयार्ड में लॉन्च किया।
- इस श्रेणी की आठ पनडुब्बियों में से पहली पनडुब्बी को पाकिस्तानी नौसेना 2028 तक अपने बेड़े में शामिल कर सकती है।
- यह एक डीजल-इलेक्ट्रिक कॉम्बैट सबमरीन है।
- हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों से बड़ी है, जिसमें कलवरी श्रेणी के 1,775 टन की तुलना में 2,800 टन का डिस्प्लेसमेंट है।
- हैंगर क्लास में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) है।
- यदि कोई पनडुब्बी 'AIP सिस्टम' से लैस है, तो पनडुब्बी को सप्ताह में केवल एक बार ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होगी। AIP पनडुब्बियों को लंबे समय तक जलमग्न में रहने की अनुमति देता है।
- AIP को वर्ष 2024 में पहली स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी INS कलवरी पर स्थापित करने की योजना है।

रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती का अभ्यास करने की घोषणा की

- हाल ही में, रूस ने फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से खतरे को देखते हुए मिलिट्री के हिस्से के रूप में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन (Tactical nuclear weapons) की तैनाती का अभ्यास करने की घोषणा की है।
- **नोट:** 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से, रूस ने अन्य देशों के शामिल होने की आशंका से बढ़ते परमाणु खतरों की चेतावनी दी है।
- रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका अब तक दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियाँ हैं, जिनके पास दुनिया के 12,100 परमाणु हथियारों में से 10,600 से अधिक हथियार हैं।

टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन

- टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को नॉन स्ट्रेटेजिक वेपन भी कहा जाता है।
- टैक्टिकल (नॉन स्ट्रेटेजिक) परमाणु हथियार (TNWs) आमतौर पर कम दूरी के हथियारों को कहते हैं, जिसमें 500 किमी से कम दूरी पर मार करने वाली भूमि आधारित मिसाइलें और 600 किमी से कम की सीमा के साथ हवा और समुद्र से प्रक्षेपित हथियार शामिल हैं।

- परमाणु हथियार-युक्त अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (जो पूरे शहरों को नष्ट कर सकती हैं) के विपरीत टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कम शक्तिशाली होते हैं और युद्ध के मैदान में सैनिकों के खिलाफ उपयोग के लिए होती हैं।
- इनकी क्षमता लगभग 1 किलोटन जितनी कम हो सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराया गया अमेरिकी बम 15 किलोटन का था।
- स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन रूस और अमेरिका के बीच हथियार नियंत्रण समझौतों के अधीन हैं लेकिन टैक्टिकल वेपन कभी भी ऐसे किसी समझौतों का हिस्सा नहीं रही हैं।

जापान और अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल हेतु इंटरसेप्टर विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए

- इस समझौते के तहत दोनों देश 2030 तक इंटरसेप्टर विकसित करने की योजना बना रहे हैं।
- इस योजना पर 3 अरब डॉलर से अधिक की लागत आएगी। इसकी पहली बार घोषणा अगस्त में की गई थी।
- इंटरसेप्टर को ग्लाइड फेज इंटरसेप्टर (GPI) कहा जाता है।
- जापान ने 2024 के बजट में इंटरसेप्टर के विकास के लिए 480 मिलियन डॉलर शामिल किए हैं।
- हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना मुश्किल होता है। वे ध्वनि की गति से पांच गुना अधिक गति से उड़ते हैं। उनके प्रक्षेप पथ अनियमित होते हैं।

पहले भारत-निर्मित सेमीकंडक्टर चिप 2025 में लॉन्च होगा

- पहले भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन 2025 में गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की पैकेजिंग इकाई से किया जाएगा।
- साणंद में बने अधिकांश चिप का निर्यात किया जाएगा, इससे भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में प्रमुख बन सकेगा।
- सेमीकंडक्टर चिप्स का उपयोग डेटा सेंटर, स्मार्टफोन, नोटबुक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों के लिए किया जाएगा।

पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन माइक्रोकंट्रोलर चिप लॉन्च

- आईआईटी मद्रास-इनक्यूबेटेड स्टार्टअप माइंडगोव टेक्नोलॉजीज ने देश का पहला वाणिज्यिक, उच्च-प्रदर्शन SoC (चिप पर सिस्टम) लॉन्च किया है।
- इसका 'सिक्वोर आईओटी' नाम है।
- माइंडगोव टेक्नोलॉजीज को ताइवान से अपने पहले सिस्टम-ऑन-चिप - सिक्वोर आईओटी - का शिपमेंट प्राप्त हुआ है।

- सिस्टम-ऑन-चिप का उपयोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) में किया जाता है और यह डिवाइस के मस्तिष्क की तरह होता है।

3D-प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट

- IIT गुवाहाटी ने एक 3D-प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित की है।
- इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों, मुख्य रूप से पहली बार मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान प्रक्रिया के बारे में सूचित करना है।
- यह डमी मतपत्र इकाई 3D प्रिंटिंग तकनीक और मकई स्टार्च से प्राप्त बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी।
- इसे IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने महज 48 घंटों में बनाया।

दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल

- मेक्सिको के शोधकर्ताओं ने ताम जा' ब्लू होल (TJBH) नाम की यह साइट अब विश्व में सबसे गहरा ज्ञात पानी के नीचे का सिंकहोल है।
- ताम जा' ब्लू होल (Taam Ja' Blue Hole: TJBH), जो मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी तट पर चेतुमल खाड़ी (Chetumal Bay) में स्थित है, समुद्र तल से कम से कम 1,380 फीट (420 मीटर) नीचे तक विस्तृत है।
- ब्लू होल पानी से भरी वर्टिकल गुफाएँ या सिंकहोल हैं, जो ऐसे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ का आधार चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसे घुलनशील सामग्री से बनी होती है।
- विश्व के अन्य प्रसिद्ध ब्लू होल: बहामास में डीन का ब्लू होल, मिस्र में दहाब ब्लू होल और बेलीज में ग्रेट ब्लू होल।

HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण

- संयुक्त राज्य अमेरिका के ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किया।
- शोधकर्ताओं को पहली बार टीकाकरण के माध्यम से एचआइवी के खिलाफ शरीर में मौजूद एंटीबॉडी को सक्रिय करने में सफलता मिली।
- जर्नल सेल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन कोशिका के बाहरी क्षेत्र को लक्षित करती है। वायरस इसी क्षेत्र में सबसे पहले हमला करता है। एंटीबॉडी एचआइवी संक्रमण रोकता है।
- यह एचआइवी के शोध की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- इस वैक्सीन के साथ एंटीबॉडी सक्रिय होती है, जो एचआइवी को रोकने में सक्षम है।

- इसके परीक्षण के दौरान HIV निगेटिव 20 व्यक्तियों को टीके की दो से तीन खुराक दी गई।
- इस टीके को डॉ. एस. मुनील आलम और हेन्स ने विकसित किया है।
- दो खुराक के बाद 95% सीरम और 100% सीडी4 टी-सेल ने प्रतिक्रिया शुरू कर दी। इससे संकेत मिलता है कि इससे मजबूत प्रतिरक्षा शुरू हो गई है।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर में मोटे तौर पर निष्क्रिय रहने वाले एंटीबॉडी ने प्रारंभिक खुराक के कुछ हफ्तों में ही काम करना शुरू कर दिया था। इस प्रतिक्रिया में आम तौर पर कई साल लग जाते हैं।

HIV

- Full Form: Human immunodeficiency viruses.
- यह ऐसा संक्रमण है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। एक्वायर्ड इम्युनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (एड्स) बीमारी का सबसे उन्नत चरण है।
- HIV शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाओं को निशाना बनाता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है।
- इससे तपेदिक, संक्रमण और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों से बीमार होना आसान हो जाता है।
- HIV संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ से फैलता है, जिसमें रक्त, स्तन का दूध और वीर्य शामिल हैं।
- एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) से एचआईवी के प्रारंभिक चरणों में इलाज और रोकथाम किया जा सकता है।
- WHO अब उन्नत एचआईवी रोग (AHD) को वयस्कों और किशोरों में 200 सेल्स/मिमी³ या WHO चरण 3 या 4 से कम CD 4 सेल गिनती के रूप में परिभाषित करता है।
- HIV एक प्रमुख वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है।
- इससे वैश्विक स्तर पर अब तक लगभग 40.4 मिलियन लोगों की मौत हुई है।
- 2022 के अंत में अनुमानित 39.0 मिलियन लोग एचआईवी से पीड़ित थे, जिनमें से दो तिहाई (25.6 मिलियन) अफ्रीकी क्षेत्र में हैं।

लक्षण

- इसका संक्रमण धीरे-धीरे प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है।
- प्रमुख लक्षण:
 - सूजी हुई लसीका ग्रंथियां
 - वजन घटना
 - बुखार
 - दस्त
 - खाँसी।

‘फेरोइलेक्ट्रिक डायोड’

- यह सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है जो 600 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी काम करने में सक्षम है।
- इसकी सहायता से कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली चिप उच्च तापमान झेलने में सक्षम है।
- नेचर जर्नल में छपे शोध के अनुसार ‘फेरोइलेक्ट्रिक डायोड’ का उपयोग करने वाले संसर व कंप्यूटिंग डिवाइस न्यूक्लियर प्लांट, जमीन की गहराई में तेल-गैस की खोज के दौरान या सबसे गर्म ग्रह शुक्र पर भी काम कर सकता है।
- इस कंप्यूटिंग डिवाइस को बनाने में फेरोइलेक्ट्रिक एल्यूमीनियम स्कैंडियम नाइट्राइड नाम के मैटेरियल का इस्तेमाल किया गया।
- यह डिवाइस दुर्गम स्थलों और विषम परिस्थितियों में भी एडवांस कंप्यूटिंग का संचालन कर सकता है।
- इससे नॉन-सिलिकॉन कंप्यूटिंग डिवाइस का नया युग शुरू हो सकता है।

विश्व की पहली ‘हेड ट्रांसप्लांट प्रणाली’

- संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूरोसाइंस व बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट-अप ब्रेनब्रिज ने विश्व की पहली ‘हेड ट्रांसप्लांट प्रणाली’ की परिकल्पना साझा की।
- यह अवधारणा दुबई स्थित प्रोजेक्ट लीडर बायोटेक्नोलॉजिस्ट हाशेम अल-घैली के दिमाग की उपज है।
- इसके तहत रोबोटिक प्रणाली एक कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से एक सिर को दूसरे के धड़ पर बदलने से पहले डोनर और प्राप्तकर्ता के शरीर से सिर को एक साथ हटा देती है।
- इसके बाद में बिना इंसानी दखल के रोबोटिक टूल्स और लेजर की एक विशाल श्रृंखला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (A.I.) से ऐसे प्रत्यारोपण कर सकते हैं।
- यह सिस्टम कैंसर, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी न्यूरो-डीजेनेरेटिव बीमारियों और पक्षाघात जैसी अनुपचारित स्थितियों से पीड़ित रोगियों के लिए सहायक हो सकता है।

6

खेल

श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंडमास्टर बने

- पी श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं।
- उन्होंने 12 मई को दुबई पुलिस मास्टर्स 2024 में जीएम जिंशी बाई (CHN) के साथ ड्रॉ खेलकर यह उपलब्धि हासिल की।

वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंडमास्टर बनी

- अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) ने 2 मई को भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंडमास्टर की उपाधि से सम्मानित किया।
- कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंडमास्टर हैं।
- विश्वनाथन आनंद शतरंज ग्रैंडमास्टर बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं
- कोनेरू हम्पी ग्रैंडमास्टर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है।
- सबसे कम उम्र के भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर आर. प्रगानंद हैं।
- वैशाली उनके भाई आर. प्रगानंद, दुनिया के पहले ग्रैंडमास्टर भाई-बहन की जोड़ी बन गए हैं।
- सबसे अधिक ग्रैंडमास्टर खिताब हासिल करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु है।

अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (Federation Internationale des Échecs - FIDE)

- शतरंज के खेल का गवर्निंग बॉडी है और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करती है।
- इसकी शुरुआत साल 1924 में पेरिस से की गई थी।
- इसे वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी।
- इसका हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड में है।

- इसके प्रेसिडेंट अर्कडी ड्वोर्कोविच और वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद हैं।

नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया

- भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया।
- उन्होंने 88.36 मीटर दूरी तक भाला फेंका।
- जैकब वडलेज पहले स्थान पर रहे उन्होंने 88.38 मीटर का थ्रो किया था।

नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता

- नीरज चोपड़ा ने 15 मई 2024 को भुवनेश्वर में 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता।
- उन्होंने 82.27 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

नीरज चोपड़ा की उपलब्धियाँ

- टोक्यो ओलंपिक (2020) में स्वर्ण पदक
- डायमंड लीग (2022) चैंपियन
- विश्व चैंपियनशिप (2023) में स्वर्ण पदक
- एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक

11वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024

- आयोजन: 17 मई से 25 मई 2024 तक।
- स्थान: कोबे (जापान)
- भारत पदक तालिका में छठे स्थान पर रहा जबकि चीन पहले स्थान पर रहा।
- **भारत के कुल पदक**
- भारत के कुल पदक: 17 (6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक)

पदक विजेता

• दीप्ति जीवनजी	महिलाओं की 400 मीटर T-20 स्पर्धा	स्वर्ण पदक
• एकता भ्यान	महिलाओं के F51 स्पर्धा थ्रो	स्वर्ण पदक
• थंगावेलू मरियप्पन	पुरुषों की उंची कूद T63 श्रेणी	स्वर्ण पदक
• सुमित अंतिल	पुरुषों के F64 श्रेणी में भाला फेंक	स्वर्ण पदक
• सिमरन शर्मा	महिलाओं की 200 मीटर T12 श्रेणी	स्वर्ण पदक
• सचिन सरजेराव खिलारी	पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा	स्वर्ण पदक
• रिंकू	रजत पदक	पुरुषों के F46 श्रेणी में भाला फेंक
• कशिश लाकड़ा	महिलाओं के F51 स्पर्धा थ्रो	रजत पदक

• योगेश कथूनिया	पुरुषों के F56 डिस्कस थ्रो	रजत पदक
• भाग्यश्री महाराव	महिलाओं की शॉटपुट F34 स्पर्धा	रजत पदक
• निषाद कुमार	पुरुषों के T47 ऊंची कूद	रजत पदक
• धरमबीर	पुरुषों के F51 श्रेणी में थ्रो स्पर्धा	कांस्य पदक
• अजीत सिंह	पुरुषों के F46 श्रेणी में भाला फेंक	कांस्य पदक
• संदीप	कांस्य पदक	पुरुषों के F64 श्रेणी में भाला फेंक
• प्रीति पाल	महिलाओं के T35 200 मीटर	कांस्य पदक
• प्रीति पाल	महिलाओं के T35 100 मीटर	कांस्य पदक
• नवदीप	पुरुषों की भाला फेंक F41 श्रेणी	कांस्य पदक

- नोट: T20 वर्ग की रेस बौद्धिक रूप से अक्षम खिलाड़ियों के लिए है।
- नोट: T35 में वो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जिन्हें समन्वय संबंधित विकृति होती है।
- नोट: दीप्ति ने हांगझाउ पैरा एशियाई खेलों में 400 मीटर T20 वर्ग में 56.69 सेकंड के एशियाई रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता था।
- निषाद कुमार टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में रजत पदक विजेता रहे थे।
- निषाद ने पेरिस में 2023 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीता था।

दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप पहला स्वर्ण पदक जीता

- दीपा कर्माकर ने ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता।
- उत्तर कोरियाई जिम्नास्ट किम सोन ह्यांग और जो क्योंग ब्योल ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते।
- पहली बार किसी भारतीय जिम्नास्ट ने एशियन चैंपियनशिप में किसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।

दीपा कर्माकर की उपलब्धियाँ

- FIG विश्व कप (2018) में स्वर्ण पदक
- 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स कांस्य पदक
- ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट।
- 2016 रियो ओलंपिक में वॉल्ट स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं।

एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024

- आयोजन: 11-12 मई 2010
- स्थान: हांगकांग (चीन)
- भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता।
- भारत की सृष्टि खंडागले एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय है।

- इसमें कजाकिस्तान की डोलगोपोलोवा ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि हांगकांग की एस हंग ने कांस्य पदक जीता।

थाइलैंड ओपन 2024

- आयोजन: 14-19 मई 2024 तक।
- स्थान: बैंकॉक (थाइलैंड)
- सात्विक साईराज रंकीरेडुी और चिराग शेट्टी ने थाइलैंड ओपन 2024 में पुरुष युगल खिताब जीता।
- सात्विक और चिराग ने अपने पहले सुपरसीरीज/सुपर 500 स्तर का खिताब 2019 में जीता था।
- मार्च 2024 में फ्रेंच ओपन जीतने के बाद यह सात्विक और चिराग का 2024 का दूसरा खिताब है।

एलोर्डा कप 2024

- स्थान: अस्ताना (कजाखिस्तान)।
- भारत ने कुल 12 पदक जीते। (2 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य पदक)
- भारत की मुक्केबाज निकहत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता।
- भारतीय मुक्केबाज मिनाक्षी ने 48 किग्रा वर्ग में भी इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।
- निकहत ने महिलाओं के 52 किग्रा वर्ग में कजाखिस्तान की जजीरा उरकबायेवा को हराया।
- अनामिका ने 50 किग्रा वर्ग और मनीषा ने 60 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीते।

प्रीतिस्मिता भोई

- प्रीतिस्मिता ने लीमा (पेरू) में विश्व युवा चैंपियनशिप में महिलाओं के 40 किग्रा में खिताब जीता।
- क्लीन एंड जर्क विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक बनी हैं।
- प्रीतिस्मिता ने स्नैच में 57 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 76 किग्रा वजन उठाया।
- उन्होंने कुल 133 किग्रा के साथ महिलाओं के 40 किग्रा का ताज जीता।
- उन्होंने अपने स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल प्रदर्शन के लिए तीन स्वर्ण पदक जीते।

एशियाई रिले चौपियनशिप में भारतीय टीम ने रजत पदक जीते

- थाईलैंड के बैंकॉक में खेले जा रहे एशियाई रिले चौपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला रिले टीमों ने 4 गुणा 400 मीटर में दो रजत पदक जीते।
- मुहम्मद अनस याहिया, टी संतोष कुमार, मिजो चाको कुरियन और राजीव अरोकिया की पुरुष रिले टीम ने रजत पदक जीता।
- महिला वर्ग में भारत की विथ्या रामराज, एम. आर. पूवम्मा, रूपल और प्राची चौधरी ने रजत पदक जीता।

तीरंदाजी विश्व कप चरण 2

- भारत ने दक्षिण कोरिया के येचिओन में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में कंपाउंड महिला टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
- ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति स्वामी टीम स्वर्ण पदक जीता
- इस जोड़ी ने लगातार तीसरा विश्व कप स्वर्ण पदक जीता है।
- विश्व तीरंदाजी महासंघ द्वारा 2006 में शुरू किए गए तीरंदाजी विश्व कप में विभिन्न देशों में चार चरण होते हैं।
- तीरंदाज विश्व स्तर पर चार चरणों में प्रतिस्पर्धा करते हैं, शीर्ष आठ (2006-09 के दौरान चार) तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में आगे बढ़ते हैं।
- जहाँ प्रत्येक श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज अंतिम खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

मनिका बत्रा

- भारत की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा विश्व महिला एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है।
- उन्होंने एकल टेबल टेनिस में किसी भारतीय द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रैंक के लिए जी. सत्यन के पांच साल पुराने रिकॉर्ड की भी बराबरी की।
- मनिका बत्रा ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत और टीम श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता था।
- उन्हें 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया।

सुनील छेत्री

- सुनील छेत्री ने 6 जून को कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालीफायर मैच के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की।
- उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 145 मैच खेले और प्रभावशाली 94 गोल किए।
- वह सैफ चैम्पियनशिप (2011, 2015, 2021) और नेहरू कप (2007, 2009, 2012) में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।

- उन्होंने भारत को 2008 एएफसी चैलेंज कप जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भारतीय राष्ट्रीय टीम में सबसे अधिक कैप और सबसे अधिक कुल गोल के साथ, वह सक्रिय खिलाड़ियों के बीच अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में लियोनेल मेस्सी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद तीसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं।
- उन्हें वर्ष 2019 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री पुरस्कार और 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- वह 2021 में भारत का शीर्ष खेल सम्मान, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं।

आभा खटुआ ने गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया

- आभा खटुआ ने महिलाओं की गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है।
- उन्होंने यह कीर्तिमान भुवनेश्वर में नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में 13 मई को 18.41 मीटर गोला फेंक कर बनाया।

17वाँ इंडियन प्रीमियर लीग 2024

- इसका खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने 26 मई 2024 को फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर जीता।
- यह कोलकाता नाइट राइडर्स का तीसरा खिताब है। इससे पहले केकेआर ने 2012 और 2014 में इस ट्रॉफी को जीता था।

IPL 2024 के पुरस्कार विजेता

- ऑरेंज कैप (सीजन में सबसे ज्यादा रन) - विराट कोहली (741 रन)
- पर्पल कैप (सीजन में सबसे ज्यादा विकेट) - हर्षल पटेल (24 विकेट)
- सीजन के उभरते खिलाड़ी - नितीश कुमार रेड्डी
- सबसे मूल्यवान खिलाड़ी - सुनील नरेन
- फेयर प्ले अवार्ड - सनराइजर्स हैदराबाद

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL):

- यह भारत में शीर्ष घरेलू क्लब-आधारित पेशेवर क्रिकेट लीग है।
- यह T-20 प्रारूप (20-20 ओवर) में खेला जाता है।
- इसकी शुरुआत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2008 में की थी।
- मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग ने IPL का सर्वाधिक बार खिताब जीता (5-5 बार) है।

एशियाई आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024

- भारतीय आर्म रेसलरों ने ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में एशियाई चैम्पियनशिप 2024 में 7 पदक जीते
- इसमें 1 स्वर्ण और 6 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते।
- **श्रीमंत झा:** बाएं हाथ के पैरा वर्ग में स्वर्ण पदक और दाएं हाथ के पैरा वर्ग में कांस्य पदक।
- **लक्ष्मण सिंह भंडारी:** मास्टर्स श्रेणी में 2 कांस्य पदक।
- **सचिन गोयल:** दाएं हाथ के सीनियर वर्ग में कांस्य पदक।
- **इबी लोलेन:** महिलाओं की दाएं और बाएं हाथ की दोनों श्रेणियों में 2 कांस्य पदक।

मैट्रिड ओपन 2024

- आयोजन: 23 अप्रैल से 5 मई 2024 तक।
- स्थान: मैट्रिड, स्पेन
- **मैट्रिड ओपन 2024 के विजेता:**

वर्ग	विजेता
पुरुष एकल	एंड्री रुबलेफेलिक्स
महिला एकल	इगा स्वेटेक
पुरुष युगल	सेबस्टियन कोर्डा/जॉर्डन थॉम्पसन
महिला युगल	क्रिस्टीना बुक्सा / सारा सोरिब्स टोर्मो

इटैलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024

- आयोजन: 6 से 19 मई 2024 तक
- स्थान: रोम, इटली

मैट्रिड ओपन 2024 के विजेता:

वर्ग	विजेता
पुरुष एकल	अलेक्जेंडर ज्वेरेव
महिला एकल	इगा स्वेटेक
पुरुष युगल	मार्सेल ग्रैनोलर्स और होरासियो जेबालोस
महिला युगल	सारा इरानी और जैस्मीन पाओलिनी

- सेरेना विलियम्स के बाद, स्विटाटेक मैट्रिड ओपन और रोम मास्टर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है।
- इटैलियन ओपन को रोम मास्टर्स के नाम से भी जाना जाता है।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो

- क्रिस्टियानो रोनाल्डो चौथी बार फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर हैं।
- सऊदी अरब के अल-नासर में शामिल होने के बाद वे दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बन गए।
- फोर्ब्स की सूची के अनुसार, रोनाल्डो ने पिछले 12 महीनों में 260 मिलियन डॉलर कमाए, जिसमें अल-

नासर के साथ उनके क्लब अनुबंध से 200 मिलियन डॉलर और ऑफ-फील्ड आय से 60 मिलियन डॉलर शामिल हैं।

फोर्ब्स के 2024 में 5 सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट

1. क्रिस्टियानो रोनाल्डो (सॉकर)	260 मिलियन डॉलर
2. जॉन रहम (गोल्फ)	218 मिलियन डॉलर
3. लियोनेल मेस्सी (सॉकर)	135 मिलियन डॉलर
4. लेब्रोन जेम्स (बास्केटबॉल)	128.2 मिलियन डॉलर
5. जियानिस एंटेटोकोनम्पो (बास्केटबॉल)	111 मिलियन डॉलर

एमिलिया रोमाग्ना ग्रांप्री फॉर्मूला वन रेस

- आयोजन: इमोला (इटली)
- विजेता: मैक्स वर्स्टापन (रेड बुल के ड्राइवर)
- यह तीन बार के विश्व चैम्पियन रह चुके हैं।

मियामी ग्रैंड प्रिक्स रेस

- आयोजन: मिलामी (फ्लोरिडा)
- विजेता: लैंडो नॉरिस (मैकलेरन के F1 रेसर)
- लैंडो नॉरिस बेल्जियम रेसिंग ड्राइवर हैं।

रवि रोंगाली

- भारत के रवि रोंगाली ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में शॉटपुट F-40 स्पर्धा में पेरिस पैरालंपिक खेलों का कोटा हासिल किया।

ला लीगा टूर्नामेंट

- स्पैनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने कैंडिज को 3-0 से हराकर ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब जीत लिया है।
- ला लीगा स्पेन में शीर्ष घरेलू पुरुष पेशेवर फुटबॉल टूर्नामेंट है।

ला लीगा

- ला लीगा, स्पेन में एक पेशेवर पुरुष क्लब-आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता है।
- यह देश का सर्वोच्च रैंकिंग वाला घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है।
- ला लीगा दुनिया में सबसे लोकप्रिय पेशेवर क्लब-आधारित फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है।
- फिलहाल ला लीगा में 20 टीमों हिस्सा लेती हैं। प्रत्येक टीम दूसरी टीम के विरुद्ध दो बार खेलती है। सबसे अधिक अंक जीतने वाली टीम को ला लीगा की चैम्पियन बनती है।
- ला लीगा में सबसे सफल टीम रियल मैड्रिड है, जिसने इसे 36 बार जीता है।

जेम्स एंडरसन

- इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 11 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।

- उन्होंने 187 टेस्ट मैचों में 700 विकेट लिए हैं - जो टेस्ट इतिहास में किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक है।
- वह सर्वकालिक विकेट लेने की सूची में श्रीलंकाई स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (800) और दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई महान शेन वार्न (708) के बाद तीसरे स्थान पर हैं।

चीन ने थॉमस और उबेर कप का खिताब जीता

- चीनी पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 3-1 से हराकर अपना 11वाँ थॉमस कप जीता।
- चीनी महिला टीम ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर अपना 16वाँ उबेर कप खिताब जीता।

थॉमस और उबेर कप 2024

- यह थॉमस कप का 33वाँ संस्करण और उबेर कप का 30वाँ संस्करण था।
- यह एक अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है।
- यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) के सदस्य संघों की पुरुष और महिला राष्ट्रीय टीमों के लिए है।

ब्राजील, 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा।

- ब्राजील में फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किया जाएगा।
- ब्राजील इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश है।

सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024

- जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है।
- यह सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का 30वाँ संस्करण था।
- इसमें छह टीमों जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और मेजबान टीम, मलेशिया ने भाग लिया था।
- मलेशिया, इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा।

अजलान शाह ट्रॉफी

- सुल्तान अजलान शाह एशिया का एक प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट है जिसने दुनिया की शीर्ष पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीमों में भाग लेती हैं।
- इस ट्रॉफी का नाम पेरक मलेशिया राज्य के पूर्व सुल्तान, सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया है।
- इस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है, जिसने इसे 10 बार जीता है।
- भारत ने 5 बार (1985, 1991, 1995, 2009, 2010) सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है।

विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 गुवाहाटी में होगा

- बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) ने घोषणा की है कि वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी गुवाहाटी (असम) द्वारा की जाएगी।
- इसकी घोषणा बीडब्ल्यूएफ थॉमस और उबेर कप 2024 के मौके पर चेंगदू में BWF की वार्षिक आम बैठक के दौरान की गई।
- गुवाहाटी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में 14 बैडमिंटन कोर्ट, एक अंतरराष्ट्रीय मानक व्यायामशाला और लगभग 4000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है।
- भारत ने आखिरी बार BWF वर्ल्ड जूनियर्स की मेजबानी 2008 में पुणे में की थी।
- साइना नेहवाल वर्ल्ड जूनियर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है।
- भारत ने हैदराबाद में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी 2009 में की थी।
- भारत ने नई दिल्ली में थॉमस और उबेर कप की मेजबानी 2014 में की थी।

बजरंग पुनिया

- विश्व कुश्ती संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।
- बजरंग पुनिया द्वारा एंटी डोप टेस्ट के लिए अपना नमूना देने से इनकार करने के बाद भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) ने 23 अप्रैल 2024 को बजरंग पुनिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था।

डोप टेस्ट

- इस परीक्षण के तहत जैविक नमूनों में साइकोएक्टिव दवाओं की उपस्थिति की जाँच किया जाता है।
- साइकोएक्टिव दवाएं मस्तिष्क के कामकाज को प्रभावित करती हैं और मूड, जागरूकता, विचारों, भावनाओं और व्यवहार में बदलाव लाती हैं।
- यह परीक्षण मूत्र, लार, पसीना और रक्त जैसे तरल पदार्थ या बाल और नाखून जैसे ठोस नमूनों के माध्यम से किया जा सकता है।

7

पुरस्कार एवं सम्मान

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024

- जर्मन लेखक जेनी एर्पेनबेक (Jenny Erpenbeck) और अनुवादक माइकल हॉफमैन को पूर्वी जर्मनी के अस्तित्व के अंतिम वर्षों के दौरान एक पेचीदा प्रेम संबंध की कहानी 'कैरोस' के लिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार (International Booker Prize 2024) से सम्मानित किया गया है।
- जेनी एर्पेनबेक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की पहली जर्मन विजेता हैं।

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार

- यह पुरस्कार दुनिया भर के उन उपन्यासों को पुरस्कृत करता है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित हुई है।
- इसके तहत पुरस्कार राशि में 50,000 पाउंड (\$64,000) लेखक और अनुवादक के बीच वितरित किया जाता है।
- वर्ष 2023 में यह पुरस्कार बल्गेरियाई लेखक जॉर्ज गोस्पोडिनोव की 'टाइम शैल्ट' पुस्तक को दिया गया था।

कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय विजेता

- भारतीय अभिनेत्री अनूसया सेनगुप्ता को 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया है।
- वह इस प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं।
- इसके अलावा चिदानंद नाइक की फिल्म 'सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो' ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए 'ला सिनेफ' पुरस्कार जीता।

भारतीय विजेता	पुरस्कार	कृति
पायल कपाड़िया	ग्रैंड प्रिक्स	All We Imagine as Light
चिदानंद एस नाइक	ला सिनेफ (प्रीमियर प्रिक्स)	Sunflowers were the first ones to know
अनसूया सेनगुप्ता	सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (अन सर्टेन रिगार्ड)	The Shameless

- 'सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन्स टू नो' एक कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है, जिसका निर्देशन भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (FTII) के छात्र चिदानंद नाइक ने किया है।
- इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा पुरस्कार 'पाम डी'ओर' सीन बेकर की फिल्म 'एनोरा' को दिया गया।
- पाम डी'ओर आधिकारिक प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के निर्देशक को दिया जाता है।
- पाम डी'ओर जीतने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म चेतन आनंद की नीचा नगर (1946) है।
- इसके अलावा सिनेमैटोग्राफर संतोष सिवन अपने 'करियर और कार्य की असाधारण गुणवत्ता' के लिए पियरे एंजनीक्स ट्रिब्यूट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई बने हैं।

व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024

- भारत की डॉ. पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार व्हिटली गोल्ड पुरस्कार (Whitley Gold Award) से सम्मानित किया गया है।
- पूर्णिमा देवी बर्मन असम की वन्यजीव जीवविज्ञानी हैं।
- उन्हें 2017 में भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- पूर्णिमा देवी बर्मन को लुप्तप्राय पक्षी, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क जिसे असमिया भाषा में हरगिला कहा जाता है, के संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए सम्मानित किया गया।
- हरगिला पक्षी मुख्य रूप से उत्तर-पूर्व, विशेषकर असम के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- इन पक्षियों की आबादी घटकर लगभग 450 रह गई थी लेकिन डॉ. पूर्णिमा के संरक्षण प्रयासों के कारण वर्तमान में इन क्षेत्रों में हरगिला पक्षियों की आबादी 1800 से अधिक हो गई है।

व्हिटली पुरस्कार

- व्हिटली फंड फॉर नेचर (WFN) संस्था ने 2007 में व्हिटली गोल्ड अवार्ड्स की स्थापना की थी।
- यह यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत एक परोपकारी संस्था है।
- व्हिटली गोल्ड पुरस्कार को 'ग्रीन ऑस्कर' भी कहा जाता है।

पुलित्जर पुरस्कार 2024

- पुलित्जर पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा 7 मई को की गई।

- इस वर्ष कविता के क्षेत्र में ब्रेंडन सोम को सम्मानित किया गया है, वहीं खोजी पत्रकारिता के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को पुरस्कृत किया गया है।
- अमेरिका के समाचार पत्र 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' और 'द वाशिंगटन पोस्ट' को वर्ष 2023 में गाजा में युद्ध से लेकर बंदूक हिंसा जैसी घटनाओं पर उल्लेखनीय कार्य के लिए तीन श्रेणियों में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गयी है।
- समाचार एजेंसी 'द एसोसिएटेड प्रेस' को अमेरिका में वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के आवागमन की कवरेज के लिए फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया।
- लोक सेवा (पब्लिक सर्विस) पुरस्कार खोजी पत्रकार संस्था 'प्रोपब्लिका' को दिया गया है। उसे अमेरिकी उच्चतम न्यायालय पर की गयी खबरों के लिए यह पुरस्कार दिया गया।
- समाचार एजेंसी रॉयटर्स को फोटोग्राफी की श्रेणी में और एसोसिएटेड प्रेस को फीचर फोटोग्राफी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया।

पुलित्जर पुरस्कार (Pulitzer Prize)

- पुलित्जर पुरस्कार, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है।
- इसकी स्थापना 1917 में हंगरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने की थी।
- यह पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है।
- यह पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को 21 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है।
- इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष कोलम्बिया विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है।

आरती को UK रॉयल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया

- उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की पिंक ई-रिक्शा ड्राइवर आरती को लंदन में यूके रॉयल अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
- आरती को प्रिंस ट्रस्ट की ओर से अमल क्लूनी महिला सशक्तीकरण अवार्ड दिया गया।
- यह पुरस्कार किंग्स ट्रस्ट इंटरनेशनल द्वारा दिया जाता है।
- किंग चार्ल्स तृतीय ने प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की थी, जो अब किंग्स ट्रस्ट इंटरनेशनल के रूप में जाना जाता है।
- यह पुरस्कार दुनिया भर की महिलाओं को बिना किसी भौगोलिक प्रतिबंध के इन क्षेत्रों में उनके प्रभावशाली काम के लिए सम्मानित करता है।
- आरती को यह सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार की पिंक

ई-रिक्शा पहल के तहत किए जा रहे कार्य के जरिए युवा लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है, जिसमें वह दूसरी महिलाओं को सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्रदान करती हैं।

यूनेस्को/गिलमों कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024

- गाजा में संघर्ष को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 के यूनेस्को/गिलमों कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार (UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize) से सम्मानित किया गया है।

यूनेस्को/गिलमों कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार

- यह पुरस्कार 1997 में स्थापित किया गया था।
- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है तथा किसी ऐसे व्यक्ति, संगठन या संस्था को सम्मानित करता है जिसने दुनिया में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रसार में उत्कृष्ट योगदान दिया है।
- यह पुरस्कार यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड की पहल पर स्थापित किया गया था और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को द्वारा औपचारिक रूप से प्रदान किया जाता है।
- इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा की स्मृति में रखा गया है।

रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया

- प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड (Ruskin Bond) को साहित्य अकादमी ने अपने सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप (महत्तर सदस्यता) से सम्मानित किया है।
- बॉन्ड को सितंबर 2021 में अकादमी के सर्वोच्च सम्मान का प्राप्तकर्ता नामित किया गया था।
- उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में वैग्रांट्स इन द वैली, वन्स अपॉन ए मॉनसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, ऑल रोड्स लीड टू गंगा, टेल्स ऑफ फोस्टरगंज, लेपर्ड ऑन द माउंटेन और टू मच ट्रबल शामिल हैं।
- प्राप्त सम्मान: पद्म श्री (1999), पद्म भूषण (2019), साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार (2012), और साहित्य अकादमी पुरस्कार (1992)
- 1978 की हिंदी फिल्म जुनून रस्किन बॉन्ड के ऐतिहासिक उपन्यास ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स (1857 का भारतीय विद्रोह) पर आधारित है।
- रस्किन बॉन्ड ने 2011 में विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित फिल्म '7 खून माफ में' एक छोटी भूमिका निभाई थी, जो उनकी कहानी 'सुजानाज सेवन हस्बैंड्स' पर आधारित है।

मेजर राधिका सेन को 'यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड' मिला

- भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को वर्ष 2023 के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड (United Nations Military Gender Advocate of the Year Award) से सम्मानित किया गया है।
- यह पुरस्कार 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के अवसर पर महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने प्रदान किया।
- यह पुरस्कार 2000 के सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में एक सैन्य शान्ति रक्षक के प्रयासों को मान्यता देता है।
- यह प्रस्ताव महिलाओं और लड़कियों सेयौन हिंसा और संयुक्त राष्ट्र के लिए लैंगिक संबंधी जिम्मेदारियों की रक्षा का आह्वान करता है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मेजर राधिका सेन ने कॉंगो गणराज्य में संगठन स्थिरीकरण मिशन में अपनी सेवाएं दी। तथा वहाँ उन्होंने उत्तर किवू में कम्युनिटी अलर्ट नेटवर्क स्थापित करने में सहायता दी।
- मेजर राधिका सेन यह पुरस्कार पाने वाली दूसरी भारतीय शांति रक्षक हैं।
- उनसे पहले दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत मेजर सुमन गवानी ने यह सम्मान 2019 में प्राप्त किया था।

श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोलविज्ञान श्रेणी में शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

- अमेरिका में खगोल विज्ञान के भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिलीसेकंड खगोल-विज्ञान श्रेणी में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार (Shaw Prize in Astronomy) 2024 से सम्मानित किया जाएगा।
- यह पुरस्कार उन्हें पल्सर, गामा-किरण विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य परिवर्तनीय या क्षणिक खगोलीय पिंडों के बारे में अभूतपूर्व खोजों के लिए दिया जाएगा।
- शॉ पुरस्कार में तीन वार्षिक पुरस्कार शामिल हैं:
 - जीवन विज्ञान क्षेत्र में पुरस्कार।
 - चिकित्सा क्षेत्र में पुरस्कार।
 - गणितीय विज्ञान क्षेत्र में पुरस्कार।
- प्रत्येक पुरस्कार श्रेणी में दो लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाती है।

पं. लच्छू महाराज अवार्ड 2024

- यह पुरस्कार पं. लच्छू महाराज बैले फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है।
- पं. लच्छू महाराज पुरस्कार नृत्य और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।

- वर्ष 2014 के बाद से पं. लच्छू महाराज अवार्ड नहीं दिया गया था। अब एक साथ 10 वर्षों के सम्मान दिए गए हैं।
- अवार्ड समिति की बैठक में फाउंडेशन ने वर्ष 2015 से 2024 तक के सम्मान घोषित किए।
- पंडित राजेंद्र गंगानी को लच्छू महाराज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया।

पं. लच्छू महाराज अवार्ड विजेता

क्रम संख्या	पुरस्कार विजेता	वर्ष के लिए पुरस्कार	जगह से संबंधित	नृत्य विधा
1	उमा शर्मा	2015	नई दिल्ली	कथक
2	रमा वैद्यनाथन	2016	नई दिल्ली	कथक
3	उमा डोगरा	2017	जयपुर	कथक
4	हेमा मालिनी	2018	मुंबई	कथक, फिल्म अभिनेत्री
5	सायरा बानो	2019	मुंबई	कथक, फिल्म अभिनेत्री
6	संध्या पुरीचा संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष	2018	मुंबई	भरतनाट्यम
7	डॉ. मालविका मित्रा	2021	कोलकाता	कथक
8	प्राची शाह	2022	मुंबई	कथक, फिल्म अभिनेत्री
9	असीम बंधु भट्टाचार्य	2023	मुंबई	कथक
10	पंडित राजेंद्र गंगानी	2024	जयपुर	कथक

पं. लच्छू महाराज

- पं. लच्छू महाराज अवार्ड प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक लच्छू महाराज के सम्मान में स्थापित किया गया है।
- वे एक प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नर्तक और कोरियोग्राफर(नृत्य निर्देशक) थे।
- इन्होंने महल, मुगल-ए-आजम, छोटी-छोटी बातें और पाकीजा जैसी फिल्मों में कथक नृत्य कोरियोग्राफ किया था।
- 1957 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

8

चर्चित व्यक्तित्व

प्रदीप कुमार त्रिपाठी

- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (IAS) प्रदीप कुमार त्रिपाठी को 30 जुलाई तक लोकपाल सचिव नियुक्त किया गया है।

लोकपाल

- जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर भारत के वर्तमान लोकपाल हैं।
- भारत के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे।
- लोकपाल में छह अन्य सदस्य भी हैं।
- लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में तीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी हैं।
- लोकपाल के अन्य सदस्य अजय तिकी, पंकज कुमार और सुशील चंद्रा हैं।
- लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- राष्ट्रपति एक चयन समिति से सिफारिशें प्राप्त करने के बाद इनकी नियुक्ति करते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं।
- इसमें 1 अध्यक्ष के अलावा, लोकपाल में 8 सदस्य हो सकते हैं - चार न्यायिक और चार गैर-न्यायिक।
- लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, होता है।

राकेश रंजन

- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (IAS) राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

जया बडिगा

- भारतीय-अमेरिकी वकील जया बडिगा को अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है।
- वह एक प्रमाणित पारिवारिक कानून विशेषज्ञ हैं और उन्होंने दस साल से अधिक समय तक पारिवारिक कानून में काम किया है।
- वह अमेरिका में जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली तेलुगु महिला हैं।

समीर वी. कामत

- कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष

डॉ. समीर वी. कामत को 31 मई 2025 तक विस्तार दिया है।

- डॉ. कामत को अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया था। उन्होंने डॉ. जी. सतीश रेड्डी से पदभार संभाला था।
- डॉ. जी. सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है।

इंदाशिश नोंगरांग

- सुश्री इंदाशिश नोंगरांग को 19 मई 2024 को मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया गया है।
- सुश्री नोंगरांग ने लज्जा राम बिश्नोई का स्थान लिया।
- इनका राज्य पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यकाल 19 मई, 2026 तक रहेगा। सुश्री नोंगरांग खासी समुदाय से हैं।

कृष्णा स्वामीनाथन

- वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को 1 मई को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया।
- कृष्णा को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी (वर्तमान नौसेना प्रमुख) के स्थान पर नियुक्त किया गया।
- कार्यक्रम के दौरान कृष्णा स्वामीनाथन को नेवी ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया।
- उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है।
- वो INS विक्रमादित्य के अलावा वॉरशिप्स की कमान भी संभाल चुके हैं।

संजय भल्ला

- वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने 10 मई को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला।
- उन्होंने कई प्रमुख युद्धपोतों पर विशेषज्ञ के तौर पर काम किया है। इनमें INS निशांक, INS तारागिरी और INS व्यास शामिल हैं।
- संजय भल्ला को विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।
- उन्हें नौसेना पदक और नौसेना प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया जा चुका है।

संजय कुमार मिश्रा

- न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय कुमार मिश्रा ने 6 मई 2024 को GST अपील न्यायाधिकरण (GSTAT) का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें पद की शपथ दिलाई।

- उन्हें चार साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।
- संजय कुमार का चयन भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने किया।
- संजय कुमार मिश्रा झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं।

GSTAT

- GSTAT केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2007 के तहत स्थापित अपीलीय प्राधिकरण है।
- यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश GST अधिनियम के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई करता है।
- इसमें एक हेड बेंच और विभिन्न राज्य बेंच शामिल हैं।
- GST परिषद की मंजूरी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने दिल्ली में स्थित हेड बेंच और देशभर में विभिन्न स्थानों पर 31 राज्य बेंच को अधिसूचित किया है।
- GSTAT 1 जुलाई 2024 से दिल्ली स्थित हेड बेंच से काम शुरू करेगी।

दिलीप संधानी

- दिलीप संधानी को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति (IFFCO) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
- बलवीर सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया है।

भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति

- यह एक बहु-राज्य सहकारी समिति है।
- यह उर्वरक के निर्माण और विपणन में भाग लेती है।
- इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

प्रतिमा सिंह

- प्रतिमा सिंह को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है।
- ये 2009 बैच की इंडियन रेवेन्यू सर्विस (IRS) ऑफिसर हैं।
- प्रतिमा सिंह का कार्यकाल कार्यभार संभालने की तारीख से पांच साल तक के लिए या अगले आदेश तक जारी रहेगा।

DPIIT

- यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री) के तहत एक केंद्रीय सरकारी विभाग है।
- यह डिपार्टमेंट अपने वर्तमान स्वरूप में 27 जनवरी, 2019 को अस्तित्व में आया।
- इसमें इंटरनल ट्रेड को जोड़ने के बाद पूर्व में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का नाम बदलकर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) कर दिया गया।

- यह डिपार्टमेंट मूल रूप से 1995 में स्थापित किया गया था और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के विलय के साथ वर्ष 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया था।

संजीव पुरी

- ITC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, संजीव पुरी को 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
- संजीव पुरी ने आर. दिनेश का स्थान लिया

भारतीय उद्योग परिसंघ

- यह 1895 में स्थापित एक गैर-सरकारी उद्योग प्रबंधित संगठन है।
- यह भारत की औद्योगिक विकास प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका निभाता है।
- इस का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- यह एक सदस्यता-आधारित संगठन है, और सदस्यता निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से मिलकर बनी है।
- यह वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग को आकार देने के लिए व्यापारिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं के साथ में सलाहकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास, उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के अनुकूल माहौल बनाने और बनाए रखने के लिए काम करता है।

कामी रीता शेरपा

- नेपाल के कामी रीता ने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
- वे 12 मई 2004 को 29वीं बार शिखर पर पहुंचे।
- माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है।
- कामी रीता को 'एवरेस्ट मैन' के नाम से जाना जाता है, और वह जातीय शेरपा समुदाय से हैं।
- सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे।
- जुंको ताबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थीं।

पूर्णमा श्रेष्ठ

- नेपाल के गोरखा की 32 वर्षीय पर्वतारोही और फोटो जर्नलिस्ट पूर्णमा श्रेष्ठ 13 दिनों में तीन बार एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बनी है।

ज्योति रात्रे

- ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं।
- वह 55 साल की हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का यह उनका दूसरा प्रयास था।

एआई एंकर 'कृष' और 'भूमि' लॉन्च

- सरकारी स्वामित्व वाला टीवी चैनल डीडी किसान ने दो एआई एंकर, 'कृष' और 'भूमि' लॉन्च किए गए हैं।
- ये एआई एंकर पचास भाषाओं में संवाद करने और साल के 24x7, बिना थके समाचार प्रस्तुत करने में सक्षम हैं।
- ये एंकर कृषि अनुसंधान, वैश्विक रुझान, कृषि मंडियों से बाजार अपडेट, मौसम पूर्वानुमान और सरकारी योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करेंगे।

विलियम लाई चिंग-ते

- यह हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं।
- लाई को विलियम के नाम से भी जाना जाता है।
- उन्होंने ने साई इंग वेन की जगह ली है।
- ताइवान में 1949 से स्वतंत्र सरकार है।

ताइवान

- पूर्वी एशिया का एक देश है। इसे आधिकारिक तौर पर चीन गणराज्य कहा जाता है।
- ताइपे इसकी राजधानी है।
- ताइवान के मुख्य द्वीप को फॉर्मोसा के नाम से भी जाना जाता है।

गीतानास नौसेदा

- गीतानास नौसेदा लिथुआनिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं।
- गीतानास नौसेदा ने प्रधानमंत्री इग्निडा सिमोनीटे को हराकर लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल हासिल किया।

मोहम्मद मोखबर

- ईरान के पहले उपराष्ट्रपति रहे मोहम्मद मोखबर को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है।
- वे अधिकतम 50 दिनों की अवधि के लिए पद पर रहेंगे।
- ईरान के संविधान के अनुसार, यदि किसी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो सर्वोच्च नेता की स्वीकृति से पहले उपराष्ट्रपति 50 दिनों की अंतरिम अवधि के लिए पदभार ग्रहण करता है।
- मोहम्मद मोखबर 2021 में इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति चुने जाने पर पहले उपराष्ट्रपति बने थे।

जनरल टू लैम

- जनरल टू लैम को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है।

डोनाल्ड ट्रम्प

- डोनाल्ड ट्रम्प किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं।

- न्यूयॉर्क की एक जूरी ने उन्हें एक पोर्न स्टार को पैसे देकर 2016 के चुनाव को अवैध रूप से प्रभावित करने में दोषी पाया।
- नोट:** किसी मामले में दोषसिद्ध ट्रम्प को राष्ट्रपति पद के चुनाव में भाग लेने से नहीं रोकेगी।

व्लादिमीर पुतिन ने पांचवीं बार रूसी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली

- रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 7 मई 2024 को मॉस्को में 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली।
- पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन के बाद सबसे लम्बे समय लगभग 25 वर्ष तक सत्ता में रहने वाले श्री व्लादीमिर पुतिन का नया कार्यकाल 2030 तक रहेगा।
- पुतिन दिसंबर 1999 से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के तौर पर रूस का नेतृत्व कर रहे हैं।
- पुतिन ने 2000 में पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, जिसके बाद से 2004, 2012 और 2018 में भी वो राष्ट्रपति बन चुके हैं।
- रूस में 15-17 मार्च 2024 के बीच हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन को 87.3% मत मिले।

मिखाइल मिशुस्टिन

- रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 10 मई को मिखाइल मिशुस्टिन को देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्ति की।
- मिखाइल ने 16 जनवरी 2020 में पहली बार प्रधानमंत्री पद संभाला था।
- उन्हें कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध के बाद भी रूसी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का श्रेय दिया गया है।

इदरीस डेबी इटनो

- सैन्य तानाशाह और मध्य अफ्रीकी देश चाड के अंतरिम राष्ट्रपति महामत इदरीस डेबी इटनो ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है।
- इदरीस डेबी का कार्यकाल 6 वर्षों तक रहेगा।

लॉरेंस वोंग

- लॉरेंस वोंग ने 15 मई 2024 को सिंगापुर के नए प्रधान मंत्री बने हैं।
- वह 20 वर्षों में नेतृत्व परिवर्तन करने वाले पहले नेता और देश की आजादी के बाद केवल चौथे नेता बने।

जेरेमिया मानेले

- जेरेमिया मानेले को सोलोमन द्वीप का नया प्रधानमंत्री चुना गया है।
- वह मनश्शे सोगावारे का स्थान लेंगे।
- जेरेमिया मानेले को चीन समर्थक माना जाता है।

सोलोमन द्वीप समूह

- सोलोमन द्वीप समूह दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीप समूह है।
- हाल के वर्षों में चीन ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है।
- जेरैमिया मानेले के सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री चुने जाने से अमेरिका को आशंका है कि चीन इस क्षेत्र में सैन्य अड्डा स्थापित कर लेगा, जो ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 1200 मील की दूरी पर है।

जोस राउल मुलिनो

- जोस राउल मुलिनो पनामा के राष्ट्रपति चुने गए हैं।

निधन**इब्राहिम रायसी**

- ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई।
- इसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की भी मौत हो गई है।
- रायसी की मृत्यु के बाद, ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं।
- ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई हैं।

सलाम बिन रज्जाक

- मशहूर उर्दू साहित्यकार सलाम बिन रज्जाक का 7 मई निधन हो गया।
- सलाम बिन रज्जाक की 50 से ज्यादा कहानियां ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित हो चुकी हैं।
- सलाम को 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- सलाम को गालिब पुरस्कार, महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार समेत कई सम्मान मिले थे।

सुशील कुमार मोदी

- सुशील कुमार मोदी का 13 मई 2024 को निधन हो गया। उन्होंने बिहार के चौथे उपमुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया।
- वह चार विधायी सदनों - लोकसभा, राज्यसभा, बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य थे।

एलिस मुनरो

- साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो का 13 मई 2024 निधन हो गया।
- वे कनाडा की सबसे प्रसिद्ध लेखिकाओं में से एक हैं। उन्हें 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला।
- उनकी अंतिम कृति का शीर्षक 'डियर लाइफ' था, जो लघु कथाओं का संग्रह है।

कर्नल वैभव अनिल काले

- भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले 15 मई को गाजा के रफाह इलाके में शहीद हो गए।
- संयुक्त राष्ट्र ने वैभव अनिल काले को रफाह के यूरोपियन हॉस्पिटल में सुरक्षा कार्यों के लिए तैनात किया था। उन्होंने 2009-10 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भी भाग लिया था।

मालती जोशी

- प्रसिद्ध कथाकार मालती जोशी का 15 मई 2024 को निधन हो गया।
- मालती जोशी हिंदी और मराठी भाषा की प्रसिद्ध कथाकार थीं। उन्हें 2018 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

सुरजीत पातर

- पद्म श्री विजेता प्रसिद्ध पंजाबी कवि सुरजीत पातर का 11 मई को निधन हो गया।
- पातर को पद्म श्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।

9

चर्चित स्थल

मसूरी: भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, 'नक्षत्र सभा' उत्तराखंड पर्यटन द्वारा शुरू किया गया।

- नक्षत्र सभा की शुरुआत मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में शुरू हुई।
- नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और एस्ट्रो-टूरिज्म कंपनी स्टार्सस्केप्स के बीच एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- यह एक व्यापक खगोल-पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक पहल है।
- इसका उद्देश्य तारा अवलोकन है, और प्रतिभागियों को तारा अवलोकन, विशेष सौर अवलोकन, एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिताओं और तारों के नीचे शिविर लगाने जैसी विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना है।
- इसका लक्ष्य एक आकर्षक मंच बनाना है जो खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही, साहसी लोगों और यात्रियों को उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के साथ-साथ ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने के लिए एक साथ लाता है।

सिक्किम: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यातायात प्रबंधन प्रणाली संचालित करने वाला पहला राज्य

- सिक्किम परिवहन विभाग ने पूरे राज्य में 25 मई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू की।
- इस पहल का मुख्य उद्देश्य यातायात प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और विनियामक दक्षता में सुधार करना है।
- यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्वचालित रूप से दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और उल्लंघनों का पता लगाएगी।
- सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार, सभी वाहन मालिकों को अपने सभी वाहन दस्तावेजों को अपडेट रखना होगा।

अबू धाबी: IIT दिल्ली का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर

- आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में शुरू किया है।
- छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 या संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) 2024 के माध्यम से प्रवेश पा सकते हैं।
- इसे पहले IIT मद्रास ने पिछले साल जांजीबार, तंजानिया में एक परिसर स्थापित किया था।

विजयपुर (मध्य प्रदेश): GAIL का पहला 10 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन

- गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) ने मध्य प्रदेश (MP) के विजयपुर परिसर में अपने पहले ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) प्लांट का उद्घाटन किया।
- इस प्लांट की क्षमता 10 मेगावाट (MW) प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (PEM) इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से 4.3 टन प्रति दिन (TPD) हाइड्रोजन का उत्पादन करने की है।
- 10 मेगावाट की क्षमता वाला PEM इलेक्ट्रोलाइजर कनाडा से आयात किया गया है।
- इस प्लांट में उत्पादित हाइड्रोजन की मात्रा 99.99% होगी।
- इसे 30 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर (kg/cm²) के दबाव पर बनाया जाएगा।
- यह पहल 2040 तक नेट-जीरो स्थिति प्राप्त करने के गेल के लक्ष्य और 2030 तक भारत के लिए 5 मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता तक पहुँचने के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के लक्ष्य के अनुरूप है।

तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा: भारत का पहला जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान पाने वाला पहला हवाई अड्डा

- केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा CII-ITC-CESD (सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र) द्वारा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल (ZWL) मान्यता अर्जित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है।
- ZWL मूल्यांकन के अनुसार हवाई अड्डे ने प्रमुख अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है, जिससे लैंडफिल से उल्लेखनीय 99.50% अपशिष्ट प्रबंधन हुआ है।
- इस हवाईअड्डे ने अपने 100% प्लास्टिक कचरे और 100% नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW), जिसमें गीला और सूखा दोनों तरह का कचरा शामिल है, को लैंडफिल से दूर कर दिया है।

परिष्कृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली:

- तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ISO 14001:2015 मानकों के अनुरूप एक परिष्कृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है।

IIT कानपुर: रक्षा प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ

- IIT कानपुर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने संयुक्त रूप से IIT कानपुर परिसर

में DRDO-उद्योग-अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र (DIA COI) शुरू किया है, जो उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों में अंतःविषय अनुसंधान पर केंद्रित है।

- इस केंद्र का उद्देश्य विभिन्न रक्षा क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान का नेतृत्व करना है।
- इनमें उन्नत नैनोमटेरियल, त्वरित सामग्री डिजाइन, उच्च ऊर्जा सामग्री और बायोइंजीनियरिंग शामिल हैं।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) इन परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा और प्रमुख तकनीकी सुविधाएँ स्थापित करेगा।

शक्सगाम घाटी

- भारत ने शक्सगाम घाटी (Shaksgam valley) में चीन द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य पर कड़ी शिकायत दर्ज कराई है।
- यह घाटी वर्तमान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (Pakistan-occupied Kashmir: PoK) का हिस्सा है।
- रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन सामरिक अवस्थिति वाली शक्सगाम घाटी में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है।
- पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने सीमा विवादों को समाप्त करने के लिए 1963 में सीमा समझौते पर हस्ताक्षर कर शक्सगाम घाटी चीन को सौंप दी।
- भारत ने 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया।

• भारत का मानना है कि शक्सगाम घाटी या ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, पाक अधिकृत कश्मीर के हुंजा-गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है।

- इसकी सीमा उत्तर में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जिनजियांग प्रांत से लगती है। पाक अधिकृत कश्मीर का उत्तरी इलाका इसके पश्चिम और दक्षिण में है और पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र है।
- इस घाटी में, विशेष रूप से अधिल दर्रे (Aghil Pass) के पास, सड़क बनाने के चीन के हालिया प्रयास विशेष रूप से दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के निकट होने के कारण भारत की सुरक्षा के लिए चिंताएँ बढ़ाते हैं।

नरसिंहगढ़: त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

- त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पश्चिम त्रिपुरा जिले में स्थित नरसिंहगढ़ में बनाया जा रहा है।
- यह स्टेडियम फरवरी 2025 तक प्रमुख क्रिकेट आयोजनों की मेजबानी के लिए तैयार हो जाएगा।
- यह पूर्वोत्तर राज्य का पहला स्टेडियम होगा। इसका निर्माण 200 करोड़ रुपये के बजट से किया जा रहा है।
- इस स्टेडियम का निर्माण BCCI और त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। इस स्टेडियम की क्षमता 25,000 से अधिक होगी।

10

महत्वपूर्ण तथ्य

इंडियास्किल्स 2024

- यह देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन 15-18 मई 2024 तक नई दिल्ली के यशोभूमि में किया गया।
- यह प्रतियोगिता युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करती है।
- इसका आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा किया जाता है।

'पिरूल लाओ-पैसा पाओ' मिशन

- जंगल की आग को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार 'पिरूल लाओ-पैसा पाओ' (Pirul Lao-Paise Pao) मिशन शुरू किया है।
- इस मिशन के तहत वनाग्नि को कम करने के उद्देश्य से पिरूल को संग्रहण केन्द्र पर 50 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जायेगा।
- इस मिशन का संचालन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड अलग से रखा जाएगा।
- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के आँकड़ों के अनुसार 28 अप्रैल के बाद से देश में सबसे अधिक जंगल की आग उत्तराखंड में दर्ज की गई है।
- उत्तराखंड में जंगल की आग की बढ़ती आवृत्ति को प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय गतिविधियों के मिश्रण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
- ये जंगल, जो मुख्य रूप से 3.94 लाख हेक्टेयर में फैले अत्यधिक ज्वलनशील चीड़ के पेड़ों से भरे हुए हैं, इसलिए यहाँ आग लगने का खतरा अधिक है।

लूना इम्पैक्ट क्रेटर

- हाल ही में नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी के एक सैटेलाइट ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र (बन्नी घास के मैदान) में लूना नामक क्रेटर (Luna impact crater) की तस्वीरें रिकॉर्ड की है।
- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार एक हालिया भू-रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है कि 'इस क्रेटर में उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने (इम्पैक्ट क्रेटर) से हुए निर्माण के विशिष्ट लक्षण दिखते हैं।'

- नासा की रिपोर्ट के अनुसार लूना इम्पैक्ट क्रेटर के फुटप्रिंट 24 फरवरी को लैंडसैट 8 उपग्रह पर OLI (ऑपरेशनल लैंड इमेजर) द्वारा कैप्चर किए गए थे।
- पृथ्वी पर इम्पैक्ट क्रेटर अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं और उनमें से 200 से कम की पुष्टि की गई है।
- नासा ने कहा कि कई उल्कापिंड, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के बाद भी नष्ट नहीं होते वे, जलस्रोतों में गिर जाते हैं।

भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप इमेजिंग टूल

- आईटी सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बॉम्बे के साथ साझेदारी की है।
- इस सेंसिंग डिवाइस में सेमीकंडक्टर चिप्स के परीक्षण में सटीकता के नए स्तर को प्राप्त करने, चिप विफलताओं को कम करने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने की क्षमता होगी।
- अगले दो वर्षों में, TCS विशेषज्ञ IIT-बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कस्तूरी साहा के साथ मिलकर इस डिवाइस को विकसित करेंगे।
- सेमीकंडक्टर चिप्स सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक अनिवार्य घटक हैं।
- संचार, कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य सेवा, सैन्य प्रणाली, परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य सहित विभिन्न उद्योगों में, ये चिप्स उपकरणों के मस्तिष्क के रूप में काम करते हैं।
- वर्तमान में भारत में 4 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 3 गुजरात में और 1 असम में है।

'हज सुविधा ऐप'

- हज-2024 हेतु यात्रियों की सुविधा हेतु केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने यह पहल की है।
- यह एप यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
- इसमें यात्रियों को डिजिटल कुरआन, नमाजों का समय, हज का अरकान, हज का तरीका, मुजदलफा, अरफात की जानकारी मिलेगी।
- इसके अलावा पासपोर्ट, टिकट, दस्तावेज के अलावा सउदी अरब में आवास की सुविधा भी मिल सकेगी।

पर्यावरण

संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट (United Nations Forum on Forests: UNFF)

- इसका आयोजन 6-10 मई 2024 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया।
- यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट्स संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) का एक कार्यात्मक (Functional) आयोग है।
- इसकी सदस्यता सार्वभौमिक है अर्थात कोई भी देश इसका सदस्य हो सकता है।
- इसकी स्थापना 2000 में हुई। इसने कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिनमें 2007 में पहला संयुक्त राष्ट्र फॉरेस्ट इंस्ट्रूमेंट, 2015 में वैश्विक वन वित्तपोषण सुविधा नेटवर्क (GFFFN), और 2017 में वनों के लिए पहली संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2030 और इसके छह वैश्विक वन लक्ष्यों को अपनाना शामिल है।

विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024

- नीदरलैंड के रोट्टरडैम में 13 से 15 मई 2024 तक विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन (World Hydrogen Summit) 2024 का आयोजन किया गया।
- इस सम्मेलन में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपना पहला मंडप स्थापित किया।
- विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन सबसे बड़ा वैश्विक हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम है जो दुनिया में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

- भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया।
- इसका मुख्य उद्देश्य 2030 के अंत तक 5 मिलियन टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है।
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन ने वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास, 125 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि, जीवाश्म ईंधन के आयात में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी करना, वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी का लक्ष्य रखा है।
- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अलावा, स्टील, परिवहन और शिपिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए योजना व दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

- भारत में नवाचार को बढ़ावा देने और हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की शुरुआत की है।
- वर्तमान में, भारत की 44% ऊर्जा जरूरतें गैर-जीवाश्म स्रोतों से पूरी होती हैं। यह 2030 तक बढ़कर लगभग 65% हो जाएगा।

किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क

- हाल ही में, वैज्ञानिकों के एक समूह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र के किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क (Kishtwar High Altitude National Park) में 4 हिम तेंदुओं (पैंथेरा अनसिया) को देखा है।
- भारत हिम तेंदुए की वैश्विक रेंज के 2% का पर्यावास है। यहाँ हाई माउंटेन एशिया की फ्लैगशिप प्रजाति है।
- जनवरी 2024 में केंद्र द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, भारत में 718 हिम तेंदुए हैं, जिनमें से अधिकांश ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो कानूनी संरक्षण के अंतर्गत नहीं हैं।
- आइकोनिक हिम तेंदुओं को 'पहाड़ों का ग्रे भूत' (grey ghost of the mountains) कहा जाता है।
- किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है।
- यह संरक्षित क्षेत्र 4,300 मीटर की ऊंचाई से ऊपर स्थित है। और एक्सट्रीम वेदर के कारण यह इलाका दुर्गम हो जाता है।
- हिम तेंदुए के अलावा, इस पार्क में साइबेरियन आइबेक्स (कैप्रा सिबिरिका), हिमालयी कस्तूरी मृग (मोस्कस ल्यूकोगास्टर) और भेड़िये प्राप्त होते हैं।
- किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क हिम तेंदुए का हैबिटेट है।
- यह नेशनल पार्क तीन हिमालयी लैंडस्कैप को जोड़ता है: जम्मू और कश्मीर का ग्रेटर हिमालयए लद्दाख का ट्रांस-हिमालय (जंस्कर के माध्यम से) और हिमाचल प्रदेश का लघु हिमालय (lesser Himalayas)।

साँइल नेलिंग और हाइड्रोसीडिंग

- हाल ही में तमिलनाडु राज्य राजमार्ग विभाग मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए नीलगिरी की प्रमुख सड़कों के आसपास पांच स्थानों पर घास उगाकर ढलानों को स्थिर करने की परियोजना पर कार्य कर रहा है।
- इस परियोजना का नाम 'साँइल नेलिंग और हाइड्रोसीडिंग विधि' है।
- इसका उपयोग करके ढलान स्थिरीकरण' (Slope Stabilisation using Soil Nailing and Hydroseeding method) करना है।

- सॉयल नेलिंग एक भू-तकनीकी इंजीनियरिंग तकनीक है जिसमें मृदा (Soil) को मजबूत करने के लिए किसी निर्धारित क्षेत्र में उसमें मजबूत तत्वों को शामिल किया जाता है।
- नीलगिरी में 5 स्थानों को भूस्खलन की आशंका के कारण नेलिंग के लिए चुना गया था और भविष्य में भूस्खलन से सड़कों को अवरुद्ध होने से रोकने के लिए ढलान स्थिरीकरण (slope stabilization) के वैकल्पिक तरीकों को अपनाया जा रहा है।
- हाइड्रोसीडिंग घास और पौधों के विकास में मदद के लिए मिट्टी में बीज, उर्वरक, जैविक सामग्री और पानी का मिश्रण लगाने की एक प्रक्रिया है।
- यह मृदा की ऊपरी परत को जोड़े रखने और कटाव को रोकने में मदद करती है।

हम्बोल्ट ग्लेशियर (Humboldt glacier)

- वेनेजुएला का आखिरी ग्लेशियर था जो हाल ही में पिघल गया।
- हम्बोल्ट ग्लेशियर (Humboldt glacier) इतना सिकुड़ गया है कि वैज्ञानिकों ने इसे ग्लेशियर के वर्गीकरण से हटाकर आइस फील्ड के रूप में फिर से वर्गीकृत कर दिया है।
- वेनेजुएला विश्व का पहला देश है जिसने आधुनिक समय में अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं।
- दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र का एकमात्र बचा हुआ ग्लेशियर – हम्बोल्ट, एंडीज पर्वतमाला में था।
- वेनेजुएला में सिएरा नेवादा डी मेरिडा पर्वत श्रृंखला में कभी छह ग्लेशियरों का घर रहा है।
- वर्ष 2011 तक 5 ग्लेशियर पिघलकर विलुप्त हो गए थे, केवल हम्बोल्ट ग्लेशियर बचा था, जिसे ला कोरोना भी कहा जाता था।

11

इंडेक्स एवं रिपोर्ट्स

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024

- यह सूचकांक वैश्विक संस्था 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (RWB) ने 3 मई 2024 को जारी किया।
- इस सूचकांक में भारत 159वें स्थान पर है। (वर्ष 2023 में 161वें स्थान पर था)
- इस सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। (लगातार छठे वर्ष)
- अंतिम स्थान पर इरिट्रिया (180वें स्थान) है।
- भारत के पड़ोसी देशों में चीन 172वें, श्रीलंका 150वें, नेपाल 74वें, म्यांमार 171वें, बांग्लादेश 165वें और पाकिस्तान 152वें स्थान पर है।
- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RWB) एक फ्रांसीसी गैर-सरकारी संगठन है जिसे रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स (RSF) के रूप में भी जाना जाता है।
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक राजनीतिक संकेतक, आर्थिक संकेतक, विधायी संकेतक, सामाजिक संकेतक और सुरक्षा संकेतक सहित 5 संकेतकों पर आधारित है।

ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024

- इसे एनर्जी थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी किया गया है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया।
- सौर ऊर्जा ने 2023 में वैश्विक बिजली का रिकॉर्ड 5.5% उत्पादन किया।
- वैश्विक ट्रेड के अनुसार, भारत ने पिछले वर्ष (2023) अपनी 5.8% बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न की।
- भारत में बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 2015 में 0.5% से बढ़कर 2023 में 5.8% हो गया।
- 2023 में वैश्विक सौर उत्पादन वृद्धि के मामले में, भारत चौथे स्थान पर (+18 टेरावाट घंटा, या TWh) था।

विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024

- संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) ने 7 मई, 2024 को 'विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024' जारी की।
- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत को 111.22 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ था।
- प्रेषण (Remittance) से तात्पर्य विदेशों में काम करने वाले लोगों द्वारा अपने देश में भेजे गए धन से है।
- भारत आवक प्रेषण में 100 बिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।

- मेक्सिको ने 2022 में 61.10 बिलियन डॉलर के आवक प्रेषण के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया।
- 2024 के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक अंतरराष्ट्रीय प्रेषण 831 अरब डॉलर था जबकि 2021 में यह 791 अरब डॉलर था।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM)

- यह जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट हर दो साल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है।

यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024

- यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा सरे विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार किया गया है।
- भारत इस सूचकांक में 39वें स्थान पर है। (2021 में 54वाँ स्थान) तथा भारत का स्कोर 4.25 है।
- इस में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) प्रथम स्थान पर है।
- भारत दक्षिण एशिया और निम्न-मध्यम-आय वाले देशों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 2024 की सूची में शीर्ष पांच देशों में शामिल हैं।
- भारत का ओवरऑल यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक (TTDI) स्कोर 2019 के स्तर से 2.1% कम है।

ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमैटिक रिपोर्ट ऑन रेंजलैंड्स एंड पास्टरलिस्ट्स (Global Land Outlook Thematic Report on Rangelands and Pastoralists)

- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD) द्वारा जारी की गई।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, रेंजलैंड्स (Rangelands) सभी भूमि का 54% हिस्सा कवर करते हैं; 50% रेंजलैंड्स का क्षरण हो चुका है, जिससे मानवता की खाद्य आपूर्ति का 1/6वां हिस्सा और पृथ्वी के 1/3 कार्बन स्टॉक खतरे में पड़ गया है।
- वर्तमान में, रेंजलैंड पृथ्वी के स्थलीय सतह क्षेत्र के 80 मिलियन वर्ग किमी (पृथ्वी की भूमि के आधे से अधिक) को कवर करते हैं, और इस प्रकार यह दुनिया में सबसे बड़ा भूमि कवर या भूमि उपयोग प्रकार है।
- भारत में, थार रेगिस्तान से लेकर हिमालयी घास के मैदानों तक, रेंजलैंड्स लगभग 1.21 मिलियन वर्ग किमी में फैले हुए हैं।

- रेंजलैंड में ज्यादातर प्राकृतिक घास के मैदान शामिल हैं जिनका उपयोग पशुधन और जंगली जानवरों द्वारा चरने और चारे के लिए किया जाता है।
- इनमें सवाना, झाड़ियाँ, आर्द्रभूमि, टुंड्रा और रेगिस्तान भी शामिल हैं।

भारत की बहुसंख्यक आबादी में 7.82 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई

- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने 9 मई 2024 को एक रिपोर्ट जारी की।
- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुसंख्यक आबादी में गिरावट आई है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 1950 से 2015 तक बहुसंख्यक आबादी में 7.82% की गिरावट आई है। यह दक्षिण एशियाई देशों म्यांमार के बाद दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है।
- वर्ष 1950 में हिंदू आबादी 84.68% थी, जो 2015 में घटकर 78.06% रह गई है।
- भारत में अल्पसंख्यक समूहों - मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है तथा जैन और पारसियों की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है।
- इसी अवधि में देश में मुस्लिम आबादी 43.15% और ईसाई आबादी में 5.38% की वृद्धि हुई है।

- इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान, सिख और बौद्ध आबादी की हिस्सेदारी में क्रमशः 1.85% और 0.81% की वृद्धि देखी गई।
- हालाँकि, जनसंख्या मिश्रण में जैन और पारसियों की हिस्सेदारी में गिरावट आई और 2015 में यह क्रमशः 0.36% और 0.004% रही।
- बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी काफी कम हो गई है।

मुंबई और दिल्ली दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल

- दुनिया के सबसे अमीर शहरों की नवीनतम रैंकिंग हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा जारी की गई है।
- दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में न्यूयॉर्क शीर्ष स्थान पर है। शीर्ष 50 में 11 शहर अमेरिका के हैं।
- शीर्ष 10 सबसे अमीर शहरों में से पांच एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं। शीर्ष 10 में टोक्यो (तीसरे), सिंगापुर (चौथे), और बीजिंग (10वें) पर हैं।
- मुंबई और दिल्ली इस रैंकिंग में क्रमशः 24वें और 37वें स्थान पर हैं।

12

प्रमुख दिवस एवं सप्ताह

महाराष्ट्र और गुजरात का 64वाँ स्थापना दिवस

- महाराष्ट्र और गुजरात, प्रत्येक वर्ष 1 मई को अपना स्थापना दिवस (Maharashtra Day and Gujarat Day) मनाते हैं।
- 1 मई 1960 को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बोम्बे राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की स्थापना की गई थी।
- भारत की संसद ने बोम्बे स्टेट के विभाजन हेतु 'बोम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960' पारित किया था।
- यह अधिनियम 1 मई 1960 को लागू हुआ था।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

- प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (World Press Freedom Day) मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करना और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा तथा ड्यूटी के दौरान हमले में जान गंवाने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है।
- वर्ष 2024 में विषय (थीम)- 'ग्रह के लिए एक प्रेस: पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता.' (A Press for the Planet: Journalism in the Face of the environmental crisis.) है।

अन्तर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस

- प्रत्येक वर्ष 4 मई को अन्तर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस (International Firefighter's Day) मनाया जाता है।
- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उन फायर फाइटरों को सम्मान देना है, जो अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों और वन्य जीवों की जान आग से बचाते हैं।
- इस दिवस का प्रतीक 'लाल और नीले रंग के दो रिबन' हैं, जिसमें लाल रंग आग को, और नीला रंग पानी को दर्शाता है।

विश्व स्वच्छता दिवस

- प्रत्येक वर्ष 5 मई को 'विश्व स्वच्छता दिवस' (World Hygiene Day) मनाया जाता है।
- इस दिवस को 'विश्व हाथ स्वच्छता दिवस' (World Hand Hygiene Day) के नाम से भी जाना जाता है।
- इस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नेतृत्व में एक वैश्विक अभियान चलाया जाता है।
- इस अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति

जागरूक करना और स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहित करना होता है।

- वर्ष 2024 का मुख्य विषय (थीम)- 'हाथ की स्वच्छता की शक्ति' (Power of Hand Hygiene) है।

अंतरराष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस

- प्रत्येक वर्ष 5 मई को 'अंतरराष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस' (International Midwives Day) मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान महिला का ख्याल रखने वाली मिडवाइफ के समर्पण को सम्मान देना है।
- वर्ष 2024 मुख्य विषय (थीम)- 'Midwives: A Vital Climate Solution' है।

मिडवाइफ

- गर्भावस्था के दौरान महिला और जन्म के बाद कुछ दिनों तक बच्चे का पूरा ख्याल रखने वाली महिलाओं को 'मिडवाइफ' (Midwife) नाम दिया गया है।

विश्व एथलेटिक्स दिवस

- प्रत्येक वर्ष 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- वर्ष 2024 का मुख्य विषय (थीम) 'वर्ल्ड माइल चैलेंज' (World Mile Challenge) है।

एथलेटिक्स

- एथलेटिक्स मुख्यतः दौड़ने, कूदने, फेंकने और चलने की प्रतियोगिताओं का विशेष संग्रह है।
- इसके अंतर्गत सामान्य तौर पर ट्रैक और फील्ड, रोड रनिंग, क्रॉस कंट्री रनिंग और रेस वॉकिंग प्रतियोगिताओं को सम्मिलित किया जाता है।

विश्व थैलेसीमिया दिवस

- प्रत्येक वर्ष 8 मई को 'विश्व थैलेसीमिया दिवस' (World Thalassaemia Day) के रूप में मनाया जाता है।
- यह दिवस थैलेसीमिया रोग की रोकथाम के उपायों के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है।
- वर्ष 2024 का मुख्य विषय (theme)- 'जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना: सभी के लिए न्यायसंगत और सुलभ थैलेसीमिया उपचार.' (Empowering Lives, Embracing Progress: Equitable and Accessible Thalassaemia Treatment for All.) है।

थैलेसीमिया

- थैलेसीमिया एक रक्त संबंधी एक आनुवंशिक बीमारी (Chronic Blood Disorder) है।
- इस बीमारी से पीड़ित रोगी के लाल रक्त कणों (RBC) में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता जिसके कारण एनीमिया (रक्ताल्पता) हो जाता है।
- थैलेसीमिया से गंभीर रूप से पीड़ित रोगी को जीवित रहने के लिये अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (Bone Marrow Transplant) या नियमित रूप से रक्त चढ़ाए जाने की आवश्यकता होती है।

विश्व रेडक्रॉस दिवस

- प्रत्येक वर्ष 8 मई को 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' (Red Cross Day) के रूप में मनाया जाता है।
- यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित होते हैं।
- वर्ष 2024 का मुख्य विषय (theme) 'I give with joy, and the joy I give is a reward' है।
- विश्व रेडक्रॉस दिवस रेडक्रॉस के संस्थापक और शान्ति के लिए पहले नोबल पुरस्कार विजेता जॉन हेनरी डिनेट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जयंती

- 9 मई 2024 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती (Rabindranath Tagore Jayanti) मनाई गई।
- बंगाली कैलेंडर के अनुसार टैगोर की जयंती 9 मई को आती है, जबकि जार्जियन कैलेंडर के अनुसार से टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासाँको ठाकुरबाड़ी में हुआ था।
- उनके पिता देवेन्द्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी।

रविंद्रनाथ टैगोर

- रविंद्रनाथ टैगोर भारत के एकमात्र साहित्यकार हैं जिन्हें काव्यरचना 'गीतांजलि' के लिये वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था।
- वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय भी हैं।
- वह विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान हैं- भारत का राष्ट्र-गान 'जन गण मन' और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान 'आमार सोनार बांग्ला'।
- सन 1921 में कृषि अर्थशास्त्री लियोनार्ड एमहर्स्ट के साथ मिलकर उन्होंने अपने आश्रम के पास ही 'ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान' की स्थापना की थी, बाद में इसका नाम बदलकर श्रीनिकेतन कर दिया गया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

- प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- वर्ष 2024 की थीम "स्कूल टू स्टार्टअप्स - इंस्पायरिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट" है।
- यह दिवस भारत द्वारा किए गए सफल परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में और देश की तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने हेतु मनाया जाता है।
- पहला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई 1999 को मनाया गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय परिवार दिवस

- प्रत्येक वर्ष 15 मई को संपूर्ण विश्व में 'अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस' (International Day of Families) मनाया जाता है।
- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में परिवार की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- वर्ष 2024 का मुख्य विषय (Theme)- 'परिवार और जलवायु परिवर्तन' (Families and Climate Change) है।

अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस

- प्रत्येक वर्ष 16 मई को 'अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस' (International Day of Light) मनाया जाता है।
- यह दिवस विज्ञान, संस्कृति कला, शिक्षा और सतत विकास, और औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
- वर्ष 2024 का थीम 'हमारे जीवन में प्रकाश' (Light in Our Lives) है।
- यह दिवस भौतिकशास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेमन (Theodore Maiman) द्वारा लेजर के पहले सफल लेजर ऑपरेशन की सालगिरह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

सिक्किम स्थापना दिवस

- प्रत्येक वर्ष 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस (Sikkim Statehood Day) मनाया जाता है।
- सिक्किम 16 मई 1975 को भारतीय गणराज्य का 22वाँ राज्य बना था।
- 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय गणराज्य में 22वें सह-राज्य के रूप में शामिल किया गया।
- सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन (1975) से दिया गया।

राष्ट्रीय डेंगू दिवस

- प्रत्येक वर्ष 16 मई को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस (National Dengue Day) के रूप में मनाया जाता है।
- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डेंगू से बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है।
- वर्ष 2024 की थीम 'डेंगू की रोकथाम: सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी' (Dengue Prevention: Our Responsibility for a Safer Tomorrow) है।
- डेंगू एक विषाणु जनित (वायरस) रोग है। यह संक्रमित मादा एडीज मच्छर (Female Aedes Mosquito) के काटने से फैलता है।
- डेंगू होने पर व्यक्ति को तेज बुखार, शरीर में दर्द, आंखों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण हो सकते हैं। डेंगू के कारण खून में प्लेटलेट कम हो जाती है।

विश्व कृषि-पर्यटन दिवस

- प्रत्येक वर्ष 16 मई को विश्व कृषि-पर्यटन दिवस (World Agri-Tourism Day) मनाया जाता है।
- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कृषि और पर्यटन क्षेत्र को एकीकृत कर किसानों की आय में वृद्धि करना है।
- कृषि पर्यटन का आशय पर्यटन के उस रूप से है जिसमें ग्रामीण संस्कृति को पर्यटक आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस

- प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस (World Telecommunication and Information Society Day) मनाया जाता है।
- इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकियों द्वारा लाया गया सामाजिक परिवर्तनों की वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है।
- वर्ष 2024 मुख्य विषय (थीम) 'सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार' (Digital Innovation for Sustainable Development) है।

विश्व हाइपरटेंशन दिवस

- प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस (World Hypertension Day) मनाया जाता है।
- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पूरी दुनिया के लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है।
- वर्ष 2024 का मुख्य विषय (थीम)- 'अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें' (Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer) है।

विश्व एड्स वैक्सीन दिवस

- प्रत्येक वर्ष 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस (World AIDS Vaccine Day) मनाया जाता है।
- इसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में जाता है।

अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस

- प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (International Museum Day) मनाया जाता है।
- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना है।
- वर्ष 2024 की थीम- 'शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय' (Museums for Education and Research) है।

विश्व मधुमक्खी दिवस

- प्रत्येक वर्ष 20 मई को 'विश्व मधुमक्खी दिवस' (World Bee Day) मनाया जाता है।
- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मधुमक्खी और अन्य परागणकों के महत्व, तथा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- मधुमक्खियां सबसे बड़ी परागणकर्ता (Pollinator) हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व की लगभग 35% कृषि अभी भी परागणकों पर निर्भर है।
- वर्ष 2024 का मुख्य विषय (थीम)- 'मधुमक्खी युवाओं से जुड़ी हुई है' (Bee Engaged with Youth) है।
- यह दिवस 18वीं शताब्दी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जनसा (Antone Jansa) के जन्म दिन (20 मई) के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

विश्व मेट्रोलॉजी दिवस

- प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस (World Metrology Day) मनाया जाता है।
- इस दिवस को मनाये जाने का उद्देश्य मेट्रोलॉजी, माप के विज्ञान और इसके अनुप्रयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
- वर्ष 2024 का मुख्य विषय (theme) 'वहनीयता' (Sustainability) है।
- विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मीटर कन्वेंशन (Metre Convention) पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस कन्वेंशन पर 20 मई 1875 को हस्ताक्षर किया गया था।

राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस

- भारत में प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस (National Anti-Terrorism Day) मनाया जाता है।
- यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन मनाया जाता है।
- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से दूर रखना, शांति और मानवता का संदेश फैलाना और लोगों को जागरूक करना है।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय दिवस

- प्रत्येक वर्ष 21 मई को अन्तर्राष्ट्रीय चाय दिवस (International Tea Day) के रूप में मनाया जाता है।
- इस दिवस को मनाने का उद्देश्य चाय मजदूरों की काम की स्थिति, मजदूरों के अधिकार, दिहाड़ी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा को भी प्रोत्साहित करना है।
- अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस एक आदर्श वाक्य के साथ मनाया जाता है जो 'फील्ड से लेकर कप तक' (From Field to Cup) हैं।
- भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अन्तर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है।
- चीन दुनिया में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद भारत और केन्या हैं।

अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस

- जैव विविधता के मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है।
- यह जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय दिवस है।
- अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस (IDB) 2024 का विषय 'योजना का हिस्सा बनें' है।

विश्व भूखमरी दिवस

- यह प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य लाखों लोगों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है।
- वर्ष 2024 की थीम 'समृद्ध माताएँ समृद्ध विश्व' है।

संयुक्त राष्ट्र ने 24 मई को 'अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस' घोषित किया

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस (International Day of the Markhor) घोषित किया।
- मारखोर (कैप्रा फाल्कोनेरी) दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बकरी है।
- यह प्रजाति है जो अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है।
- भारत में, यह उप प्रजाति केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है।
- यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है।
- मारखोर को 2014 में IUCN की संकटापन्न प्रजातियों की रेड लिस्ट "नियर थ्रेटेन्ड" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूयॉर्क में महासभा की 80वें सत्र में 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस (World Football Day) के रूप में घोषित किया है।
- इस वर्ष इतिहास में खेले गए पहले अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ है।
- यह मैच 25 मई 1924 को पेरिस में आयोजित 1924 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में आयोजित हुआ था।
- इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के स्थायी प्रतिनिधि ताहेर एम. एल. सोनी ने यह संकल्प पेश किया है।

13

सार : योजना - कुरुक्षेत्र

योजना

बुनाई की जीवंत दुनिया: भारतीय बुनाई में क्षेत्रीय विविधता

भारत की कपड़ा ताने-बाने की कला क्षेत्रीय विविधता का एक अद्भुत प्रदर्शन है, जिसका प्रत्येक धागा उस भूमि की कहानियाँ सुनाता है जहाँ से वह आता है। केरल के पवित्रता के प्रतीक बेदाग सफेद कपड़ों से लेकर गुजरात की पटोला साड़ियों के जीवंत रंगों और जटिल डिजाइनों तक, भारतीय बुनाई वह जगह है जहाँ कलात्मक प्रतिभा गणितीय परिशुद्धता से मिलती है।

विरोधाभासों का एक चक्र:

- **दक्षिणी शान:** केरल के हथकरघा कारीगरों की विशेषता सफेद मुंडू वेष्टी, कसावु साड़ियाँ और धोती हैं, जो अक्सर चमकते हुए सुनहरे किनारों और अनोखे धारीदार सिरों से सजी होती हैं। उनके घरेलू लिनेन अपनी सघन बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं, जो तौलिये और चादरों के लिए एकदम उपयुक्त हैं।
- **तकनीकों का एक ताना-बाना:** उत्तर की ओर बढ़ते हुए, कर्नाटक में कपास और रेशम की बुनाई का खजाना है, जिसमें प्रतिष्ठित मोलकालमुरू और इलकल साड़ियाँ शामिल हैं, जबकि पड़ोसी गोवा अपनी अनूठी चेकर्ड बुनाई की कहानियाँ सुनाता है, जो इसके आकर्षक कपड़ा इतिहास की विरासत है। महाराष्ट्र अपने शाही पैठनी रेशम पर गर्व करता है, साथ ही वर्धा कपास के सांसारिक आराम और विदर्भ रेशम की चमकदार समृद्धि पर भी।
- **गुजरात: व्यापारी भावना:** गुजरात की प्रतिष्ठित पटोला साड़ियाँ, अपने जीवंत रंगों और बोल्ड ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध डबल इकत, राज्य की उद्यमशीलता की भावना को दर्शाती हैं। सूत, कपड़ा उद्योग का एक पावरहाउस, पावर लूम के साथ फलता-फूलता है, जो भारत के मशीनीकृत वस्त्रों में स्वतंत्रता के बाद के विकास का प्रमाण है।

रंगों का बहुरूपदर्शक:

- **राजस्थान: एक शाही पैलेट:** राजस्थान की वस्त्र विरासत उसके हाथ से बुने हुए कपड़ों, चमकीले रंग की दरियों (फर्श कवरिंग) और पारंपरिक रूप से बुने हुए सादे कपड़ों में निहित है। राज्य में मिल क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने वाले प्रिंटेड कपड़ों और पुरुषों के औपचारिक परिधानों में व्यापक वृद्धि देखी गई है।

- **उत्तर में बदलती परिस्थितियाँ:** पंजाब और हरियाणा की पारंपरिक बुनाई रोजमर्रा के पहनने और घरेलू उपयोग के लिनेन के लिए मजबूत कपड़ों पर केंद्रित थी। आजादी के बाद, इन क्षेत्रों में मशीन से बने बुने हुए कपड़ों और ऊनी कपड़ों की ओर रुझान देखा गया है।
- **हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर:** हिमालय में बसा हिमाचल प्रदेश अपने कुल्लू और किन्नौर शॉल, कंबल और सिर पर पहने जाने वाले कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो बेहतरीन ऊन से बनाए जाते हैं। जम्मू और कश्मीर को अपने शानदार पश्मीना शॉल, बेहतरीन कढ़ाई वाले ऊनी कपड़े और क्लासिक ट्वीड पर गर्व है।

केन्द्रीय केन्द्र और सांस्कृतिक राजधानियाँ:

- **मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़:** वस्त्र उद्योग का महाशक्ति: मध्य प्रदेश उत्कृष्ट माहेश्वरी और चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि छत्तीसगढ़ अपने टसर रेशम और सूती बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, तथा इनके संरक्षण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त है।
- **वाराणसी: जहां रेशम का आध्यात्मिकता से मिलन होता है:** उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, बनारसी रेशमी साड़ियों की शाश्वत सुंदरता का पर्याय है, जो जटिल डिजाइन और नाजुक कुशलता के साथ बुनी गई हैं।
- **पूर्वी शान:** टसर सिल्क और भागलपुर बुनाई के पुनरुद्धार के साथ बिहार में बुनाई को नया जीवन मिलता है। बंगाल ने कपास और रेशम बुनाई की अपनी विरासत को जारी रखते हुए परंपरा को आधुनिक प्रगति के साथ सहजता से मिश्रित किया है। ओडिशा की इकत साड़ियाँ और अद्वितीय टसर पैटर्न हमेशा प्रभावित करने में विफल नहीं होते हैं।
- **पूर्वोत्तर की समृद्ध ताने-बाने:** असम के मेखला चादर और मुगा रेशम इस क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं। मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में बुनाई की जीवंत ताने-बाने की झलक देखने को मिलती है, जो उनकी जनजातीय परंपराओं और क्षेत्रीय सौंदर्यबोध को दर्शाती है।
- **उत्तर और दक्षिण का मिलन बिंदु:** आंध्र प्रदेश की वेंकटगिरी और गडवाल साड़ियाँ उत्तर और दक्षिण भारतीय डिजाइन की संवेदनशीलता का सही मिश्रण दिखाती हैं। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकत साड़ियाँ,

अपने आकर्षक ज्यामितीय पैटर्न के साथ, किसी भी साड़ी पारखी के लिए जरूरी हैं।

- **तमिलनाडु की बुनाई के चमत्कार:** प्रसिद्ध कांचीपुरम सिल्क अपनी भव्य सीमाओं और मंदिरों से प्रभावित डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं। कालातीत तकनीकों में पारंपरिक कोरवाई और चेल्लेथा बुनाई विधियाँ शामिल हैं।

बुनकर की चुनौती:

- अपनी समृद्ध विरासत के बावजूद, पारंपरिक बुनाई चुनौतियों का सामना कर रही है। मशीनीकृत करघों और सस्ते कपड़ों के बढ़ते चलन से हथकरघों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। कम मांग और उच्च उत्पादन लागत के कारण बुनकर आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। इन सदियों पुरानी बुनाई तकनीकों को संरक्षित करना और उन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है।

भविष्य बुनना:

- फैशन के बदलते परिदृश्य में पश्चिमी परिधानों और सिले हुए कपड़ों के प्रति बढ़ती पसंद के कारण एक और चुनौती सामने आई है। हालांकि, बुनाई भारत की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग बनी हुई है।

धागों का उत्सव:

- **सांस्कृतिक विरासत:** बुना गया प्रत्येक धागा एक कहानी कहता है, जो उस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है।
- **कलात्मक अभिव्यक्ति:** बुनाई कलात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करती है, जिससे बुनकरों को अपनी रचनात्मकता को शानदार वस्त्रों में बदलने का अवसर मिलता है।
- **आर्थिक जीवनरेखा:** हथकरघा उद्योग ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- **वैश्विक मान्यता:** भारतीय वस्त्र देश की निर्यात क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इसकी वैश्विक सांस्कृतिक उपस्थिति को बढ़ाते हैं।

विरासत को संरक्षित करना:

- **बुनकरों को समर्थन:** बुनकरों को समर्थन देने और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
- **बाजार का विस्तार:** समकालीन फैशन में पारंपरिक बुनाई के उपयोग को प्रोत्साहित करने से घरेलू उपभोक्ताओं के बीच रुचि फिर से जागृत हो सकती है। मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश किया जा सकता है, जिससे वैश्विक दर्शकों के सामने भारतीय वस्त्रों की अनूठी शिल्पकला का प्रदर्शन किया जा सकता है।

- **नवाचार और अनुकूलन:** डिजाइनरों और बुनकरों के बीच सहयोग से पारंपरिक बुनाई की अभिनव और आधुनिक व्याख्याओं का निर्माण हो सकता है, जिससे लगातार विकसित हो रही फैशन की दुनिया में उनकी निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित हो सकती है। इसके अतिरिक्त, बुनाई की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने से पारंपरिक तरीकों के सार को संरक्षित करते हुए दक्षता और उत्पादकता में सुधार हो सकता है।

निष्कर्ष:

- भारत की बुनाई की जीवंत दुनिया इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक विरासत का प्रमाण है। पारंपरिक बुनाई के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करके और हथकरघा को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने और बुनकरों का समर्थन करने जैसे समाधानों को लागू करके, भारत इस सदियों पुरानी कला के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकता है। यह न केवल देश की सांस्कृतिक पहचान के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संरक्षित करेगा बल्कि बुनकरों को सशक्त भी बनाएगा और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान देगा। भारतीय वस्त्रों का भविष्य अतीत को गले लगाने और एक टिकाऊ और जीवंत भविष्य की ओर एक रास्ता बुनने में निहित है।

भारत की ताने-बाने की बुनाई: धागों में बुनी विरासत

- भारत में बुनाई महज शिल्प से कहीं बढ़कर है; यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इतिहास के रूप में कार्य करती है, जो राष्ट्र के ताने-बाने में जटिल रूप से बुनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता (3300-1300 ईसा पूर्व) के साक्ष्य इस परंपरा की प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं, जिसमें कपास की खेती और कपड़ा उत्पादन का दस्तावेजीकरण किया गया है। ऋग्वेद प्राचीन भारतीय समाज में बुनाई के महत्व को और रेखांकित करता है, जिसमें धार्मिक और औपचारिक सेटिंग्स में इस्तेमाल किए जाने वाले वस्त्रों का संदर्भ दिया गया है।

पौराणिक कथाएँ और इतिहास: आपस में जुड़े धागे

- भारतीय लोककथाएँ बुनाई को ईश्वरीयता से जोड़ती हैं। दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा की कथा इस शिल्प की पवित्र प्रकृति का उदाहरण है। पूरे इतिहास में, विभिन्न संस्कृतियों के आदान-प्रदान ने बुनाई की तकनीकों और रूपांकनों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। फारस के अचमेनिद साम्राज्य ने फारसी डिजाइन और तरीके पेश किए, जबकि मुगल काल में शाही संरक्षण द्वारा ब्रोकेड, मलमल और मखमल जैसे शानदार वस्त्रों का उत्कर्ष हुआ। औपनिवेशिक काल में कपड़ा निर्माण केंद्रों के विस्तार और यूरोपीय व्यापार नेटवर्क की स्थापना के साथ-साथ मशीनीकृत करघे और सिंथेटिक रंग आए।

क्षेत्रीय अभिव्यक्तियाँ: शैलियों का एक समन्वय

भारत में क्षेत्रीय बुनाई शैलियों और तकनीकों का एक समृद्ध इतिहास मौजूद है।

- **बनारसी** रेशम "श्रृंगार" (श्रृंगार) की अवधारणा को मूर्त रूप देता है, जो भव्य लालित्य और मुगल रूपांकनों से प्रेरणा लेकर तथा धातु के धागों से अलंकृत जटिल पैटर्न की विशेषता रखता है।
- **कांचीपुरम** रेशम, जो "धर्म" का प्रतिनिधित्व करता है, में समृद्ध बनावट, जीवंत रंग और बहुमूल्य धातुओं से बुनी गई विशिष्ट जरी की किनारी होती है।
- **पैठणी** बुनाई, जो "लक्ष्य" (आकांक्षा) का प्रतीक है, टेपेस्ट्री बुनाई पद्धति का उपयोग करके जीवंत रंगों और मोर की आकृतियाँ बनाने के लिए एक जटिल तकनीक का उपयोग करती है।
- **पटोला** शिल्प, "वसुधैव कुटुम्बकम्" (विश्व एक परिवार है) का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें जटिल ज्यामितीय पैटर्न और आकृतियाँ बनाने के लिए दोहरी इकत तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो सद्भाव और संतुलन का प्रतीक है।

आधुनिक व्याख्याएँ: एक टिकाऊ भविष्य

- सव्यसाची मुखर्जी, अनीता डोंगरे, राहुल मिश्रा, हिमांशु शनि और अनीथ अरोड़ा जैसे समकालीन भारतीय फैशन डिजाइनर पारंपरिक बुनकरों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। यह तालमेल पारंपरिक तकनीकों को आधुनिक डिजाइन संवेदनाओं के साथ जोड़ता है, वैश्विक अपील को बढ़ावा देता है और इस समृद्ध शिल्प विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। नैतिक प्रथाओं और स्थिरता को बढ़ावा मिल रहा है, निष्पक्ष व्यापार पहलों के साथ कारीगरों के लिए उचित मजदूरी और नैतिक कार्य स्थितियों को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, जैविक खेती, प्राकृतिक रंगों और पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों पर बढ़ते ध्यान का उद्देश्य बुनाई उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है।

महत्व और चुनौतियाँ: एक नाजुक संतुलन

- बुनाई अनगिनत कारीगरों और उनके परिवारों को सशक्त बनाती है, जिससे आय और आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत मिलता है। डिजाइनरों के साथ सहयोग पारंपरिक हथकरघा उत्पादों के लिए नए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोलता है। यह न केवल आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों तक बुनाई तकनीकों और विरासत के हस्तांतरण को सुनिश्चित करके सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने का भी काम करता है। वैश्विक मान्यता बुनाई समुदायों के भीतर सांस्कृतिक गौरव और पहचान को और मजबूत करती है।

- हालांकि, उद्योग चुनौतियों का सामना कर रहा है। बाजार की बदलती मांगों और बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा के अनुकूल होना महत्वपूर्ण है। कुशल बुनकरों की संख्या में गिरावट के कारण तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए हानिकारक रसायनों और अपशिष्ट उत्पादन पर निर्भरता को संबोधित करना आवश्यक है।

भविष्य को सुरक्षित करना: एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण

- कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देना तकनीकी कौशल को बढ़ाने और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है। कारीगरों को उद्यमशीलता कौशल से लैस करने से वे उभरते बाजार के रुझानों के अनुकूल बन सकेंगे और व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने वाली सहायक सरकारी नीतियाँ, बुनाई समुदायों को वित्तीय सहायता के साथ, दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, पारंपरिक कारीगरों को समकालीन डिजाइनरों से जोड़ने वाले सहयोगी मंच बनाने से नवाचार को बढ़ावा मिलता है और इस प्राचीन कला रूप की निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष: समय के साथ बुनी गई विरासत

- भारत में बुनाई केवल उत्पादन तक ही सीमित नहीं है; यह देश की परंपराओं, इतिहास और मूल्यों का जीवंत प्रमाण है। सदियों से चले आ रहे सांस्कृतिक आदान-प्रदान और समकालीन सहयोग के माध्यम से, भारतीय वस्त्रों का विकास जारी है, जो इस समृद्ध विरासत की कालातीत सुंदरता और शिल्प कौशल को संरक्षित करता है। वर्तमान चुनौतियों का समाधान करके और नवाचार को बढ़ावा देकर, भारत अपनी जीवंत बुनाई परंपरा का भविष्य सुनिश्चित कर सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी विरासत की गारंटी हो सके।

भारतीय बुनाई स्थिरता को बढ़ावा दे रही है

- स्थिरता पर बढ़ते वैश्विक फोकस के मद्देनजर, भारतीय हथकरघा वस्त्र फैशन उद्योग के भीतर एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभरे हैं। अपनी अनूठी शिल्पकला और गहरी सांस्कृतिक विरासत की विशेषता वाले ये बुने हुए कपड़े टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

समय में बुनी गई विरासत: ऐतिहासिक संदर्भ

- भारत में बुनाई की कला एक समृद्ध और प्राचीन विरासत समेटे हुए है, जिसमें सहस्राब्दियों से विभिन्न

क्षेत्रों में अलग-अलग परंपराएँ फल-फूल रही हैं। उदाहरणों में वाराणसी के जटिल ब्रोकेड और तेलंगाणा के जीवंत इकत शामिल हैं। कपास एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल, ने न केवल आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की है, बल्कि भारत की स्थायी कपड़ा विरासत के प्रतीक के रूप में भी उभरी है। भारतीय बुनाई से जुड़ी पारंपरिक शिल्पकला ने पीढ़ियों से आजीविका को बनाए रखा है और कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना जारी रखा है।

डिजाइन द्वारा टिकाऊ: पर्यावरण-अनुकूल प्रथाएँ

- भारतीय बुनाई स्वाभाविक रूप से टिकाऊ है क्योंकि वे कपास, रेशम, जूट और ऊन जैसे प्राकृतिक रेशों पर निर्भर हैं, जो सभी स्थानीय रूप से प्राप्त होते हैं। ये प्राकृतिक सामग्रियाँ बायोडिग्रेडेबल, नवीकरणीय हैं और जैव विविधता को बनाए रखने में योगदान देती हैं। पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक बुनाई तकनीकें बड़े पैमाने पर उत्पादन में इस्तेमाल की जाने वाली आधुनिक विधियों की तुलना में पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा, प्राकृतिक रेशों का उपयोग सिंथेटिक विकल्पों की तुलना में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है जो प्रदूषण और संसाधन की कमी में योगदान करते हैं।

स्थिरता को बढ़ावा देना: भारतीय कपास निगम (CCI) की भूमिका

- भारतीय कपास निगम (सीसीआई) कपास किसानों की आर्थिक भलाई की रक्षा करने तथा कपास की खेती और बुनाई में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- 'कस्तूरी कॉटन भारत' ब्रांड ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाता है ताकि एंड-टू-एंड ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित हो सके। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ती है बल्कि आपूर्ति श्रृंखला के भीतर विश्वास भी बढ़ता है।
- राष्ट्रीय ध्वज निर्माण के लिए कच्चे कपास की सतत खरीद सुनिश्चित करने के लिए सीसीआई खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ रणनीतिक सहयोग करता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन के माध्यम से, सीसीआई कपास किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, उन्हें बाजार की अस्थिरता से बचाता है और उचित मूल्य सुनिश्चित करता है।

चुनौतियाँ और अवसर: एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण

- अपनी अंतर्निहित स्थिरता के बावजूद, भारतीय हथकरघा वस्त्रों को बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्त्रों से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो बाजार पर हावी हैं।

इसके अलावा, बुनियादी ढांचे की कमी और युवा पीढ़ी के बीच घटती दिलचस्पी पारंपरिक बुनकर समुदायों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करती है।

- इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से आशाजनक समाधान मिलते हैं।
- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, जिसका उदाहरण शकस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड है, आपूर्ति श्रृंखला के भीतर पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता को बढ़ा सकती है।
- कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करना, पारंपरिक बुनकरों को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे उभरते बाजार के साथ तालमेल बिठा सकें और उसमें सफल हो सकें।
- डिजाइनरों, निगमों और सरकारी निकायों जैसे हितधारकों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना एक और महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। सहयोग करके, ये संस्थाएँ लक्षित विपणन अभियानों और अभिनव उत्पाद विकास के माध्यम से पारंपरिक बुनाई को बढ़ावा दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को सचेत विकल्प बनाने और स्थानीय हथकरघा उत्पादों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना पारंपरिक बुनाई समुदायों की निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

नैतिक आचरण और स्थिरता: एक सहजीवी संबंध

- नैतिक विचार टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के साथ जुड़े हुए हैं। निष्पक्ष व्यापार पहल जो बुनकरों के लिए उचित मजदूरी और नैतिक कार्य स्थितियों की गारंटी देती है, आवश्यक है। इसके अलावा, जैविक खेती प्रथाओं और प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा देने से कपड़ा उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

महत्व: स्थिरता से परे

- भारतीय हथकरघा वस्त्रों का प्रचार केवल स्थिरता के विचारों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह दृष्टिकोण लाखों कारीगरों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, के लिए महत्वपूर्ण आजीविका प्रदान करके आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है। बुनकरों का समर्थन स्थानीय बाजार विकास और आर्थिक विकास में योगदान देता है। इसके अलावा, यह पारंपरिक बुनाई तकनीकों की निरंतरता सुनिश्चित करके और भारत की समृद्ध विरासत की रक्षा करके सांस्कृतिक संरक्षण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। शकस्तूरी कॉटन भारत जैसी पहल भारतीय वस्त्रों के वैश्विक मूल्यांकन और प्रशंसा को बढ़ाती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर सांस्कृतिक गौरव और मान्यता को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष: एक टिकाऊ भविष्य बुनना

- संधारणीय प्रथाओं के माध्यम से भारतीय हथकरघा वस्त्रों को बढ़ावा देना सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और अधिक संधारणीय फैशन उद्योग में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। सीसीआई द्वारा की गई अभिनव पहल, जैसे ब्लॉकचेन-सक्षम ट्रेसिबिलिटी और केवीआईसी जैसे संगठनों के साथ सहयोग, भविष्य के लिए एक मॉडल के रूप में काम करते हैं। प्रौद्योगिकी, साझेदारी और नैतिक प्रथाओं के माध्यम से मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके, भारतीय हथकरघा वस्त्र एक संधारणीय भविष्य में फलते-फूलते रह सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी स्थायी विरासत सुनिश्चित हो सके।

भारतीय खादी स्वतंत्रता का प्रतीक

- खादी, हाथ से काता और बुना हुआ कपड़ा, महज कपड़े से कहीं आगे है; यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावना का प्रतीक है। चंपारण सत्याग्रह (1917) के दौरान महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय, खादी आत्मनिर्भरता और औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई।

ऐतिहासिक जड़ें: शोषित राष्ट्र

- चंपारण सत्याग्रह ने ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नील की खेती करने के लिए मजबूर किए गए भारतीय किसानों की दुर्दशा को उजागर किया। इस प्रणाली ने न केवल किसानों को गरीब बनाया बल्कि उन्हें किफायती तैयार कपड़े तक पहुंच से भी वंचित कर दिया। ब्रिटिश नीतियों ने स्थिति को और खराब कर दिया। भारत की ताकत, कच्चा कपास, इंग्लैंड को निर्यात किया गया, केवल महंगे तैयार उत्पादों के रूप में वापस लौटा। इन नीतियों ने भारत के एक बार संपन्न कपड़ा उद्योग को पंगु बना दिया, जो मोहनजो-दारो में पुरातात्विक खोजों और ऐतिहासिक विवरणों से स्पष्ट है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में अद्वितीय बुनाई, रंगाई और छपाई तकनीकें थीं, लेकिन औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में बिजली के करघों के उदय ने इन उद्योगों को कुचल दिया, जिससे लाखों भारतीय सूत कातने वाले और बुनकर बेरोजगार हो गए।

गांधी का दृष्टिकोण: कताई क्रांति

- 1908 में गांधी द्वारा चरखे की खोज महत्वपूर्ण थी। उन्होंने स्वराज (स्व-शासन) और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए एक उपकरण के रूप में इसकी क्षमता को पहचाना। कताई के पुनरुद्धार का उद्देश्य किसानों के लिए अतिरिक्त आय प्रदान करना और ब्रिटिश वस्त्रों पर निर्भरता कम करना था। गंगाबेन मजूमदार जैसी प्रमुख हस्तियों ने चरखे की पुनः खोज में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाई। गांधी के आश्रमों ने स्थानीय मिल मालिकों के सहयोग से बुनाई को बढ़ावा दिया।

दार्शनिक आधार: स्वदेशी और उससे आगे

- खादी स्वदेशी आंदोलन का केंद्रीय प्रतीक बन गई, जिसने आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव पर जोर दिया। प्रतीकवाद से परे, खादी ने एक स्थायी आर्थिक मॉडल पेश किया। विकेंद्रीकृत उत्पादन ने ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाया और समान आय वितरण को बढ़ावा दिया। हालाँकि, व्यापार प्रतिबंध और मूल्य हेरफेर सहित ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश कीं।

आधुनिक प्रासंगिकता: चुनौतियाँ और अवसर

- समकालीन युग में, खादी को बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्त्रों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। प्रामाणिकता को बनाए रखते हुए तकनीकों का आधुनिकीकरण करना एक चुनौती बनी हुई है। इन बाधाओं के बावजूद, खादी महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। यह न्यूनतम निवेश आवश्यकताओं के साथ, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा, खादी उत्पादन न्यायसंगत आय वितरण को बढ़ावा देता है।

सांस्कृतिक महत्व और आगे का रास्ता

- खादी भारत की सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम का एक सशक्त प्रतीक है। यह पारंपरिक वस्त्र ज्ञान और कौशल को संरक्षित करता है, तथा अतीत से जुड़ाव को बढ़ावा देता है।
- इसके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरणों जैसी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है।
- कौशल विकास कार्यक्रम दक्षता और गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं।
- खादी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियाँ और सब्सिडी के साथ-साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की पहल आवश्यक है।
- खादी को वैश्विक बाजारों में टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल कपड़े के रूप में स्थापित करने से नए अवसर मिलेंगे। इसके लाभों और विरासत को उजागर करने वाले उपभोक्ता जागरूकता अभियान भी महत्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष: धागों में बुनी विरासत

- गांधी द्वारा पोषित खादी की विरासत केवल कपड़े तक ही सीमित नहीं है। यह टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है। खादी को बढ़ावा देकर, भारत टिकाऊ विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, पारंपरिक शिल्प को संरक्षित कर सकता है, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बना सकता

है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान कर सकता है। खादी का समर्थन करना न केवल अतीत में बल्कि एक टिकाऊ और न्यायसंगत भविष्य में भी एक निवेश है।

कुरुक्षेत्र

हरित प्रौद्योगिकियाँ: वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ और आगे की राह

- पर्यावरण की गुणवत्ता और संसाधन दक्षता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए नवाचारों को शामिल करते हुए हरित प्रौद्योगिकियाँ एक स्थायी भविष्य प्राप्त करने के लिए सर्वोपरि हैं। वे जलवायु परिवर्तन और संसाधन की कमी की दोहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करते हैं। भारत अपनी विकासशील नीतियों और सुधारों के माध्यम से सक्रिय रूप से हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने का प्रयास कर रहा है, जो स्थिरता और आर्थिक विकास दोनों को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता को पहचानता है।

वर्तमान परिदृश्य: हरित समाधान अपनाना

- भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव देखा जा रहा है। राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी पहल इस प्रतिबद्धता का उदाहरण हैं।
- भवन निर्माण क्षेत्र हरित भवन डिजाइन को अपना रहा है, जिसमें ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता दी जाती है तथा टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग किया जाता है।
- परिवहन क्षेत्र में टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के विकास के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में भी वृद्धि हो रही है।
- अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों में प्रगति और टिकाऊ जल उपयोग प्रथाओं को अपनाना, हरित समाधान के क्षेत्र में भारत की प्रगति को और उजागर करता है।

चुनौतियों का सामना करना: हरित पथ पर बाधाएं

- महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए आवश्यक प्रारंभिक निवेश काफी अधिक हो सकता है, जो कुछ हितधारकों के लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। जटिल विनियामक ढाँचे इन प्रौद्योगिकियों के विकास और कार्यान्वयन में बाधा डाल सकते हैं। इसके अलावा, व्यापक रूप से अपनाने के लिए अधिक से अधिक सार्वजनिक जागरूकता और स्वीकृति को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। मौजूदा बुनियादी ढाँचा नई हरित प्रौद्योगिकियों के साथ आसानी से संगत नहीं हो सकता है, जिससे अनुकूलन की आवश्यकता होती है। नवीकरणीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन एक सतत चिंता का विषय बना हुआ है।

हरित लाभांश: एक बहुआयामी लाभ

हरित प्रौद्योगिकियाँ अनेक लाभ प्रदान करती हैं।

- नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में नए बाजारों और रोजगार के अवसरों के सृजन के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की क्षमता है।
- पर्यावरणीय लाभों में कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरणीय क्षरण में कमी शामिल है।
- हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने से सामाजिक सुधार हो सकते हैं, जैसे वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार, जिससे नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
- इसके अलावा, हरित प्रौद्योगिकियाँ व्यावसायिक नवाचार के लिए उत्प्रेरक का काम करती हैं तथा टिकाऊ उत्पादों और सेवाओं के विकास को बढ़ावा देती हैं।

मार्ग का निर्धारण: एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण

- मौजूदा चुनौतियों पर काबू पाने और हरित प्रौद्योगिकियों की क्षमता का पूर्ण दोहन करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है।
- वित्तीय प्रोत्साहन और सुव्यवस्थित विनियमनों सहित सहायक सरकारी नीतियाँ, गोद लेने की दरों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं।
- हरित प्रौद्योगिकियों के लाभों के बारे में जनता को शिक्षित करने और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जन जागरूकता अभियान आवश्यक हैं।
- नवाचार को बढ़ावा देने और हरित प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) में निवेश बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
- नई प्रौद्योगिकियों को समायोजित करने के लिए मौजूदा बुनियादी ढाँचे को उन्नत करना और अनुकूलित करना आवश्यक है।
- अग्रणी वैश्विक संस्थाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ज्ञान और संसाधनों को साझा करने का अवसर मिलता है, जिससे प्रगति में तेजी आती है।

निष्कर्ष: एक हरित अनिवार्यता

- हरित प्रौद्योगिकियाँ केवल एक विकल्प नहीं हैं; वे एक स्थायी भविष्य के लिए अनिवार्य हैं। पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करके, वे एक अधिक स्थायी और समृद्ध दुनिया की ओर एक मार्ग प्रदान करते हैं। हरित प्रौद्योगिकी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, जैसा कि इसकी नीतियों और पहलों से स्पष्ट है, वैश्विक स्थिरता प्रयासों में देश को एक संभावित नेता के रूप में स्थापित करती है। रणनीतिक निवेश, सहायक नीतियों और सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से मौजूदा चुनौतियों पर काबू पाना हरित प्रौद्योगिकियों की पूरी क्षमता को अनलॉक करने और सभी के लिए एक हरित भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना: भारत में हरित अपशिष्ट तकनीक को अपनाना

ग्रामीण भारत को अपशिष्ट प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। खुले में डंपिंग, जैविक ईंधन जलाना और अनुचित निपटान जैसी अप्रभावी प्रथाएँ पर्यावरण क्षरण में योगदान करती हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और आजीविका प्रभावित होती है। हरित अपशिष्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाना ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने, पर्यावरणीय खतरों को कम करने और शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने के लिए एक आशाजनक समाधान प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण 2070 तक एक परिपत्र अर्थव्यवस्था और शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

वर्तमान परिदृश्य: अपशिष्ट प्रबंधन संकट

- भारत में ग्रामीण कचरा प्रबंधन प्रणालियाँ काफी हद तक अविकसित हैं, जिसके कारण गंभीर पर्यावरणीय परिणाम सामने आते हैं। खुले में कूड़ा फेंकना, ई-कचरा और कृषि अवशेषों को जलाना और नदी प्रदूषण जैसी आम प्रथाएँ पर्यावरण क्षरण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। औपचारिक कचरा प्रबंधन बुनियादी ढाँचे की यह कमी शहरीकरण और कृषि व्यवसाय क्षेत्रों के विस्तार से और भी बढ़ जाती है, जिससे जैविक खेती की प्रथाओं और जैव विविधता को खतरा होता है। बाढ़ और सूखे जैसे जलवायु-प्रेरित खतरे, गरीबी और पलायन जैसी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के साथ मिलकर स्थिति को और जटिल बनाते हैं।

अपशिष्ट धाराएँ: चुनौतियों का एक स्पेक्ट्रम

- ग्रामीण अपशिष्ट उत्पादन में विविध प्रकार की सामग्रियाँ शामिल होती हैं, जिनमें ठोस अपशिष्ट (कृषि अवशेष और गीला अपशिष्ट), प्लास्टिक अपशिष्ट, खतरनाक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, तथा निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट शामिल हैं।

हरित समाधान: अपशिष्ट को अवसर में बदलना

- हरित अपशिष्ट प्रौद्योगिकी अपशिष्ट को मूल्यवान संसाधनों में बदलने का अवसर प्रदान करती है। इन प्रौद्योगिकियों को लागू करने से ऊर्जा पुनर्प्राप्ति और संसाधन पुनर्चक्रण में सुविधा हो सकती है, जिससे ग्रामीण समुदायों को आर्थिक लाभ मिल सकता है और साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव कम हो सकता है।
- **प्रभाव विश्लेषण:** हरित प्रौद्योगिकियाँ ग्रामीण भारत को सशक्त बना रही हैं
- **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन:** माइक्रो-हाइड्रो पावर (एमएचपी) और इसी तरह की प्रौद्योगिकियाँ ग्रामीण विकास पहलों को शक्ति प्रदान कर सकती हैं और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करके गरीबी को कम कर सकती हैं।

अपशिष्ट रूपांतरण प्रक्रियाएँ:

- तापीय रूपांतरण (भस्मीकरण, ताप-अपघटन, गैसीकरण) ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के साथ कुशल अपशिष्ट निपटान समाधान प्रदान करते हैं।
- **जैव-रासायनिक रूपांतरण** (खाद बनाना, अवायवीय पाचन) जैविक अपशिष्ट को खाद और बायोगैस में परिवर्तित करके, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाकर और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करके एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।
- **रासायनिक रूपांतरण** (बायोडीजल उत्पादन के लिए ट्रांस-एस्टरीफिकेशन) ग्रामीण जैवईंधन उत्पादन के लिए अवसर पैदा करते हैं।

वैश्विक सफलता की कहानियाँ:

- **अपशिष्ट गैसीकरण:** जापान, अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में कार्यान्वयन अपशिष्ट की मात्रा और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में गैसीकरण की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
- **अपशिष्ट से ऊर्जा समाधान:** ये प्रौद्योगिकियाँ जीवाश्म ईंधन के लिए एक स्थायी विकल्प प्रदान करती हैं, तथा ग्रामीण समुदायों के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं।

हरित प्रौद्योगिकी: ग्रामीण विकास के लिए उत्प्रेरक

- **पर्यावरणीय स्थिरता:** कम्पोस्ट और बायोगैस उत्पादन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर स्वच्छ पर्यावरण में योगदान करते हैं।
- **आर्थिक अवसर:** हरित अपशिष्ट प्रौद्योगिकियाँ, खाद, बायोगैस और संभावित रूप से जैव ईंधन की बिक्री के माध्यम से नए व्यावसायिक अवसर पैदा करके ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाती हैं।
- **जलवायु लचीलापन:** प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियाँ लैंडफिल और संबंधित मीथेन उत्सर्जन पर निर्भरता को कम करके जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन में योगदान देती हैं।
- **सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता:** हरित अपशिष्ट प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन से अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित ज्ञान और कौशल विकास को बढ़ावा देकर सामुदायिक स्वामित्व और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलता है।

अपनाने में बाधाएँ: स्थिरता की राह पर चुनौतियाँ

- **अनुचित निपटान से प्रदूषण:** कृषि अवशेषों, ई-कचरे और प्लास्टिक को खुले में जलाना वायु की गुणवत्ता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है।
- **बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ:** ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित बुनियादी ढाँचे और संसाधनों की उपलब्धता प्रभावी

अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन में बाधा डालती है।

- **जागरूकता का अभाव:** उचित अपशिष्ट निपटान प्रथाओं के बारे में अपर्याप्त जानकारी से पर्यावरण प्रदूषण और संबंधित स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं।

टिकाऊ समाधान: अंतर को पाटना

- **स्मार्ट अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली (एसडब्ल्यूएम):** वास्तविक समय डेटा संग्रह के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर से लैस स्मार्ट डिब्बे, अनुकूलित रसद के लिए जीपीएस-निर्देशित अपशिष्ट संग्रह वाहन और निरंतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए सौर-संचालित सेंसर जैसी सुविधाओं के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
- **सफल कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास:**
 - **राष्ट्रीय कार्यक्रम:** राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) और स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहल ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं।
 - **समुदाय-संचालित पहल:** स्थानीय स्तर पर कम्पोस्ट और जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने वाले स्वयं सहायता समूह अपशिष्ट में कमी और संसाधन पुनः प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

केस स्टडीज: अनुकरणीय मॉडल

- **हसीरू माने परियोजना, कर्नाटक:** यह परियोजना खाद के उत्पादन और बिक्री के माध्यम से हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाती है।
- **पुंसारी गांव, गुजरात:** इस गांव में अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र स्थानीय रूप से एकत्रित कचरे से बिजली पैदा करते हैं।
- **पिंड चक्र कार्यक्रम, पंजाब:** यह कार्यक्रम किसानों को बायोमास ऊर्जा उत्पादन के लिए कृषि अपशिष्ट एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

हरित प्रौद्योगिकियों का विस्तार: बाधाओं पर काबू पाने की रणनीतियाँ

- **कचरा बीनने वालों का सामाजिक समावेशन:** अपशिष्ट प्रबंधन श्रृंखला में कचरा बीनने वालों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना तथा कौशल विकास और आजीविका के अवसरों के माध्यम से उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना।
- **डिजिटल निगरानी:** IoT, मोबाइल एप्लिकेशन और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके अपशिष्ट संग्रह और निपटान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। अपशिष्ट की मात्रा और संरचना पर वास्तविक समय का डेटा अनुकूलित मार्ग नियोजन और संसाधन आवंटन की अनुमति देता है, जिससे संग्रह दक्षता में सुधार होता है और लागत कम होती है।

- **सामुदायिक शिक्षा:** जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आधार तैयार करना।

नीति और आगे की राह

- **सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण:** विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में ऊपर वर्णित सफल स्थानीय मॉडलों के प्रसार और अनुकरण को प्रोत्साहित करना।
- **ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना:** सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली नीतियों और पहलों का विकास करना, विशेष रूप से हरित अपशिष्ट प्रबंधन समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना।
- **पर्यावरणीय अन्याय को संबोधित करना:** ऐसी नीतियों को लागू करना जो अनुचित अपशिष्ट निपटान प्रथाओं से असमान रूप से प्रभावित हाशिए पर और दूरदराज के समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले पर्यावरणीय अन्याय को संबोधित करती हैं।
- **शहरी-ग्रामीण सामंजस्य:** अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित ज्ञान साझाकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संसाधन विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के बीच सामंजस्य नीतियों को बढ़ावा देना।
- **टिकाऊ ग्रामीण नगर पालिकाएँ:** टिकाऊ 'हरित' ग्रामीण नगर पालिकाओं की अवधारणा का समर्थन करना जो अपशिष्ट में कमी, संसाधन पुनर्प्राप्ति और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं।

निष्कर्ष: एक हरा-भरा और समावेशी भविष्य

- ग्रामीण भारत में हरित अपशिष्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाना और उनका विस्तार करना वित्तीय प्रोत्साहन और तकनीकी सहायता सहित सहायक नीतिगत ढाँचों पर निर्भर करता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी हरित अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन समाधानों को अपनाकर, भारत अपनी ग्रामीण आबादी के लिए हरित और अधिक समावेशी भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक सशक्तीकरण और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा मिलेगा।

रिमोट सेंसिंग और जीआईएस उपकरणों का उपयोग करके जैव विविधता संरक्षण

- जैव विविधता संरक्षण एक वैश्विक चुनौती है, जिसके लिए मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियों की आवश्यकता है। रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) की मदद से जैव विविधता का विस्तृत मानचित्रण और विश्लेषण संभव है, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जहां पहुंचना मुश्किल है।

- महाविविध देशों में से एक माना जाता है, जहाँ जीवन की एक समृद्ध तासीर मौजूद है। दुनिया के 2.4% भूभाग में 45,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियाँ और 91,000 जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, भारत को चार जैवविविधता हॉटस्पॉट द्वारा और भी अलग पहचान दी गई है: हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंदरलैंड। दस जैवभौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए, जिनमें से प्रत्येक की विशेषता अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियाँ हैं, भारत की जैवविविधता महत्वपूर्ण दबावों का सामना करती है। विखंडन, संसाधनों के अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियों और जलवायु परिवर्तन के कारण आवास की हानि पारिस्थितिक संतुलन और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को खतरे में डालती है।
- जैव विविधता का संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता नहीं है; यह सतत विकास का आधार है। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और उत्पादकता सुनिश्चित करती है, ऑक्सीजन उत्पादन, जल शोधन और परागण जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करती है, जो जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। पारिस्थितिक लाभों से परे, जैव विविधता आर्थिक और सामाजिक मूल्य प्रदान करती है। प्रत्यक्ष उपयोग से लकड़ी, भोजन, ईंधन की लकड़ी और चारा मिलता है, जबकि अप्रत्यक्ष लाभों में पर्यटन, सांस्कृतिक महत्व और वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल हैं।
- जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और समान लाभ साझाकरण को बढ़ावा देते हैं। आईयूसीएन रेड लिस्ट एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है, जो विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करती है और तत्काल संरक्षण कार्रवाई की आवश्यकता वाली प्रजातियों को उजागर करती है।

रिमोट सेंसिंग और जीआईएस: संरक्षण प्रयासों को सशक्त बनाना

- भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियाँ, विशेष रूप से सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करती हैं। सुदूर संवेदन परिदृश्य, क्षेत्रीय और वैश्विक पैमाने पर जैव विविधता पर डेटा प्रदान करता है। यह डेटा भूमि उपयोग पैटर्न, वन आवरण और वनस्पति स्वास्थ्य में परिवर्तनों की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। जीआईएस एक शक्तिशाली विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो स्थानिक डेटा के प्रबंधन, विश्लेषण और दृश्य को सक्षम बनाता है। वर्णनात्मक जानकारी के साथ स्थान डेटा को एकीकृत करके, जीआईएस जैव विविधता पैटर्न और प्रवृत्तियों के व्यापक विश्लेषण की अनुमति देता है।

ये भू-स्थानिक उपकरण संरक्षण प्रयासों में अनेक अनुप्रयोग प्रदान करते हैं:

- **संरक्षित क्षेत्रों का मानचित्रण और निगरानी:** प्रभावी संरक्षण प्रबंधन के लिए संरक्षित क्षेत्रों का सटीक चित्रण और निगरानी महत्वपूर्ण है।
- **आवास विखंडन और भूमि उपयोग परिवर्तन विश्लेषण:** सुदूर संवेदन डेटा आवास विखंडन और भूमि उपयोग परिवर्तनों की पहचान और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है, जिससे लक्षित संरक्षण हस्तक्षेप संभव हो पाता है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन:** जलवायु परिवर्तन के प्रतिक्रियास्वरूप प्रजातियों के वितरण पैटर्न में परिवर्तन की निगरानी, सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक है।
- **डेटा-संचालित संरक्षण योजना:** स्थानिक डेटा को पारिस्थितिकी जानकारी के साथ एकीकृत करने से डेटा-संचालित योजना बनाने और संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देने की सुविधा मिलती है।

चुनौतियाँ और अवसर: अंतर को पाटना

अपनी क्षमता के बावजूद, जैव विविधता संरक्षण में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस को अपनाने में चुनौतियाँ हैं:

- **तकनीकी बाधाएँ:** प्रौद्योगिकी की उच्च लागत और जटिलता, साथ ही डेटा व्याख्या के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता, व्यापक कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
- **कार्यान्वयन बाधाएँ:** सीमित बुनियादी ढांचे और उच्च-रिजॉल्यूशन डेटा तक अपर्याप्त पहुंच, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, रसद संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।
- **नीति और शासन:** सफल कार्यान्वयन के लिए सहायक नीतियाँ, वित्त पोषण तंत्र और हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक हैं।

चुनौतियों पर विजय पाना: एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण

- **क्षमता निर्माण:** भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना के साथ-साथ संरक्षणवादियों और स्थानीय समुदायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी कौशल अंतर को दूर कर सकते हैं।
- **नीतिगत समर्थन:** संरक्षण योजना में भू-स्थानिक उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करना और उन्हें राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों में एकीकृत करना महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप हैं।
- **तकनीकी प्रगति:** लागत प्रभावी और उपयोगकर्ता-अनुकूल भू-स्थानिक उपकरणों का विकास, वास्तविक समय निगरानी के लिए ड्रोन और उन्नत उपग्रह इमेजिंग के उपयोग को बढ़ावा देना, पहुंच और दक्षता को बढ़ा सकता है।

- **सामुदायिक भागीदारी:** भू-स्थानिक उपकरणों का उपयोग करके संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से स्वामित्व की भावना को बढ़ावा मिलता है और उन्हें अपनी प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है।

मामले का अध्ययन

- **हसीरू माने परियोजना, कर्नाटक :** अपशिष्ट प्रबंधन और समुदाय-नेतृत्व वाली खाद बनाने के लिए भू-स्थानिक उपकरणों का उपयोग।
- **पुंसारी गांव, गुजरात:** गांव के कचरे से बिजली पैदा करना, कचरे से ऊर्जा बनाने की पहल का प्रदर्शन करना।
- **पिंड चक्र कार्यक्रम, पंजाब:** बायोमास ऊर्जा उत्पादन के लिए कृषि अपशिष्ट संग्रहण का पारिश्रमिक देना।

आगे की ओर देखना: एक टिकाऊ भविष्य

- पारिस्थितिकी संतुलन और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण है। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस उपकरण जैव विविधता के मानचित्रण, निगरानी और प्रबंधन के लिए शक्तिशाली साधन प्रदान करते हैं। तकनीकी, कार्यान्वयन और नीतिगत चुनौतियों का समाधान करके और सरकार, प्रौद्योगिकी डेवलपर्स और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत प्रभावी जैव विविधता संरक्षण के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों की पूरी क्षमता का दोहन कर सकता है।

सतत जल प्रबंधन में हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग

- जल की कमी एक बढ़ती हुई वैश्विक चिंता है, जिसके लिए स्थायी जल प्रबंधन के लिए अभिनव समाधानों की आवश्यकता है। पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी दृष्टिकोणों को शामिल करने वाली हरित प्रौद्योगिकियाँ इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण संभावनाएँ प्रदान करती हैं। पानी की भारी कमी का सामना कर रहे बंगलुरु जैसे शहर इन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर जल संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन से बहुत लाभ उठा सकते हैं।

सतत जल प्रबंधन: एक एकीकृत दृष्टिकोण

- संधारणीय जल प्रबंधन जल को एक परस्पर जुड़ी प्रणाली के रूप में देखता है, जिसमें पीने का पानी, अपशिष्ट जल, वर्षा जल और तूफानी जल निकासी शामिल है। भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घट रही है, जिससे मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को पाटने के लिए संधारणीय प्रथाओं की ओर बदलाव की आवश्यकता है। कुशल जल प्रबंधन आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह के लाभ प्रदान करता है। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, जल की कमी से

2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में 6% की कमी आ सकती है, जबकि स्वच्छ जल तक पहुँच सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मौलिक है।

वर्तमान जल प्रबंधन चुनौतियाँ

भारत में सतत जल प्रबंधन में कई चुनौतियाँ बाधा डालती हैं:

- **सीमित आपूर्ति वृद्धि:** जल आपूर्ति बढ़ाने के पारंपरिक तरीके अपनी सीमा तक पहुँच रहे हैं।
- **गिरता जल स्तर:** भूजल संसाधनों के अत्यधिक दोहन से जल स्तर में गिरावट आ रही है।
- **जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दे:** विभिन्न स्रोतों से होने वाले प्रदूषण के कारण जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
- **जलवायु परिवर्तन प्रभाव:** वर्षा के बदलते पैटर्न और चरम मौसम की घटनाओं से जल सुरक्षा को खतरा है।

हरित प्रौद्योगिकी: आगे की ओर एक आशाजनक रास्ता

- हरित प्रौद्योगिकी एक अनूठा लाभ प्रदान करती है: इन्हें पर्यावरण और आर्थिक रूप से कुशल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रौद्योगिकियाँ पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती हैं जबकि जल प्रबंधन के लिए लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख नवाचार दिए गए हैं:
- **वर्षा जल संचयन:** बाद में उपयोग के लिए वर्षा जल को एकत्रित करना और संग्रहीत करना, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में लाभदायक।
- **तूफानी जल प्रबंधन:** जल निकायों में प्रवेश करने से पहले प्रदूषकों को हटाने के लिए तूफानी जल अपवाह का उपचार करना।
- **उन्नत अपशिष्ट जल उपचार:** प्रभावी अपशिष्ट जल उपचार के लिए सूक्ष्मजीवों द्वारा संचालित बायोरिएक्टर और बायोफिल्टर का उपयोग करना।

वैश्विक सफलता की कहानियाँ:

- **सिंगापुर की डीप टनल सीवरेज प्रणाली (DTSS):** यह व्यापक प्रणाली उपयोग किए गए जल प्रबंधन के लिए ऊर्जा-कुशल पंप, उन्नत झिल्ली बायोरिएक्टर और सह-उत्पादन संयंत्रों का उपयोग करती है। कैं न केवल ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, बल्कि अपशिष्ट जल उपचार के माध्यम से संसाधन पुनर्प्राप्ति को भी बढ़ावा देता है।
- **वेरिबी ट्रीटमेंट प्लांट, मेलबर्न:** यह प्लांट सिंचाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पुनर्नवीनीकृत जल का उत्पादन करने के लिए उन्नत तृतीयक उपचार प्रक्रियाओं का लाभ उठाता है, जिससे मीठे जल संसाधनों पर निर्भरता कम होती है।

चुनौतियाँ और अवसर

अपनी क्षमता के बावजूद, हरित प्रौद्योगिकियों को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है:

- **तकनीकी चुनौतियाँ:** इन प्रौद्योगिकियों का क्रियान्वयन महंगा और जटिल हो सकता है, जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण और विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी।
- **कार्यान्वयन चुनौतियाँ:** ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित बुनियादी ढांचे और उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की कमी से रसद संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **नीति और शासन संबंधी मुद्दे:** व्यापक रूप से अपनाने के लिए सहायक नीतियाँ और पर्याप्त वित्तपोषण तंत्र आवश्यक हैं। प्रभावी हितधारक समन्वय भी महत्वपूर्ण है।

सतत जल प्रबंधन की ओर बढ़ना

- **क्षमता निर्माण:** स्थानीय समुदायों सहित हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के साथ मिलकर कौशल अंतर को दूर किया जा सकता है।
- **नीतिगत समर्थन:** वित्तीय प्रोत्साहन, विनियामक ढांचे, तथा राष्ट्रीय जल प्रबंधन नीतियों में हरित प्रौद्योगिकी पहलों का एकीकरण, अपनाने को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।

- **तकनीकी उन्नति:** लागत प्रभावी और उपयोगकर्ता-अनुकूल हरित प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ-साथ जल प्रबंधन प्रक्रियाओं में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ावा देने से पहुंच और स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है।
- **सामुदायिक भागीदारी:** जल प्रबंधन पहल में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और हरित प्रौद्योगिकियों के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

- जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाना महत्वपूर्ण है। तकनीकी, कार्यान्वयन और नीतिगत चुनौतियों का समाधान करके और सरकार, प्रौद्योगिकी डेवलपर्स और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत जल-सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। हरित प्रौद्योगिकियाँ कुशल जल प्रबंधन की दिशा में एक मार्ग प्रदान करती हैं, जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती हैं।

14

आलेख

1. आपदा प्रबंधन के लिए भारत का बहुआयामी दृष्टिकोण

- भारत का विशाल भूभाग इसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के लिए उजागर करता है। चक्रवातों और बाढ़ से लेकर भूकंप और सूखे तक, देश ने प्रकृति के प्रकोप का खामियाजा भुगता है। इसके निवारण हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की स्थापना की गई थी, जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसम की घटनाओं और बहु-खतरे वाले परिदृश्यों सहित आपदाओं की बदलती प्रकृति, एक सक्रिय रणनीति की मांग करती है।
- 2005 का आपदा प्रबंधन अधिनियम राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर बहु-स्तरीय संस्थागत प्रतिक्रिया के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। NDMA नीतियाँ बनाता है और उन्हें क्रियान्वित करता है, जबकि राज्य और जिला प्राधिकरण योजनाओं को लागू करते हैं और विकास में शमन उपायों को एकीकृत करते हैं। स्थानीय निकाय क्षमता निर्माण और राहत प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहायक संस्थानों में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) शामिल हैं।
- भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (SFDRR) और ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (HFA) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षरकर्ता है, जो व्यवस्थित और स्थायी जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों पर जोर देता है।

प्रमुख आपदाएँ:

- बाढ़ (जैसे, बिहार 2023, असम 2022) 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को प्रभावित करती है।
- चक्रवात और तूफान (जैसे, चक्रवात बिपरजॉय 2023, चक्रवात फैनी 2019) भारत की विस्तृत तटरेखा को खतरे में डालते हैं।
- भूकंप (जैसे, मिजोरम 2022, सिक्किम 2011) भारत की भूकंपीय गतिविधि के कारण जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- अनियमित वर्षा के कारण सूखा (जैसे, महाराष्ट्र 2024) 68% कृषि योग्य भूमि को प्रभावित करता है।
- पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन (जैसे, हिमाचल प्रदेश 2023, मणिपुर 2022) आम हैं।
- हीट वेव एक बढ़ता हुआ खतरा है, 2022 में 280 हीट

वेव वाले दिन दर्ज किए गए हैं। जंगल की आग (जैसे, हिमाचल प्रदेश 2024, गोवा 2023) जंगलों और वायु गुणवत्ता को खतरे में डालती है। औद्योगिक दुर्घटनाएँ (जैसे, सूरत रासायनिक रिसाव 2023, मुंबई औद्योगिक आग 2024) खतरनाक सामग्रियों से होने वाले जोखिम को उजागर करती हैं।

बढ़ाने वाले कारक:

- तेजी से शहरीकरण और अनियोजित विकास असमानता को बढ़ाता है, जैसा कि 2023 में चेन्नई बाढ़ में देखा गया था।
- जलवायु परिवर्तन से चक्रवात की उत्पत्ति जैसे 2020 में अम्फान।
- अपर्याप्त रखरखाव के साथ पुराना बुनियादी ढांचा आपदा जोखिम को बढ़ाता है।
- वनों की कटाई, खनन और अस्थिर भूमि उपयोग प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण का क्षरण भूस्खलन और मिट्टी के कटाव के जोखिम को बढ़ाता है।
- औद्योगिकीकरण और खतरनाक सामग्रियों पर निर्भरता दुर्घटनाओं के जोखिम को बढ़ाती है।

समाधान

- मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ समर्पित आपदा प्रतिक्रिया गलियारे विकसित करें। भूकंप, आग और हवा प्रतिरोधी सामग्रियों का उपयोग करके आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दें। कृषि में सूखा प्रतिरोधी फसलों, सटीक खेती और मृदा संरक्षण को प्रोत्साहित करें।
- पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण और सतत प्रबंधन (इको-डीआरआर) को आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों में एकीकृत करें।
- उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बहु-खतरे की प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करें।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए स्थानीयकृत, नवीकरणीय-संचालित माइक्रोग्रिड लागू करें।
- पीड़ितों की सहायता के लिए आपदा प्रतिक्रिया में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करें।
- एक स्थायी आपदा प्रबंधन कार्यबल का निर्माण करें और स्थानीय निकायों को पर्याप्त आपदा तत्परता रिजर्व आवंटित करें।
- तैयारियों को प्राथमिकता देने, संस्थानों को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाले बहु-आयामी दृष्टिकोण को अपनाकर, भारत इन मौजूदा खतरों की चुनौतियों से निपट सकता है।

2. भारत की रक्षा रणनीति को बढ़ाना: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की भूमिका और चुनौतियाँ

भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए स्थायी और महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के निर्माण का उद्देश्य युद्ध दक्षता को बढ़ाना और नई तकनीकी-रणनीतिक चुनौतियों से निपटना था, लेकिन परिणाम मिश्रित रहे हैं।

सीडीएस की नियुक्ति के पीछे तर्क:

- **संयुक्तता को बढ़ावा देना:** सीडीएस सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच एकीकृत योजना और संसाधन अनुकूलन की कमी के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को संबोधित करता है। उदाहरण के लिए, 1999 के कारगिल युद्ध ने बेहतर समन्वय की आवश्यकता को उजागर किया।
- **एकल सैन्य सलाहकार:** सीडीएस सरकार को एकीकृत सैन्य सलाह प्रदान करता है, जो नागरिक-सैन्य अंतर को कम करता है। पहले, सरकार को तीनों सेना प्रमुखों से परस्पर विपरीत सलाह मिलती थी।
- **ऑपरेशनल तालमेल बढ़ाना:** सीडीएस ऑपरेशन के दौरान सेवाओं के बीच अधिक तालमेल और अंतर-संचालन को बढ़ावा देता है। बेहतर समन्वय 2004 की सुनामी राहत प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता था।
- **संसाधन आवंटन:** संयुक्त कौशल को बढ़ावा देकर, सीडीएस का उद्देश्य रक्षा व्यय को युक्तिसंगत बनाना और संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है।
- **रणनीतिक बल प्रबंधन:** सीडीएस दीर्घकालिक रक्षा योजना, रक्षा संरचना और क्षमता विकास की देखरेख करता है ताकि सैन्य तैयारियों को भावी चुनौतियों के साथ जोड़ा जा सके।

सीडीएस पद के निर्माण हेतु किए गए प्रयास:

- 1999: कारगिल समीक्षा समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे की समीक्षा की सिफारिश की।
- 2001: मंत्रियों के एक समूह ने सीडीएस पद बनाने की सिफारिश की।
- 2001-2019: सिफारिशों के बावजूद, राजनीतिक इच्छाशक्ति और आम सहमति की कमी के कारण पद नहीं बनाया गया।
- 2019: 24 दिसंबर को सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने सीडीएस के निर्माण को मंजूरी दी। जनरल बिपिन रावत को 31 दिसंबर को पहला सीडीएस नियुक्त किया गया। सैन्य मामलों का विभाग भी बनाया गया।
- 2022: लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को 28 सितंबर को सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया।

सीडीएस कार्यालय के समक्ष चुनौतियाँ:

- **आकस्मिक व्यवधान:** दिसंबर 2021 में जनरल बिपिन रावत की मृत्यु ने निरंतरता और प्रभावशीलता को बाधित किया।
- **जिम्मेदारियों का बोझ:** सीडीएस को सौंपी गई भूमिकाओं की विस्तृत श्रृंखला संयुक्त परिचालन तालमेल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने से विचलित कर सकती है।
- **आम सहमति का अभाव:** सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच अलग-अलग प्राथमिकताएँ और दृष्टिकोण सीडीएस की कार्यक्षमता में बाधा डालते हैं।

उभरती रक्षा चुनौतियाँ:

- **दो-मोर्चे का खतरा परिदृश्य:** चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे सीमा तनाव के कारण समन्वित सैन्य तैयारियाँ आवश्यक हैं।
- **हाइब्रिड युद्ध और सीमा पार आतंकवाद:** हाइब्रिड युद्ध की चुनौती के लिए एक व्यापक और बहुआयामी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
- **समुद्री सुरक्षा:** भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाएँ एक मजबूत, एकीकृत समुद्री रणनीति की माँग करती हैं।
- **सैन्य आधुनिकीकरण:** प्रभावी सैन्य आधुनिकीकरण के लिए दोहराव से बचना और अंतर-संचालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **अंतरिक्ष सुरक्षा:** अंतरिक्ष सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतरिक्ष-विरोधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए समन्वित प्रयास महत्वपूर्ण हैं।
- **आर्कटिक और अंटार्कटिक ऑपरेशन:** जलवायु परिवर्तन के कारण इन क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए संयुक्त रक्षा क्षमताओं को विकसित करना आवश्यक हो गया है।

सशस्त्र बलों के एकीकरण को बढ़ाने के उपाय:

- **भूमिका स्पष्टता:** सीडीएस और सेवा प्रमुखों के बीच भूमिकाओं को सुव्यवस्थित करने से स्पष्ट कमान और नियंत्रण सुनिश्चित होता है।
- **एकीकृत थिएटर कमांड:** एकीकृत थिएटर कमांड के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने से संयुक्त कौशल और संसाधन अनुकूलन को बढ़ावा मिलता है।
- **क्वांटम-सुरक्षा संचार:** क्वांटम-सुरक्षा नेटवर्क विकसित करने से संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए अत्यधिक सुरक्षित संचार चैनल सुनिश्चित होते हैं।
- **भारत की रक्षा रणनीति को इन उभरती चुनौतियों से निपटने तथा अपने सशस्त्र बलों के एकीकरण और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विकसित किया जाना चाहिए।**

3. भारत में जंगल की आग से निपटना: चुनौतियाँ और पहल

उत्तराखंड में लगी विनाशकारी जंगल की आग ने उनके कारण होने वाले व्यापक विनाश को उजागर किया है। भारत में जंगल की आग मुख्य रूप से अप्रैल और मई के बीच शुष्क मौसम के दौरान होती है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी आवृत्ति बढ़ गई है, जिससे यह एक प्रमुख पर्यावरण पीय चिंता बन गई है।

वन की आग क्या है? भारत में वन की आग की स्थिति क्या है?

- वन की आग एक अनियंत्रित आग है जो जंगलों के बड़े हिस्से को नष्ट कर देती है। भारत में, वन की आग का मौसम नवंबर से जून तक होता है, जिसका चरम मौसम फरवरी के अंत में शुरू होता है और लगभग 12 सप्ताह तक रहता है। भारत राज्य वन रिपोर्ट (ISFR) 2019 के अनुसार, भारत का 21.67% भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है। असम, मिजोरम और त्रिपुरा के जंगलों को 'अत्यधिक आग-प्रवण' के रूप में पहचाना जाता है, विशेष रूप से शुष्क पर्णपाती वन।

भारत में जंगल में आग लगने के प्रमुख कारण:

- भारत में जंगल में आग लगने के पीछे प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारण हैं:

प्राकृतिक कारण:

- बिजली गिरना:** बिजली गिरने से निकलने वाली चिंगारी जंगल में आग लगा सकती है।
- ज्वालामुखी विस्फोट:** विस्फोट से निकलने वाला गर्म लावा जंगलों में बह सकता है, जिससे आग लग सकती है।
- गर्मी के प्रारूप:** ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि से जंगल अधिक असुरक्षित हो जाते हैं।
- मिट्टी में नमी की कमी:** उत्तराखंड में देखी गई सूखी मिट्टी की स्थिति आग लगा सकती है।
- प्राकृतिक सामग्री:** सूखी लकड़ी, पत्तियों और घास की बहुतायत आग को बढ़ावा देती है।

मानवजनित कारण:

- धूम्रपान:** फेंके गए सिगरेट के बट जंगल में आग लगा सकते हैं।
- कैम्पफायर:** बाहरी गतिविधियों के दौरान बिना देखरेख के आग लगने से आग लग सकती है।
- मलबा जलाना:** कचरे को जलाने से जंगल में आग लग सकती है, जैसा कि हाल ही में सिमलीपाल जंगल में लगी आग में हुआ था।
- झूमिंग कृषि:** यह प्रथा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक प्रमुख कारण है।

वसंत ऋतु के दौरान प्रमुख वन आग की घटनाओं का

क्या कारण है?

मार्च और अप्रैल के बीच होने वाले वसंत में भारत में वनों में आग लगने की घटनाएं चरम पर होती हैं, क्योंकि:

- सर्दियों के दौरान कम वर्षा:** मिट्टी की नमी कम होने से वन अधिक ज्वलनशील हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हाल ही में उत्तराखंड में लगी आग है।
- ज्वलनशील पदार्थों की उपलब्धता:** सूखी लकड़ी और पत्तियाँ तेज हवाओं के कारण आग की तीव्रता को बढ़ाती हैं।

भारत में वनों की आग का प्रभाव:

- पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का नुकसान:** आग से आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता का नुकसान होता है।
- वनों का क्षरण:** आग से मिट्टी की उर्वरता और पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता कम हो जाती है।
- आजीविका पर प्रभाव:** वन कई लोगों की आजीविका का आधार हैं; आग से यह बाधित होता है।
- वायु प्रदूषण:** आग से कार्बन अवशोषण कम होता है और बड़े पैमाने पर धुएँ के बादल बनते हैं।
- मिट्टी का क्षरण:** आग से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और कटाव होता है।
- वाटरशेड का विनाश:** आग से वनों के भीतर आर्द्रभूमि क्षेत्रों को नुकसान पहुँचता है।

भारत में जंगल की आग के लिए सरकारी पहल:

- वन अग्नि चेतावनी प्रणाली (FFAS):** भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा वास्तविक समय में जंगल की आग की निगरानी के लिए विकसित की गई है।
- MODIS सेंसर:** ये सेंसर वास्तविक समय में जंगल की आग की जानकारी प्रदान करते हैं, जिसे SMS अलर्ट के माध्यम से स्थानीय समुदायों को विभिन्न स्तरों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।
- वन अग्नि नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान:** एक समन्वित और एकीकृत अग्नि प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करने का लक्ष्य रखता है।

वन की आग को कम करने के लिए आगे की राह:

- वन की आग को कम करने के लिए, निम्नलिखित कदम सुझाए गए हैं:**
- क्षमता विकास:** सभी स्तरों पर वन विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।
- वन नियंत्रण नियमावली:** प्रारंभिक पहचान और नियंत्रण के लिए नियमावली बनाना।
- व्यापक वन अग्नि नीति:** एक ऐसी नीति तैयार करना जिसमें जलवायु परिवर्तन के पहलुओं को शामिल किया गया हो।
- स्वदेशी ज्ञान:** अग्नि प्रबंधन में स्थानीय और आदिवासी ज्ञान का उपयोग करना।

- **बुनियादी ढांचे का निर्माण:** अग्निशमन कर्मचारियों की संख्या में सुधार, वॉचटावर का निर्माण और अग्नि निरीक्षकों को काम पर रखना।
- **प्रौद्योगिकी का विकास:** आधुनिक अग्निशमन तकनीकों को अपनाना और राष्ट्रीय अग्नि खतरा रेटिंग प्रणाली (NFDRS) और अग्नि पूर्वानुमान प्रणाली जैसी प्रणालियों का विकास करना।

इन उपायों को लागू करके, भारत जंगल की आग की घटनाओं और प्रभावों को बेहतर ढंग से प्रबंधित और कम कर सकता है।

4. चुनावों में डीपफेक: निहितार्थ और समाधान

चुनावी प्रक्रियाओं में डीपफेक का बढ़ना महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। पारंपरिक गलत सूचना के विपरीत, डीपफेक वास्तविकता और मनगढ़ंत जानकारी के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं, जिससे जानकारी की पुष्टि करने के लिए हमारे विश्लेषण और तकनीकी समाधानों पर भरोसा करने की हमारी क्षमता कम हो जाती है।

डीपफेक क्या हैं?

- डीपफेक कृत्रिम मीडिया हैं जो व्यक्तियों को धोखा देने के लिए दृश्य और ऑडियो सामग्री में हेरफेर या उत्पन्न करने के लिए AI तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं।

उत्पत्ति:

- "डीपफेक" शब्द 2017 में एक अज्ञात Reddit उपयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न गया था, जिसने अश्लील वीडियो बनाने और साझा करने के लिए Google की डीप-लर्निंग तकनीक का उपयोग किया था।

निर्माण:

- डीपफेक 'जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क (GAN)' का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जिसमें एक जनरेटर (नकली चित्र या वीडियो बनाना) और एक डिस्क्रिमिनेटर (वास्तविक और नकली सामग्री के बीच अंतर करना) शामिल होता है। इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है, जिसे अक्सर सहमति के बिना प्राप्त किया जाता है।

चुनावों में डीपफेक के लाभ

- **विभाजन और लक्ष्यीकरण:** डीप लर्निंग एल्गोरिदम राजनीतिक दलों को जनसांख्यिकी और सोशल मीडिया जुड़ाव सहित व्यापक मतदाता डेटा का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। एनएलपी एल्गोरिदम अभियानों को मतदाताओं को प्रभावी ढंग से लक्षित करने के लिए बड़ी मात्रा में पाठ्य डेटा की व्याख्या करने में सक्षम बनाता है।
- **वास्तविक समय की निगरानी और अनुकूलन:** एआई-संचालित पूर्वानुमान विश्लेषण, जैसे कि एआई

क्लाउड, पार्टियों को मतदान डेटा, आर्थिक संकेतक और सोशल मीडिया भावना का विश्लेषण करके चुनाव परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की अनुमति देता है। एआई एल्गोरिदम सार्वजनिक भावना को मापने और रुझानों की पहचान करने के लिए लगातार डेटा स्रोतों को स्कैन करते हैं।

- **सुरक्षा और अखंडता:** एआई-संचालित डीपफेक उपकरण मतदाता दमन और मतदान प्रणालियों में हेरफेर सहित चुनावी धोखाधड़ी का पता लगाते हैं और उसे रोकते हैं। वे चुनाव की अखंडता को बनाए रखने के लिए डेटा पैटर्न का विश्लेषण करते हैं।

चुनावों में डीपफेक की चुनौतियाँ

- **चुनावी व्यवहार में हेरफेर:** डीपफेक अत्यधिक व्यक्तिगत प्रचार कर सकते हैं, जिससे मतदाताओं में हेरफेर और भ्रम पैदा हो सकता है। एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो विरोधियों की छवि को खराब कर सकते हैं, जिससे मतदाता की धारणा प्रभावित होती है।
- **गलत सूचना फैलाना:** डीपफेक मॉडल गलत सूचना फैलाकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हेरफेर कर सकते हैं, जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा गया था, जहाँ महात्मा गांधी की क्लोन आवाज ने एक राजनीतिक दल के लिए प्रचार किया था।
- **अशुद्धियाँ और अविश्वसनीयता:** डीपफेक AI मॉडल में अशुद्धियाँ होने की संभावना होती है, जिससे उनकी विश्वसनीयता के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं। व्यक्तियों को गलत तरीके से पेश करने वाले AI मॉडल के उदाहरण अनियंत्रित AI के खतरों को उजागर करते हैं।
- **नैतिक चिंताएँ:** डीपफेक गोपनीयता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के बारे में नैतिक मुद्दे उठाते हैं। AI एल्गोरिदम पक्षपात को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे मतदाता समूहों के साथ अनुचित व्यवहार हो सकता है। AI निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी से जनता का विश्वास कम हो सकता है।
- **नियामक चुनौतियाँ:** तेजी से तकनीकी प्रगति और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वैश्विक प्रकृति डीपफेक को विनियमित करना मुश्किल बनाती है। मौजूदा कानून फर्जी खबरों को संबोधित करते हैं, लेकिन AI और डीपफेक तकनीक के लिए विशिष्ट प्रावधानों का अभाव है।

सरकारी पहल

- **आईटी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021:** इन कानूनों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डीपफेक सामग्री को तुरंत हटाना होगा, पालना न करने पर दंड का प्रावधान।

- **आईटी अधिनियम की धारा 66D:** संचार उपकरणों का उपयोग करके नकल करने पर कारावास और जुर्माना हो सकता है।
- **नियम 3(1)(B)(7) और नियम 3(2)(B):** ये नियम शिकायत के 24 घंटे के भीतर प्रतिरूपण सामग्री को हटाने का आदेश देते हैं।
- **तथ्य अन्वेषण इकाई:** आईटी नियम 2021 के तहत स्थापित, यह इकाई फर्जी खबरों के निर्माण और प्रसार को रोकती है और संदिग्ध जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

डीपफेक के दुरुपयोग पर नियंत्रण

- **कानूनी उपाय:** चुनावी हेरफेर के लिए डीपफेक सामग्री के निर्माण और उपयोग को संबोधित करने वाले सख्त कानून लागू करें।
- **चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश:** राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एआई एल्गोरिदम के उपयोग में पारदर्शिता की आवश्यकता है, जिसमें फंडिंग प्रकटीकरण और एल्गोरिदम पारदर्शिता शामिल है।
- **तकनीकी-आधारित समाधान:** वास्तविक समय में डीपफेक सामग्री का पता लगाने के लिए उन्नत एआई उपकरण विकसित करें।
- **जागरूकता और शिक्षा अभियान:** मतदाताओं को डीपफेक और चुनावों पर उनके प्रभाव के बारे में शिक्षित करें।
- **तथ्यों का व्यापक अन्वेषण:** फर्जी खबरों और डीपफेक से तुरंत निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल स्थापित करें।
- **सहयोगी प्रयास:** सरकारों, तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज को डीपफेक खतरों के लिए समन्वित प्रतिक्रियाएँ विकसित करनी चाहिए।
- **नैतिक एआई को बढ़ावा देना:** नैतिक सिद्धांतों के साथ एआई प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना, पूर्वाग्रह को कम करने, गोपनीयता की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना।

इन चुनौतियों का समाधान करके और मजबूत उपायों को लागू करके, डीपफेक के बढ़ते खतरे के बीच चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को संरक्षित किया जा सकता है।

5. महिला सशक्तीकरण: भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास का मार्ग

चूँकि भारत का लक्ष्य 2047 तक एक 'विकसित' राष्ट्र बनना है, इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत जरूरी है। अमर्त्य सेन की "लापता महिलाओं" की अवधारणा के अनुसार, केवल विकास ही लैंगिक असमानताओं को दूर नहीं कर सकता। महिलाओं के विभिन्न कल्याण मापदंडों के साथ, भारत को सामाजिक-आर्थिक परिणामों में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए प्रमुख नीतियाँ

अपनानी चाहिए।

महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए प्रमुख प्रावधान

संवैधानिक उपाय:

- **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
- **अनुच्छेद 15(3):** राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 16:** सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 39(डी):** पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की मांग करता है।
- **अनुच्छेद 42:** राज्य को मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

सरकारी पहल:

- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:** महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए किराया मुक्ति ऋण प्रदान करती है।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:** शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के कल्याण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **महिला ई-हाट:** महिला उद्यमियों का समर्थन करने वाला एक ऑनलाइन मंच।
- **महिला शक्ति केंद्र:** कौशल विकास और उद्यमिता के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रमों और संसाधनों की सुविधा प्रदान करता है।
- **कामकाजी महिला छात्रावास:** शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास का समर्थन करता है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना:** महिलाओं के नाम पर आवास सुनिश्चित करता है।
- **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017:** सवेतन मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया और क्रेच सुविधाओं (पालना घर) को अनिवार्य कर दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/समझौते:

- **CEDAW (1979):** महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान करता है।
- **बीजिंग घोषणा और कार्रवाई के लिए मंच (1995):** महिला सशक्तीकरण के लिए एजेंडा क्षेत्रों को रेखांकित करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र एसडीजी लक्ष्य 5:** 2030 तक लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना।

महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले प्रमुख कारक

- **सामाजिक मानदंड और पितृसत्तात्मक मानसिकता:** रूढ़िवादी मानदंड महिलाओं की गतिशीलता, शिक्षा और आर्थिक अवसरों को प्रतिबंधित करते हैं। लिंग-पक्षपाती लिंग चयन विषम लिंग अनुपात की ओर ले जाता है।
- **कम श्रम भागीदारी:** महिला श्रम शक्ति भागीदारी लगभग 37% है, जो वैश्विक औसत 47% से कम है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र में कई महिलाएँ कार्यरत हैं,** जिनमें वेतनभोगी कामों में उनका अनुपात कम है।
- **अवैतनिक देखभाल कार्य का अनुपातहीन हिस्सा:** महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अवैतनिक देखभाल कार्य पर लगभग तीन गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं।
- **लिंग वेतन अंतर:** सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वेतन अंतर मौजूद हैं। वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2023 में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है, जो आर्थिक भागीदारी में केवल 36.7% समानता प्राप्त करता है।
- **संपत्ति के स्वामित्व और वित्तीय समावेशन का अभाव:** केवल 20% महिलाओं के पास जमीन या संपत्ति है।
- **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 में** महिलाओं की तुलना में संपत्ति रखने वाले पुरुषों का प्रतिशत अधिक है।
- **हिंसा में वृद्धि:** घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न सहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उच्च प्रचलन।
- **सीमित शिक्षा:** महिला साक्षरता दर 71.5% है, जो पुरुष साक्षरता दर 84.7% से कम है। उच्च शिक्षा के स्तर पर नामांकन में लैंगिक समानता में गिरावट आई है।
- **सीमित राजनीतिक भागीदारी:** संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, लोकसभा में 14.4% और राज्यसभा में 13% है।

महिलाओं के बीच सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उपाय

- **महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाना:** महिलाओं की LFP दर को 50% तक बढ़ाने से GDP वृद्धि 8% तक बढ़ सकती है। श्रम-प्रधान क्षेत्रों में विनिर्माण क्षमता के विस्तार पर ध्यान दें।
- **कौशल तक पहुँच में सुधार:** महिलाओं के लिए प्रशिक्षण संस्थानों में वृद्धि करें।
- **करियर काउंसलिंग, जॉब प्लेसमेंट सेल और मेंटरशिप प्रोग्राम को बढ़ावा दें।**
- **शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की गतिशीलता को सक्षम बनाना:** महिलाओं की गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए लिंग के दृष्टिकोण से शहरों की योजना बनाएँ। उच्च गुणवत्ता वाले, सब्सिडी वाले शहरी देखभाल बुनियादी ढाँचे का विकास करें।
- **सहज तकनीकी उपलब्धता:** घरेलू गतिविधियों पर महिलाओं के समय के बोझ को कम करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए नकद छूट प्रदान करें।
- **स्वरोजगार मंचों को विकसित करना:** मांग में कौशल पर केंद्रित लचीले, स्वरोजगार मंचों का विकास किया जाना चाहिए।
- **महिलाओं के नेतृत्व वाली आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क:** महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को सीधे बड़े निगमों और सरकारी खरीद कार्यक्रमों से जोड़ें। फाल्गुनी नायर की नाइका जैसे उदाहरणों का अनुसरण करते हुए महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को प्रोत्साहित करें।
- **इन उपायों को लागू करके,** भारत लैंगिक समानता और सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है।

15

टर्म इन न्यूज़

बैंक रन

- बैंक रन एक स्थिति है जब किसी बैंक के बहुत से ग्राहक एक ही समय में अपनी जमा धनराशि का पूरा या एक बड़ा हिस्सा बैंक से निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि बैंक दिवालिया हो जाएगा। यह लोगों के स्वयं के पूर्वानुमान के कारण होती है चूंकि बैंक के पास सभी निकासी को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं हो सकती है, जिससे बैंक दिवालिया हो सकता है। पहले लोग इस स्थिति में नकदी निकालने के लिए व्यक्तिगत रूप से बैंक जाते थे लेकिन वर्तमान में वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से नकदी निकल सकते हैं।

सर्कुलर इकॉनमी

- सर्कुलर इकॉनमी वह है जहां उत्पादों को स्थायित्व, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए डिजाइन किया जाता है, यह संसाधनों के दीर्घकालिक और अनुकूलतम उपयोग को प्राथमिकता देती है। अर्थात् उत्पादों को इस प्रकार डिजाइन करना ताकि वे उच्च गुणवत्ता युक्त और टिकाऊ हों। व्यवसाय में उत्पादों को बेचने की बजाय किराए पर देने या नवीनीकरण जैसी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पुनर्चक्रण के तहत अपशिष्ट को उत्पाद में परिवर्तित किया जा सकता है। अंततः, सर्कुलर इकॉनमी ऐसी बंद लूप प्रणाली है जिसमें संसाधनों को नियमित रूप से पुनर्चक्रित किया जाता है, इससे पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है और अधिक टिकाऊ भविष्य को प्रोत्साहन मिलता है।

प्रिसिजन फार्मिंग

- प्रिसिजन फार्मिंग में फसल उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए GPS, सेंसर और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीक का उपयोग न्यूनतम इनपुट के साथ किया जाता है। यह किसानों को फसल की वृद्धि, मिट्टी की स्थिति और संसाधनों के उपयोग की सटीकता के साथ निगरानी और प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है। इस तकनीक में इनपुट, रिमोट सेंसिंग और स्वचालित मशीनरी शामिल है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए पैदावार और लाभ को अधिकतम करना है। यह जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि जैसी चुनौतियों का समाधान करता है। इससे कृषि उत्पादकता, स्थिरता और लचीलापन बढ़ता है। प्रिसिजन फार्मिंग कृषि के लिए एक आधुनिक, डेटा-संचालित दृष्टिकोण को चिह्नित करती है, जो पारंपरिक खेती

के तरीकों में क्रांति लाती है। यह कृषि के लिए अधिक कुशल और टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

शुंक्फ्लेशन

- शुंक्फ्लेशन कंपनियों द्वारा ग्राहकों के ध्यान में आए बिना कीमतें बढ़ाने की एक पद्धति है। इसके तहत किसी उत्पाद का आकार या मात्रा कम हो जाती है जबकि कीमत वही रहती है (या कभी-कभी बढ़ भी जाती है)। अर्थात् ग्राहक जो उत्पाद खरीद रहे हैं उसकी मात्रा की तुलना में ज्यादा भुगतान करते हैं। यह खाद्य और घरेलू सामानों में सामान्य घटना है, और जब तक ग्राहक उत्पादों को ध्यान से नहीं देखते हैं, तब तक इसका पता लगाना मुश्किल होता है।

J-1 वीजा

- J-1 वीजा, जिसे आमतौर पर एक्सचेंज विजिटर वीजा के रूप में जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर समृद्ध सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। सरकारी एजेंसियों, विश्वविद्यालयों और निजी संगठनों जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित, ये कार्यक्रम अकादमिक गतिविधियों में शामिल होने, शिक्षण के माध्यम से ज्ञान साझा करने, शोध प्रयासों का संचालन करने या विविध क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं। चाहे आप एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हों, एक समर्पित शोधकर्ता हों, एक जुनूनी कैम्प काउंसलर हों या एक प्रेरित प्रशिक्षु हों, आपके विशिष्ट एक्सचेंज प्रोग्राम के अनुरूप एक निर्दिष्ट J-1 वीजा श्रेणी है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रम पूरा होने के बाद J-1 वीजा धारकों पर आम तौर पर दो साल की घरेलू निवास आवश्यकता लागू की जाती है (कुछ मामलों में अपवाद उपलब्ध हैं)। यह आवश्यकता ज्ञान के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करती है और आपके गृह देश में लौटने पर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देती है।

डंपिंग

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग तब होती है जब कोई कंपनी या देश अपने घरेलू बाजार में बेची जाने वाली कीमत से काफी कम कीमत पर सामान निर्यात करता है। यह वास्तव में आयातक देश के बाजार को सस्ते सामानों से भर देता है, संभावित रूप से स्थानीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचाता है जो कृत्रिम रूप से

कम कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। हालांकि यह आयात करने वाले देश में उपभोक्ताओं को कम कीमतों के साथ लाभान्वित कर सकता है। डंपिंग से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं और नौकरी छूट सकती है तथा प्रभावित उद्योग के उत्पादन में कमी आ सकती है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के पास डंपिंग को नियंत्रित करने के लिए नियम हैं, जो देशों को अनुचित मूल्य लाभ की भरपाई करने और अपने घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की अनुमति देते हैं।

एंटी-डंपिंग शुल्क

- भारतीय बाजार में, एंटी-डंपिंग शुल्क अनुचित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। ये शुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाए जाते हैं जिन्हें डंप माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें उनके घरेलू बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर बेचा जाता है। ये सस्ते आयात उस क्षेत्र में भारतीय व्यवसायों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे कृत्रिम रूप से कम कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करते हैं। जबकि उपभोक्ता अस्थायी लाभ का आनंद ले सकते हैं, एंटी-डंपिंग शुल्क समान एवम प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए लगाए जाते हैं। भारतीय अधिकारी डंपिंग के दावों की जांच करते हैं और यदि साबित हो जाते हैं, तो इन शुल्कों को आयात मूल्य में जोड़ देते हैं, जिससे अनुचित लाभ बेअसर हो जाता है और इस प्रकार घरेलू उत्पादकों की रक्षा होती है।

गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाएँ

- गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाएँ प्रमुख बाजार-संचालित प्रणालियों के विपरीत हैं। यहां, सरकार संसाधनों के आवंटन और कीमतें निर्धारित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है, अक्सर राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के माध्यम से। यह दृष्टिकोण शुद्ध लाभ पर सामाजिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दे सकता है लेकिन दक्षता और नवाचार को भी सीमित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, देश अक्सर गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि निर्यात के वास्तविक मूल्य का आकलन करना और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है। इससे व्यापार विवाद और एंटी-डंपिंग शुल्क प्रतिबंध जैसे विवादों को बढ़ावा मिलता है।

आर्कटिक प्रवर्धन

- आर्कटिक प्रवर्धन उस घटना को दर्शाता है जिसमें आर्कटिक क्षेत्र में वैश्विक औसत से कहीं अधिक गति से तापमान में वृद्धि होती है, पिछले चार दशकों में तापमान दो से तीन गुना तेजी से बढ़ा है। यह

मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों के कारण होता है, जो वायुमंडल के तापमान में वृद्धि करते हैं, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव में बढ़ोतरी होती है। समुद्री बर्फ का पिघलना इस तीव्र गर्मी के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक है, क्योंकि यह पृथ्वी के एल्बेडो को कम करता है, जिससे बर्फ और अधिक पिघलती है और सूर्य के प्रकाश का अवशोषण बढ़ता है। आर्कटिक प्रवर्धन के परिणामों में बर्फ, ग्लेशियर और स्थायी तुषार भूमि का पिघलना, समुद्री बर्फ का नुकसान, पारिस्थितिकी तंत्र और स्वदेशी समुदायों की पारंपरिक आजीविका को बाधित करना शामिल है। इसके अलावा, ये परिवर्तन आर्कटिक से परे मौसम के पैटर्न, समुद्र के स्तर और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं, इस प्रकार जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन प्रयासों के व्यापक संदर्भ में आर्कटिक वार्मिंग को संबोधित करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

रिटर्निंग ऑफिसर

- एक रिटर्निंग ऑफिसर को एक विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों की निगरानी और प्रशासन के लिए नियुक्त किया जाता है, जो चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखते हुए मतदान, गिनती और अन्य संबंधित गतिविधियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। भारत में, चुनाव आयोग प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी के रूप में सरकार या स्थानीय प्राधिकार के एक अधिकारी को, लोकसभा चुनावों के लिए जिला मजिस्ट्रेट और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के रूप में नामित करता है। रिटर्निंग अधिकारी के पास मतपत्रों की वैधता तय करने और मतदान व मतगणना प्रक्रिया संचालित करने का वैधानिक अधिकार होता है। इन निर्णयों को चुनाव आयोग द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)

- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) भौतिक उपकरणों के एक विशाल नेटवर्क को संदर्भित करता है जो संसर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस हैं। ये 'स्मार्ट डिवाइस' एक दूसरे के साथ डेटा एकत्र और आदान-प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें कार्यों को स्वचालित करने और अपने परिवेश पर प्रतिक्रिया करने की अनुमति मिलती है। यह साधारण थर्मोस्टेट जो आपके घर के तापमान को समायोजित करता है से लेकर जटिल औद्योगिक मशीनरी जो अपने स्वयं के प्रदर्शन की निगरानी करता है, तक हो सकता है। अरबों डिवाइस पहले से ही जुड़े हुए हैं और और भी आने वाले हैं, IoT तेजी से हमारे रहने, काम करने और

हमारे आसपास की दुनिया के साथ संलग्न के तरीके को बदल रहा है।

जेनोटांसप्लांटेशन

- जेनोटांसप्लांटेशन मनुष्यों के इलाज के लिए जानवरों के अंगों, ऊतकों या कोशिकाओं का उपयोग करने का विचार है। इसे प्रत्यारोपण के लिए अंगों की आपूर्ति की गंभीर कमी के संभावित समाधान के रूप में देखा जाता है। सूअर अपने आकार की अनुकूलता और उपलब्धता के कारण विशेष रूप से आशाजनक स्रोत हैं। हालाँकि, बाधाएँ हैं। हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से अन्य जीवों के ऊतकों को अस्वीकार करता है, और वैज्ञानिक इस जोखिम को कम करने के लिए जानवरों को आनुवंशिक रूप से संशोधित करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जानवरों की बीमारियों का मनुष्यों में संचरण की संभावना एक बड़ी चिंता का विषय है। जेनोटांसप्लांटेशन एक प्रायोगिक क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन यह भविष्य में कई लोगों की जान बचाने का वादा करता है।

भारतीय अस्थिरता सूचकांक

- INDIA VIX, जिसे भारतीय अस्थिरता सूचकांक के रूप में भी जाना जाता है, अगले 30 कैलेंडर दिनों में शेयर बाजार (निफ्टी 50 इंडेक्स) की अस्थिरता की उम्मीद का एक माप है। यह अनिवार्य रूप से निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है कि स्टॉक की कीमतों में कितना उतार-चढ़ाव होने की उम्मीद है। एक उच्च INDIA VIX कीमत में उतार-चढ़ाव के पूर्वानुमान का सुझाव देता है, जबकि कम मूल्य शांत बाजारों की उम्मीदों को इंगित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि INDIA VIX गैर-दिशात्मक है, जिसका अर्थ है कि यह भविष्यवाणी नहीं करता है कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, केवल यह अनुमानित करता है कि कितना उतार-चढ़ाव अपेक्षित है। परंपरागत रूप से, 20 से नीचे का VIX मान अपेक्षाकृत स्थिर बाजार का संकेत देता है, जबकि 35 से ऊपर की रीडिंग बढ़ी हुई अस्थिरता का संकेत देती है।

व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)

- व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) देशों के बीच एक विस्तृत व्यापार समझौता है। इसमें सामान्य मुक्त व्यापार समझौते की तरह, आयात करों को कम करने के अलावा भी अन्य कई मुद्दों को शामिल किया जाता है। CEPA का लक्ष्य वस्तुओं पर टैरिफ को कम करने के साथ-साथ देशों के बीच सेवाओं और निवेश में व्यापार को सरल बनाकर अधिक व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाना है। इसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों पर समझौते, सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद प्रणाली और किसी भी व्यापार विवाद को निपटाने के

उपायों को शामिल किया जा सकता है। समग्र रूप से, CEPA का लक्ष्य भागीदार देशों के बीच व्यापार और निवेश प्रवाह को अधिक सुचारू बनाना है।

सिकआउट

- सिकआउट एक श्रमिक विरोध रणनीति है जहाँ कर्मचारियों का एक समूह सामूहिक रूप से बीमार होने का नाटक करता है, जिसका अर्थ है कि सभी एक ही समय में एक साथ। इस समन्वित अनुपस्थिति का उद्देश्य नियोक्ता के संचालन को बाधित करना और श्रमिकों की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करवाना है। यह औपचारिक हड़ताल का सहारा लिए बिना, एक प्रकार की दबाव रणनीति के रूप में कार्य करता है, जिसकी कड़ी कानूनी सीमाएँ हो सकती हैं। सिकआउट्स को अक्सर उन उद्योगों में नियोजित किया जाता है जहाँ कर्मचारियों की उपस्थिति दैनिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होती है जैसे एयरलाइंस, अस्पताल या सार्वजनिक परिवहन। कार्यस्थलों पर कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अवकाश एवम बीमारियाँ उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं और असुविधा का कारण बन सकती हैं, जिससे नियोक्ताओं को श्रमिकों की मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उदाहरण के लिए, मई 2024 में, भारत में एयर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू ने नए स्वामित्व के तहत इलाज के संबंध में अपनी चिंताओं का विरोध करने के लिए एक सिकआउट का इस्तेमाल किया।

अंतरिम जमानत

- अंतरिम जमानत, भारत की आपराधिक प्रक्रिया संहिता में एक प्रावधान है, जो गिरफ्तार व्यक्ति को अस्थायी राहत प्रदान करता है। यह एक अल्पकालिक रिहाई है जबकि नियमित या अग्रिम जमानत के लिए उनके आवेदन पर अदालत द्वारा विचार किया जा रहा है। यह उन स्थितियों में मददगार हो सकती है जहाँ आरोपी को तत्काल व्यक्तिगत जरूरतें हों, जैसे चिकित्सा आपात स्थिति या पारिवारिक संकट। नियमित जमानत के विपरीत, अंतरिम जमानत सीमित अवधि के लिए होती है और अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होती है। यह अनिवार्य रूप से मुख्य जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय आने तक अनावश्यक हिरासत को रोकने का एक तरीका है।

पॉलीमरिक नोड्यूल्स

- पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, या मैंगनीज नोड्यूल्स, गहरे समुद्र तल में बिखरे हुए आलू जैसे खनिज भंडार हैं। लाखों वर्षों में, वे परत दर परत बढ़ते हैं, निकल, तांबा और कोबाल्ट जैसी मूल्यवान धातुओं के साथ-साथ लोहा और मैंगनीज जमा करते हैं। 4 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर पाए जाने वाले, ये पिंड गहरे

मैदानों के विशाल क्षेत्रों को कालीन बनाते हैं। उनकी समृद्ध धातु सामग्री उन्हें आधुनिक उद्योगों के लिए संभावित रूप से मूल्यवान बनाती है, लेकिन गहरे समुद्र में खनन की कठिनाई और पर्यावरणीय प्रभाव उनके स्थायी निष्कर्षण के बारे में चिंता पैदा करते हैं।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG)

- पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) एक ऐसा ढांचा है जो किसी कंपनी के मुनाफे से परे उसके प्रभाव पर विचार करता है। यह देखता है कि वे पर्यावरण (प्रदूषण, उत्सर्जन) का प्रबंधन कैसे करते हैं, अपने कर्मचारियों और समुदायों (श्रम प्रथाओं, सामाजिक जिम्मेदारी) के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और खुद को कैसे नियंत्रित करते हैं (नैतिकता, पारदर्शिता)। दीर्घकालिक, संधारणीय विकास चाहने वाले निवेशकों के लिए यह तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। उपभोक्ता भी कंपनी की ESG प्रथाओं के आधार पर चुनाव कर रहे हैं, और कंपनियों को उनके पर्यावरणीय और सामाजिक पदचिह्न के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए नियम विकसित हो रहे हैं। ESG सिद्धांतों को अपनाकर, कंपनियाँ न केवल निवेश और ग्राहकों को आकर्षित कर सकती हैं, बल्कि भविष्य के लिए अधिक जिम्मेदार और लचीला व्यवसाय भी बना सकती हैं।

टर्बुलेंस

- टर्बुलेंस उड़ान के दौरान आने वाली हवा की विकराल एवम असामान्य गति है। यह अनियमित वायुमंडलीय स्थितियों के कारण होता है, जैसे तेज हवाएं वायुराशियों को अलग-अलग दिशाओं में गतिमान करती हैं या तापमान में भिन्नता के कारण उच्च या निम्न वायुदाब के क्षेत्र बनते हैं। जब कोई विमान इन असमान वायुप्रवाहों के मध्य से गुजरता है, तो वह असंतुलित हो जाता है, जिससे धक्कों और झटकों की अनुभूति होती है। टर्बुलेंस अत्यधिक भयावह हो सकता है, आधुनिक हवाई जहाज इसे सुरक्षित रूप से संभालने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पायलटों को टर्बुलेंस से निपटने और जब भी संभव हो यात्री असुविधा को कम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (PLI)

- प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (PLI) एक सरकारी योजना है जो विशिष्ट वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में वृद्धि हासिल करने के लिए कंपनियों को वित्तीय पुरस्कार प्रदान करती है। यह गाजर एवम छड़ी सिद्धांत के समान है। कंपनियों को एक निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित उत्पादन लक्ष्य से अधिक होने पर नकद प्रोत्साहन मिलता है। इस योजना का लक्ष्य घरेलू

विनिर्माण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और सौर पैनल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाले सामानों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।

विरोध की दीवार

- G7 बैठक में 'विरोध की दीवार' शब्द का इस्तेमाल चीन की राज्य-नियंत्रित औद्योगिक नीतियों के खिलाफ बाजार-संचालित देशों द्वारा गठित संयुक्त मोर्चे का वर्णन करने के लिए किया गया था, जहां सरकार उद्योगों को भारी रूप से प्रभावित करती है और उन्हें सब्सिडी देती है। ये नीतियां वैश्विक व्यापार में अनुचित लाभ पैदा करती हैं। चीन में अत्यधिक उत्पादन और प्रतिस्पर्धा की कमी से चिंतित अमेरिका चाहता है कि अन्य G7 सदस्य एक एकीकृत संदेश प्रस्तुत करें कि इस तरह की प्रथाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए टिकाऊ नहीं हैं। 'विरोध की दीवार' G7 देशों की निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने वाले समाधान खोजने की साझा इच्छा को दर्शाती है।

एआई एजेंट

- एआई एजेंट, जिन्हें बुद्धिमान एजेंट के रूप में भी जाना जाता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं जो विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं कार्य कर सकते हैं। एक डिजिटल या भौतिक इकाई की कल्पना करें जो अपने परिवेश को समझ सकती है, निर्णय ले सकती है और कार्रवाई कर सकती है। ये एजेंट जानकारी इकट्ठा करने के लिए सेंसर का उपयोग करते हैं (जैसे कैमरा या माइक्रोफोन) और इसका विश्लेषण करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। कुछ लोग समय के साथ सीख भी सकते हैं और सुधार भी कर सकते हैं। हम उन्हें उन रोबोटों में देखते हैं जो फैक्ट्रियों में नेविगेट करते हैं या चौटबॉट्स में जो आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जैसे-जैसे एआई का विकास जारी है, ये एजेंट ग्राहक सेवा से लेकर वित्त तक विभिन्न क्षेत्रों में और भी बड़ी भूमिका निभाने का दावा करते हैं।

बौद्धिक संपदा (IP) अधिकार

- बौद्धिक संपदा (IP) अधिकार दिमाग की रचनाओं को दी गई कानूनी सुरक्षा हैं। इसमें आविष्कार, साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक (जैसे ट्रेडमार्क) शामिल हैं। इसे विचारों के स्वामित्व के रूप में जाना जाता है। आईपी अधिकार रचनाकारों को इस बात पर विशेष नियंत्रण देते हैं कि एक निश्चित अवधि के लिए उनकी रचनाओं का उपयोग कैसे किया जाता है, जिससे उन्हें उनके काम से लाभ मिलता है। यह बाजार में

निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है।

क्यूबसैट

- क्यूबसैट एक रूबिक क्यूब जितना छोटा मानकीकृत आकार में निर्मित उपग्रह है। ये मॉड्यूलर अधभूत एकल इकाइयाँ हो सकते हैं या अधिक क्षमता के लिए एक साथ रखे जा सकते हैं। उनकी कम लागत और संयोजन में आसानी के कारण, उनका उपयोग आमतौर पर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप द्वारा वैज्ञानिक प्रयोगों, पृथ्वी अवलोकन और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों के लिए किया जाता है। क्यूबसैट का उपयोग रिमोट सेंसिंग, संचार, अंतरिक्ष मौसम की निगरानी, अंतरग्रहीय मिशन और कक्षा में नई प्रौद्योगिकियों के परीक्षण के लिए भी किया जाता है।

डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक

- फरवरी 2024 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, एक अविश्वास कानून है जिसे इसके विशाल डिजिटल बाजार में बड़ी तकनीकी कंपनियों के प्रभुत्व को रोकने के लिए बनाया गया है। यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट्स एक्ट से प्रेरित, यह बिल 30 बिलियन डॉलर से अधिक वैश्विक राजस्व वाली बड़ी डिजिटल फर्मों और कम से कम 10 मिलियन भारतीय उपयोगकर्ताओं को लक्षित करता है, जिसमें Google, Amazon और Apple जैसी कंपनियाँ शामिल हैं। बिल में तीन प्रमुख उपाय प्रस्तावित हैं: इन कंपनियों को उपयोगकर्ताओं के गैर-सार्वजनिक डेटा का शोषण करने से रोकना, उन्हें प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपनी सेवाओं को तरजीह देने से रोकना और ओपन ऐप

स्टोर को सक्षम करना जहाँ उपयोगकर्ता स्वतंत्र रूप से तृतीय-पक्ष ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। टेक उद्योग लॉबी समूहों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है क्योंकि इससे उपयोगकर्ता की लागत बढ़ सकती है। इस बिल का भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

बिग टेक

- बिग टेक का मतलब कुछ बेहद सफल प्रौद्योगिकी कंपनियों से है जो अपने-अपने क्षेत्रों में हावी हैं। ये दिग्गज, जिनमें आमतौर पर अल्फाबेट (गूगल), अमेज़न, ऐप्पल, मेटा (फेसबुक) और माइक्रोसॉफ्ट शामिल हैं, अपने आकार, धन और ऑनलाइन विज्ञापन और सोशल मीडिया से लेकर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर तक हर चीज पर प्रभाव के कारण अपार शक्ति रखते हैं। उन्हें अक्सर उनके नवाचार के लिए सराहा जाता है, लेकिन उनके बाजार प्रभुत्व और संभावित गोपनीयता चिंताओं के लिए भी जांच का सामना करना पड़ता है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ ऐसी कंपनियाँ हैं जो उधारकर्ताओं, आमतौर पर सरकारों और व्यवसायों की साख का आकलन करती हैं। ये एजेंसियाँ उधारकर्ता के वित्तीय स्वास्थ्य का विश्लेषण करती हैं और क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती हैं, जो एक अक्षर ग्रेड है जो उधारकर्ता द्वारा अपना ऋण चुकाने की संभावना को इंगित करता है। निवेशक किसी निवेश के जोखिम को मापने के लिए इन क्रेडिट रेटिंग का उपयोग करते हैं, उच्च रेटिंग डिफॉल्ट के कम जोखिम का संकेत देती है। क्रेडिट रेटिंग उद्योग में तीन प्रमुख खिलाड़ियों का वर्चस्व है: मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एसएंडपी), और फिच रेटिंग्स, जो सामूहिक रूप से लगभग 95% बाजार को नियंत्रित करते हैं।

मॉडल प्रश्न

- राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 - सदाचार समिति के अध्यक्ष पद पर श्री हरीश चौधरी को नियुक्त किया गया है।
 - महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष पद पर श्रीमती अनिता भदेल को नियुक्त किया गया है।
 - वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी है।

सही विकल्प का चयन कीजिए-

(A) 1 व 2 (B) 2 व 3
(C) 1, 2 और 3 (D) 1 व 3
- हाल ही में चर्चा में रही ताकली बाँध मध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है?

(A) कोटा (B) सीकर
(C) भरतपुर (D) जालौर
- राजस्थान में वन विभाग द्वारा कितने स्थानों को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा?

(A) 75 (B) 110
(C) 115 (D) 120
- डॉ. कमला बेनीवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 - यह राजस्थान की पहली महिला उपमुख्यमंत्री और पहली महिला मंत्री रह चुकी है।
 - यह बिहार, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यपाल रह चुकी है।

सही विकल्प का चयन कीजिए-

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 न ही 2
- हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु किस जिले में 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' चलाया गया है?

(A) जयपुर (B) बाड़मेर
(C) जैसलमेर (D) बीकानेर
- राजस्थान में किस स्थान पर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी?

(A) अजमेर (B) जोधपुर
(C) जयपुर (D) उदयपुर
- राजस्थान में 'इंटर-ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) 2.0' के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया?

(A) मुख्यमंत्री (B) मुख्य सचिव
(C) पुलिस महानिदेशक (D) शासन सचिव
- राजस्थान में मुंबई और सूरत जेम बोर्स की तर्ज पर 'जेम्स एंड ज्वैलरी बोर्स' कहाँ स्थापित किया जाएगा?

(A) जोधपुर (B) उदयपुर
(C) अलवर (D) जयपुर
- वार्षिक वन्यजीव वाटरहोल सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 - इसके तहत राजस्थान में गोडावण पक्षी की गणना की गई।
 - राजस्थान में वर्तमान में गोडावण पक्षियों की संख्या 180 है।
 - गोडावण का वैज्ञानिक नाम 'अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स' है।

सही विकल्प का चयन कीजिए-

(A) 1 व 2 (B) 2 व 3
(C) 1, 2 व 3 (D) 1 व 3
- राजस्थान में बाघों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 - राजस्थान में वर्तमान में कुल बाघों की संख्या 134 हो गई है।
 - राजस्थान में सर्वाधिक बाघ रणथंभौर टाइगर रिजर्व में है।
 - राजस्थान में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व है।

सही विकल्प का चयन कीजिए-

(A) 1 व 2 (B) 2 व 3
(C) 1, 2 व 3 (D) 1 व 3
- राजस्थान के किस जिले में ढाई हजार वर्ष पुराना यज्ञ कुंड और अश्विनी कुमारों की प्रतिमा प्राप्त हुई है?

(A) बूंदी (B) हनुमानगढ़
(C) बाड़मेर (D) डीग
- राजस्थान का सबसे लंबा रोप-वे किस जिले में बनाया जाएगा?

(A) कोटा (B) अजमेर
(C) उदयपुर (D) जयपुर
- हाल ही में राजस्थान में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है?

(A) जोधपुर (B) बाड़मेर
(C) पाली (D) अजमेर
- हाल ही में राजस्थान से किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है?
 - चंद्रपाल सिंह
 - शैतान सिंह
 - हरिकेश मीना

- सही विकल्प का चयन कीजिए-
- (A) 1 व 2 (B) 1 व 3
(C) 1, 2 और 3 (D) 2 व 3
15. राजस्थान सरकार द्वारा 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण हेतु 4 करोड़ पौधों का वितरण किस योजना के तहत किया जाएगा?
- (A) घर-घर औषधि योजना
(B) जनता वन योजना
(C) एकीकृत वनरोपण और पर्यावरण-विकास परियोजना
(D) टोफर (TOFER) योजना
16. राजस्थान में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कौनसा अभियान चलाया जा रहा है?
- (A) शुद्ध के लिए युद्ध अभियान
(B) शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान
(C) मिलावट पर प्रहार अभियान
(D) शुद्ध आहार, स्वस्थ राजस्थान अभियान
17. राजस्थान के गोपालन विभाग द्वारा पशु-पक्षियों को लू और ताप घात से बचाने हेतु कौनसा अभियान शुरू किया गया है?
- (A) धूप-रक्षण 24 अभियान
(B) ताप-रक्षक 24 अभियान
(C) सन-रक्षण 24 अभियान
(D) सूर्य-रक्षा 24 अभियान
18. रावतभाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. यहाँ राजस्थान का दूसरा भारी जल संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
 2. यहाँ रूस के सहयोग से भारत का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया था।
 3. यहाँ चम्बल नदी पर जवाहर सागर बांध स्थित है।
- सही विकल्प का चयन कीजिए-
- (A) 1 व 2 (B) केवल 1
(C) केवल 2 (D) 2 व 3
19. हाल ही में राजस्थान में आत्महत्या के मामले रोकने हेतु किस जिला पुलिस प्रशासन ने मेटा कंपनी के साथ समझौता किया है?
- (A) जयपुर (B) जोधपुर
(C) सीकर (D) कोटा
20. भारत में पहली बार किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया गया है?
- (A) नेशनल पीपुल्स पार्टी
(B) बहुजन समाज पार्टी
(C) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(D) आम आदमी पार्टी
21. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. चीन वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है।
 2. भारत का चीन से निर्यात के मुकाबले आयात में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है।
- सही विकल्प का चयन कीजिए-
- (A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 न ही 2
22. वर्ष 2023 में भारत का रेमिटेंस (विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा) 125 अरब डॉलर था। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है?
- (A) 1.4% (B) 3.4%
(C) 2.7% (D) 1.9%
23. चाबहार पोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारत ने इराक से इस बंदरगाह के 10 वर्ष की अवधि तक संचालन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
 2. यह बंदरगाह अदन की खाड़ी में स्थित है तथा यह लाल सागर के रास्ते खाड़ी देशों और यूरोपीय देशों को भारत से जोड़ेगा।
- सही विकल्प का चयन कीजिए-
- (A) केवल 2
(B) केवल 1
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2
24. अन्तरराष्ट्रीय सौर गठबन्धन (ISA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. हाल ही में स्पेन इस गठबंधन का 99वाँ सदस्य बना है।
 2. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- सही विकल्प का चयन कीजिए-
- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2
25. हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी-रेडिशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसका क्या नाम है?
- (A) ब्रह्मोस (B) मैत्री II
(C) रुद्रम II (D) निर्भय II
26. अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर (SOrTeD)-01 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इसे अंतरिक्ष स्टार्ट-अप स्काईरुट एयरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया।
 2. यह भारत का पहला अर्द्ध-क्रायोजेनिक इंजन-संचालित रॉकेट लॉन्च है और दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D-प्रिंटेड इंजन से लैस है।

3. इसे अग्निकुल कॉसमॉस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित भारत के पहले निजी लॉन्चपैड 'धनुष' से लॉन्च किया गया।
सही विकल्प का चयन कीजिए-
(A) 1 व 2 (B) 2 व 3
(C) 1, 2 व 3 (D) 1 व 3
27. हाल ही में किस देश द्वारा 'लॉन्ग मार्च-5 Y8 रॉकेट' द्वारा चंद्रमा के सुदूर भाग से नमूने एकत्र करने हेतु रोबोटिक अंतरिक्ष मिशन 'चांग'ई-6' लॉन्च किया गया है?
(A) जापान (B) दक्षिण कोरिया
(C) चीन (D) यूनाइटेड किंगडम
28. हाल ही में भारतीय वायु सेना द्वारा 'स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल' को जमीन पर उतारने का सफल परीक्षण किया गया, इसका क्या नाम है?
(A) अर्जुन (B) अजेय
(C) शौर्य (D) भीष्म
29. 'FLOAT प्रोजेक्ट' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इसका पूरा नाम 'Forecast Lunar on a Track' है।
2. इसके तहत अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु 'रोबोटिक परिवहन प्रणाली' विकसित की जाएगी।
सही विकल्प का चयन कीजिए-
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 न ही 2
30. नीरज चोपड़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज ने भुवनेश्वर (ओड़िशा) में आयोजित फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता।
2. नीरज ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है।
सही विकल्प का चयन कीजिए-
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 न ही 2
31. हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक जीता?
(A) डोला बनर्जी (B) ज्योति सुरेखा वेनम
(C) दीपिका कुमारी (D) मुस्कान किरार
32. हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में भारत की किस खिलाड़ी ने कपाउंड महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता?
(A) दीपिका कुमारी (B) ज्योति सुरेखा वेनम
(C) कोमालिका बारी (D) अंकिता भकत
33. हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने हैरी शल्टिंग गोम्स के 100 मी. बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता?
(A) ज्योति याराजी (B) दुती चंद
(C) हिमा दास (D) भावना जाट
34. सुनील छेत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. यह फुटबॉल में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले विश्व के पाँचवे खिलाड़ी है।
2. यह 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न' पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय फुटबॉलर है।
सही विकल्प का चयन कीजिए-
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 न ही 2
35. हाल ही में एशियाई जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है?
(A) प्रणति नायक (B) अरुणा रेड्डी
(C) दीपा कर्माकर (D) दीपिका कुमारी
36. पैरा एथलेटिक्स विश्व चैम्पियनशिप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इसका आयोजन कोबे (जापान) में किया गया।
2. इसमें भारत ने 6 स्वर्ण, 5 रजत, 6 कांस्य पदकों सहित कुल 17 पदक जीते।
3. भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
सही विकल्प का चयन कीजिए-
(A) 1 व 2 (B) 1 व 3
(C) 1, 2 और 3 (D) 2 व 3
37. सचिन सजेंराव खिलारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. यह भारत के भाला फेंक (Javelin Throw) स्पर्धा के पैरा खिलाड़ी है।
2. सचिन ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024 में F46 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
3. सचिन 2023 में पेरिस में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था।
सही विकल्प का चयन कीजिए-

- (A) 1 व 2 (B) 1 व 3
(C) 1, 2 और 3 (D) 2 व 3
38. सात्विकसाईंराज रंकीरेड्डी और चिराग शेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इस जोड़ी ने थाईलैंड ओपन सुपर 500 पुरुष युगल का खिताब जीता।
 2. इन्होंने थाईलैंड ओपन का खिताब पहली बार जीता है।
 3. यह जोड़ी वर्तमान में BWF विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर है।
- सही विकल्प का चयन कीजिए-
- (A) केवल 3
(B) केवल 2
(C) 1, 2 और 3
(D) 1 व 3
39. येचियोन (दक्षिण कोरिया) में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज-2 में भारतीय महिला कपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता, इस टीम में निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी शामिल नहीं है?
- (A) ज्योति सुरेखा वेन्म
(B) परनीत कौर
(C) अदिति स्वामी
(D) अदिति अशोक
40. भारत के किस पर्यावरणविद को 'ग्रीन नोबेल' कहे जाने वाले 'गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024' हेतु चुना गया है?
- (A) मेधा पाटकर
(B) सदगुरु
(C) सुनीता नारायण
(D) आलोक शुक्ला
41. हाल ही में वर्ष 2024 के लिए 'व्हिटली गोल्ड अवार्ड' से किसे सम्मानित किया गया?
- (A) डॉ. पूर्णिमा देवी बर्मन
(B) प्रभा वर्मा
(C) गुलजार
(D) रामभद्राचार्य
42. 'कान्स फिल्म फेस्टिवल - 2024' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. अनुसूया सेनगुप्ता 'अन सर्टेन रिगार्ड' श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं।
 2. भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया ने फिल्म 'ऑल वी इमेजिन ऐज लाइट' के लिए 'पाल्म डी ओर' अवॉर्ड जीता है।
- सही विकल्प का चयन कीजिए-
- (A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 न ही 2
43. मेजर राधिका सेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इन्हें '2023 के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवॉर्ड' से सम्मानित किया जाएगा।
 2. मेजर राधिका यह अवॉर्ड पाने वाली पहली भारतीय शांति रक्षक हैं।
- सही विकल्प का चयन कीजिए-
- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2
44. पुलित्जर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. यह पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है।
 2. 'द वाशिंगटन पोस्ट' समाचार पत्र के डेविड ई. हॉफमैन को 'संपादकीय लेखन' श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- सही विकल्प का चयन कीजिए-
- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 न ही 2
45. हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं?
- (A) विवेक राम चौधरी
(B) अनिल चौहान
(C) दिनेश कुमार त्रिपाठी
(D) आर. हरि कुमार
46. लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. पिनाकी चंद्रा घोष वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष हैं।
 2. हाल ही में प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल सचिव नियुक्त किया गया है।
 3. जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और सुशील चंद्रा लोकपाल के सदस्य हैं।
- सही विकल्प का चयन कीजिए-
- (A) 1 व 2 (B) 1 व 3
(C) 1, 2 व 3 (D) 2 व 3
47. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इदाशिशा नोंगरांग मेघालय की पुलिस महानिदेशक बनी है।
 2. यह भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक है।
- सही विकल्प का चयन कीजिए-
- (A) केवल 2 (B) केवल 1
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 न ही 2

48. हाल ही में जॉन स्वाइनी ने किस देश के पहले मंत्री (First Minister) के रूप में शपथ ली है?
(A) स्कॉटलैंड (B) फिनलैंड
(C) आयरलैंड (D) स्विट्जरलैंड
49. भारत की पहली और एकमात्र महिला वनकर्मि जो 'मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट' बनी है?
(A) प्रेम कँवर (B) नीरू यादव
(C) माया टंडन (D) सलीमा टेटे
50. हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं?
(A) लाई चिंग-ते (B) मोहम्मद मोखबर
(C) जॉन स्वाइनी (D) टू लैम

Answer Key (May 2024)

1.	D	11.	D	21.	A	31.	C	41.	A
2.	A	12.	D	22.	B	32.	B	42.	A
3.	B	13.	C	23.	D	33.	A	43.	A
4.	A	14.	B	24.	A	34.	B	44.	C
5.	A	15.	D	25.	C	35.	C	45.	C
6.	C	16.	B	26.	B	36.	A	46.	D
7.	B	17.	C	27.	C	37.	D	47.	B
8.	D	18.	B	28.	D	38.	D	48.	A
9.	D	19.	D	29.	B	39.	D	49.	A
10.	A	20.	D	30.	C	40.	D	50.	D